R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 20 । अंक : 12

16 से 31 मार्च 2022

पृष्ठ : 48

मूल्य : 25 रु.

मोदी अभी भी असरदार ब्रांड!

4 राज्य जीतकर...
भाजपा की 2024 की राह आसान

कांग्रेस का विकल्प होगी
केजरीवाल की आम आदमी पार्टी...?

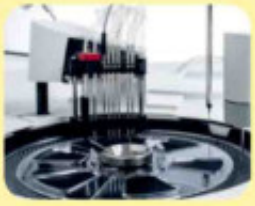

ANU SALES CORPORATION
R1+S Cycle 17
R1+S Cycle 17
R2 Cycle 1
R2 Cycle 1
R1+S Cycle 18
R1+S Cycle 18
R2 Cycle 2
When time matters,
Real 200 t/h throughput
Even with double reagent reactions, the analyzer keeps its speed. Up to 4 volumes can be handled in every cycle.
1 2 3 • 17 18 19 20 • 33 34 35 36 37 • 45 46
R1+S L1 R2 L2 WS1 WS2
Dispensation
Aspiration
We Deal in Pathology & Medical Equipment
BA200
BioSystems
The Highest Flexibility
Add : Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530
Email : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

राजपाट

9 | सस्ती हुई शराब...पर बेचने वाले नहीं तैयार

पंकज उधास की यह गजल तो आपने सुनी ही होगी कि महंगी हुई शराब, थोड़ी-थोड़ी पिया करो। लेकिन इसके उलट मप्र में सरकार ने शराब सस्ती कर दी है और पीने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है, लेकिन शराब बेचने के लिए...

राजपथ

10-11 | कागजी साबित हुआ बजट सत्र

मप्र विधानसभा का 13 दिवसीय बजट सत्र के 7 दिनों में सदन के अंदर केवल कागजी घोड़े दौड़ाए गए हैं। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण, बजट का प्रस्तुतिकरण, विधायक निधि में बढ़ोत्तरी के अलावा और कोई ऐसा काम...

मप्र कांग्रेस

14 | एक आनार कई बीमार

20 अगस्त तक कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा के साथ इस पद के लिए जद्दोजहद शुरू हो गई है। मौजूदा अध्यक्ष कमलनाथ की कोशिश है कि वे 2023 के विधानसभा चुनाव तक पद पर काबिज रहें। इसके लिए उन्हें पार्टी की कार्यवाहक...

तैयारी

15 | 2024 में चलेगी मेट्रो

राजधानी में मेट्रो परियोजना का काम वर्ष 2018 में शुरू किया गया है। एम्स से सुभाष नगर तक पहली लाइन के लिए 80 फीसदी हिस्से में पिलर खड़े कर उन पर गार्डर लांच किए जा चुके हैं। इसके बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि अब तक इस प्रोजेक्ट का चार फीसदी काम ही हो पाया है।

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

उप्र सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम से एक बार फिर से इस बात पर मुहर लग गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी देश की राजनीति में सबसे असरदार ब्रांड हैं। इस ब्रांड के आधार पर भाजपा ने 4 राज्यों को जीतकर 2024 की राह आसान कर ली है। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, आर्थिक बदहाली के इस दौर में माना जा रहा था कि भाजपा बड़े नुकसान में रहेगी, लेकिन ब्रांड मोदी के असर के सामने विपक्ष के सारे हथियार पस्त हो गए।

16-17

35

44

45

राजनीति

30-31 | राहुल ताजपोशी को तैयार!

राहुल गांधी ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। कांग्रेस को वो पांडव मानते हैं क्योंकि भाजपा को वो कौरवों की सेना समझते हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गुजरात में उनके गढ़ में घेरने का एक्शन प्लान भी तैयार कर चुके हैं। हालांकि, राहुल गांधी का...

महाराष्ट्र

35 | दक्षिण के सहारे तीसरा मोर्चा

करीब ढाई महीने बाद मुंबई में शरद पवार एक बार फिर से तीसरे मोर्चे के लिए अपना आशीर्वाद देते नजर आए। लेकिन 20 फरवरी को हुई बैठक में इस बार एनसीपी प्रमुख शरद पवार का समर्थन लेने वाला किरदार बदला हुआ था। इस बार शरद पवार के साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस...

बिहार

38 | लालू की सजा पर सियासत

चारा घोटाला राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद का पीछा छोड़ता नहीं लग रहा है। अब झारखंड में अंतिम (पांचवें) मामले में डोरंडा कोषागार से 139.50 करोड़ रुपए निकासी के सिलसिले में 5 साल जेल...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

इस बार किसानों की बल्ले-बल्ले

देश में खेती-किसानी पर किसी कवि ने लिखा है...

मैं किसान हूं मुझे भरोसा है अपने जूनून पर,
निगाहें लगी हुई हैं आकाश के मानसून पर।

लेकिन इस बार प्रकृति किसानों पर पूरी तरह मेहरबान रही है। मप्र में हर साल ओला-पानी से किसानों की फसल बर्बाद होती है, लेकिन इस बार प्रकृति का ऐसा साथ मिला है कि प्रदेश में गेहूं की बंपर पैदावार हुई है। यही नहीं इस बार किसानों को गेहूं के अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। वैसे तो प्रदेश में 25 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी होना है, लेकिन कृषि उपज मंडियों में मिल रहे अच्छे भाव के चलते किसानों की रुचि इस बार समर्थन मूल्य की जगह सीधे मंडी में ही अनाज बेचने में दिख रही है। जिसका असर अभी से मंडियों में दिखने लगा है। समर्थन मूल्य पर बिक्री से पहले ही मंडियों में किसानों के ट्रेक्टर उमड़ पड़े हैं। दरअसल, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनियाभर में चिंता का माहौल है लेकिन मप्र के किसानों को इस युद्ध का लाभ मिलता दिख रहा है। दरअसल रूस-यूक्रेन में युद्ध के चलते वहां से गेहूं का निर्यात नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते भारत के गेहूं की मांग बढ़ी है। इसका फायदा देश के किसानों को मिल रहा है। मप्र के किसान भी खुश हैं क्योंकि खुले बाजार में गेहूं 500 रुपए तक ऊंचा बिक रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में गेहूं के दाम लगभग 3000 रुपए क्विंटल तक जा सकते हैं। मप्र में गेहूं का सरकारी पंजीयन शुरू हो चुका है। इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2050 तक है लेकिन खुले बाजार में यह 200-2500 रुपए क्विंटल तक बिक रहा है। हालांकि अभी सरकारी गेहूं की खरीदी शुरू नहीं हुई है लेकिन किसानों को इस बार खुले बाजार में ही अच्छी कीमत मिल रही है, जिससे किसान खुश हैं। इस बार मंडी में गेहूं की आवक फरवरी से ही शुरू हो गई है और मार्च तक गेहूं की आवक ने रिकॉर्ड बना लिया है। समर्थन मूल्य अधिक मिलने से मंडी में वाहनों की कतार लग रही है। बता दें कि रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते अभी तक भारत से निर्यात होने वाले गेहूं का आंकड़ा मौजूदा वित्तीय वर्ष में फरवरी अंत तक ही करीब 7 मिलियन टन हो चुका है। उल्लेखनीय है कि रूस और यूक्रेन में बड़े पैमाने पर अनाज का उत्पादन किया जाता है। ये दोनों देश पूरी दुनिया के कुल गेहूं निर्यात का एक तिहाई हिस्सा निर्यात करते हैं। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश है। यही वजह है कि रूस-यूक्रेन के युद्ध के चलते भारत का अनाज निर्यात बढ़ा है। आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में 111.32 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होगा, जो कि पिछले साल के 109 मिलियन टन से ज्यादा है। मप्र पिछले कुछ सालों से गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना हुआ है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक गेहूं की बिक्री होती है। इसलिए इस बार युद्ध के कारण गेहूं के दाम में जो बढ़ोत्तरी हुई है, उसका फायदा मप्र के किसान खूब उठा रहे हैं। इससे किसानों की बल्ले-बल्ले हो गई है। उधर, मप्र सरकार ने भी इस बार भी किसानों का एक-एक दाना खरीदने का ऐलान किया है। इससे सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुना करने का जो प्लान तैयार किया है, उसको बल मिलेगा। गौरतलब है कि मप्र को सबसे अधिक अनाज उत्पादन के मामले में अभी तक 7 कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुके हैं। संभावना जताई जा रही है कि इस बार भी मप्र इस अवार्ड का सबसे प्रबल दावेदार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार किसानों का घर गेहूं से भरा पड़ा है।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 20, अंक 12, पृष्ठ-48, 16 से 31 मार्च, 2022

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी
फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,
फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर,
भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर,
मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास
मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र-संपादक के नाम

akshnews.com

एक्टिव मोड में भाजपा

मप्र में इन दिनों सत्ता में होने के बाद भी भाजपा का संगठन पूरी तरह से एक्टिव मोड में बना हुआ है। आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। भाजपा 2018 के विधानसभा चुनावों की तरह कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए।

● **प्रीति शर्मा,** इंदौर (म.प्र.)

कांग्रेस में गुटबाजी शुरू

मप्र कांग्रेस कमेटी के मुखिया कमलनाथ को चुनौती देने के लिए नेताओं की लामबंदी शुरू हो गई है। प्रदेश में कांग्रेस के कई गुट हैं। आने वाले चुनावों को देखते हुए हर नेता अपने गुट का प्रदेश अध्यक्ष देखना चाहता है। कई नेता दिल्ली दरबार में भी अर्जी लगा चुके हैं।

● **शिवानी सोनी,** राजगढ़ (म.प्र.)

बढ़ता जा रहा अवैध खनन

प्रदेश के कई जिलों में अवैध रेत का खनन किया जा रहा है। प्रशासन की सख्ती के बावजूद रेत माफिया निडर होकर अवैध खनन कर रहे हैं। प्रशासन रेत माफिया पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, बावजूद इसके रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन नहीं रुक रहा है।

● **ऋषि नागफंसे,** जबलपुर (म.प्र.)

आम लोगों को भुगतने होंगे युद्ध के दुष्परिणाम

हमने दो विश्व युद्धों का जख्म झेला है और अनुभव यही है कि युद्ध किसी भी समस्या का न तो विकल्प हो सकता है और न ही समाधान। युद्ध का खामियाजा वहां के आम लोगों और सैनिकों के परिवारों को सालों साल भुगतना पड़ता है। जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद और विश्व के बड़े हुक्मरान इस समस्या का समाधान निकालें। रूस जानता है कि इस कदम के बाद यूरोपीय देश और पश्चिम के तमाम देश उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, कई तरह की बंदिशें लगेंगी, उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के आरोप भी लगेंगे, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि फर्क पड़ता है तो दोनों देशों के आम लोगों और उनके सैनिकों को, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है।

● **निखिल वर्मा,** भोपाल (म.प्र.)

किसानों का समाधान जरूरी

भारत में खेती कई कारणों से जोखिम भरा काम है। इसमें उत्पादन चक्र के साथ दूसरे कारण जुड़कर ऐसी स्थिति बना देते हैं कि किसानों के लिए कर्ज न लेना असंभव हो जाता है। लगातार घाटा और घटता मुनाफा उन्हें कर्ज का भुगतान करने में चूकने के लिए मजबूर करता है। यह चूक उन्हें और तकलीफ में डालती है, और कभी-कभी तो उन्हें आत्महत्या तक करने को मजबूर कर देती है। सरकार को किसानों के लिए और अधिक सोचने की जरूरत है, जिससे वे तकलीफ में न पड़ें और आत्महत्या को भी मजबूर न हों।

● **छवि रिछारिया,** नई दिल्ली

जैविक खेती को बढ़ावा

मप्र सरकार ने जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना तय किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को जैविक व प्राकृतिक खेती का मॉडल पेश करने के लिए कहा है, लेकिन अधिकतर मंत्री अभी खेती के प्रयोगों से दूर हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मंत्रियों को भी आगे आना चाहिए। जिससे अन्य लोगों में खेती को लेकर उत्साह बढ़ेगा। मुख्यमंत्री शिवराज अनार से लेकर आम तक की खेती करते हैं।

● **दुर्गेश साहू,** ग्वालियर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

नए सीडीएस पर फंसा पेंच

केंद्र सरकार देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नियुक्ति को लेकर निर्णय नहीं ले पा रही है। पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की एक हेलीकाप्टर दुर्घटना में मृत्यु के बाद इस पद को खाली पड़े लगभग तीन महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट न होने के चलते रक्षा मामलों के जानकार चिंता जाहिर करने लगे हैं। गौरतलब है कि जनरल रावत की इस पद पर नियुक्ति के बाद तीनों सेनाओं के मध्य आपसी समन्वय बैठाने का सिस्टम गति पकड़ने लगा था। जनरल रावत बहुत सुलझे हुए अंदाज में इस काम को आगे बढ़ाने में लगे थे जो उनकी दर्दनाक मृत्यु के पश्चात अधर में लटका बताया जा रहा है। रक्षा जानकारों की मानें तो सरकार के पास वर्तमान थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे को अगला सीडीएस बनाए जाने का एकमात्र विकल्प है क्योंकि तीनों सेनाओं के वर्तमान मुखिया में सबसे वरिष्ठ जनरल नरवणे ही हैं। सरकार यदि ऐसा करती है तो पहले उसे नया थल सेना प्रमुख चुनना पड़ेगा। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेजी से हालात बदलने लगे हैं जिनका असर भारत की सुरक्षा पर पड़ने का अंदेशा है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा पहले ही हो चुका है। गौरतलब है कि तालिबान भारत को अपना विरोधी मानता आया है।

नतीजों की नसीहत

चुनावी नतीजों ने वसुंधरा राजे को भी संदेश दे दिया है। प्रधानमंत्री के पहले शपथ समारोह से नदारद रहने वाली भाजपा की वे इकलौती मुख्यमंत्री थीं। वे अपने समर्थकों के साथ किसी न किसी बहाने पार्टी के समानांतर गतिविधि चलाती रहती हैं। उन्होंने इसी माह अपना जन्मदिन मनाया। दक्षिणी राजस्थान के बूंदी जिले के केशोराज पाटन मंदिर में मत्था टेकने के बाद, समर्थकों को संबोधित करते हुए याद दिलाया कि राजनीति में 1989 में उतरी थीं। सियासत की डगर कांटों भरी है, पर वे हार नहीं मानेंगी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में गहलोत सरकार को उखाड़ फेकेंगी। यह जिक्र भी कर दिया कि तीन की संख्या पार्टी के लिए शुभ है। 2003 में 120 और 2013 में 163 सीटें जीती थीं। इस रिकार्ड को 2023 में तोड़ देंगी। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और सतीश पूनिया के पोस्टर लगे थे, पर पूनिया मौजूद नहीं थे। हालांकि खुद प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। पिछले साल भी उन्होंने अपना जन्मदिन पूर्वी राजस्थान के भरतपुर से धार्मिक यात्रा शुरू करके मनाया था। पार्टी की तरफ से कोई अधिकृत बयान तो नहीं आया पर एक दिन पहले अलवर के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने वीडियो संदेश से पार्टी हित में उन्हें सलाह जरूर दे डाली कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का ख्वाब देखना छोड़ देना चाहिए।

प्रियंका पर सबकी निगाहें

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जिस अंदाज में उप्र के चुनावी समर में उतरी उससे एक बात स्पष्ट हो उभरी है कि भविष्य में कांग्रेस की तारणहार बनने का काम राहुल गांधी से कहीं ज्यादा प्रियंका करने वाली हैं। उप्र में लगभग मृतप्राय हो चुकी कांग्रेस को अपनी आक्रामक रणनीति के जरिए पुर्नजीवित कर प्रियंका ने अपने विरोधियों को तो करारा जवाब दे ही डाला, अपनी स्पष्टवादिता के चलते वे मीडिया की भी करीबी बन गईं हैं। आमतौर पर राजनेता अप्रिय बातों का स्पष्ट जवाब देने से बचते हैं। लेकिन प्रियंका अपवाद बन उभरी हैं। गत् दिनों चुनाव प्रचार के दौरान से पत्रकारों द्वारा पूछे गए हरेक प्रश्न का वे ईमानदार से जवाब देती नजर आईं। लखनऊ में एक प्रेसवार्ता के दौरान जब उनसे कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे पार्टी के बड़े नेताओं की बाबत पूछा गया तो उन्होंने बहुत ईमानदार जवाब दे सबको चौंका दिया। प्रियंका ने कहा कि 'राजनीति में नेता आते-जाते रहते हैं लेकिन दो नेताओं ने जिस तरीके से कांग्रेस को छोड़ा उससे मैं आहत हूं। एक हैं माधव राज सिंधिया जी के बेटे जिन्होंने सत्ता पाने के लालच में अपनी सरकार तक मप्र में गिरा दी। दूसरे नेता का नाम लेते हुए प्रियंका ने कहा 'आरपीएन सिंह की बाबत हमें पहले से ही पता था कि वे भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं।'

सन्नाटे का साया

5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने के बाद हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में भी सन्नाटा पसर गया है। प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को उम्मीद थी कि कम से कम पंजाब में कांग्रेस सरकार बना ही लेगी। लेकिन जिस तरह पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया और कांग्रेस का बुरा हाल हो गया, उससे प्रदेश के कांग्रेसी सदमे में आ गए हैं। उपचुनावों में हिमाचल में तीन विधानसभा और एक संसदीय हलके के उपचुनाव हुए थे और चारों सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर पार्टी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जोश भर दिया था। जुब्बल-कोटखाई हलके में तो भाजपा उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो गई थी। लेकिन पांच राज्यों के हुए चुनावों के नतीजों ने प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की नींद उड़ा दी है। उपचुनावों में जीत के बाद कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री की दौड़ के लिए जोड़-घटाव करने में लग गए थे। लेकिन पांच राज्यों के चुनाव आने के बाद अब ये नेता कहने लगे हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, पहले एकजुट होकर सत्ता में आना है।

आत्ममंथन की तरफ

कभी देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी होने और ज्यादातर प्रदेशों में मजबूत संगठन वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) आज अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष करती नजर आ रही है। सीपीआई (एम) तीन राज्यों में विशेषकर मजबूत राजनीतिक ताकत बन आजादी बाद उभरी थी। इन तीनों ही राज्यों-केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में वह कई दफा सत्ता में रही। पश्चिम बंगाल में 1977 से 2000 तक लगातार उसकी सरकार बनी। 23 बरस, 127 दिन तक सत्ता में रहने का यह रिकॉर्ड और किसी पार्टी का अभी तक किसी भी राज्य में नहीं बना है। त्रिपुरा में भी 1998 से 2018 तक पार्टी एकछत्र बीस बरस तक सत्ता में काबिज रही। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं। वर्तमान में केवल एक राज्य केरल में पार्टी की सरकार है। तमिलनाडु में वह डीएमके गठबंधन का हिस्सा होने चलते सरकार का हिस्सा जरूर है लेकिन यह हिस्सेदारी विपक्षी एकता को बनाए रखने चलते उसे दी गई है।

गधी का गुस्सा... कुम्हार पर

ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि गधी से गिरकर गुस्सा कुम्हार पर उतारना। कुछ ऐसी ही स्थिति प्रदेश की एक महिला मंत्री की है। उक्त महिला मंत्री वैसे तो अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहती हैं। यही नहीं, विवाद बढ़ाने का वे कोई भी मौका नहीं चूकती हैं। अपने ऊल-जुलूल बयानों के कारण विवादों में रहने वाली उक्त मंत्री की सरकार में बिलकुल नहीं चल रही है। आलम यह है कि मंत्री के पास जो प्रमुख विभाग है वहां उनकी कोई नहीं सुनता है। स्थिति यह है कि उस विभाग में या सरकार के पास वे जो भी काम का प्रस्ताव भेजती हैं, उसे फाइलों में दबा दिया जाता है। इस कारण उक्त मंत्री इस कदर चिड़चिड़ी हो गई हैं कि वे कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल रही हैं। विगत दिनों वे अपने दूसरे विभाग में पहुंचीं। वे बिना सोचे-समझे उक्त विभाग के प्रमुख सचिव पर पिल पड़ीं। मंत्री का धारा प्रवाह गुस्सा बढ़ता देख प्रमुख सचिव भी अपनी पर उतर आए और उन्हें टोकते हुए कहा कि आप गलत जगह आ गई हैं। वैसे आप जैसा चाहती हैं, वैसा काम कोई विभाग नहीं कर पाएगा। अधिकारी कायदे-कानून में बंधे होते हैं। इसलिए कोई भी काम नियमों के तहत ही होगा। आप दूसरी जगह का गुस्सा हमारे ऊपर क्यों निकाल रही हो। प्रमुख सचिव से मिले उपदेश के बाद उक्त महिला मंत्री कुछ शांत हुईं। लेकिन उन्हें कौन बताए कि गधी का गुस्सा कुम्हार पर उतारने से कुछ नहीं होने वाला।

वायरल हो गया प्रेमालाप

देश और प्रदेश की राजनीति में सम्मान की दृष्टि से देखे जाने वाले एक वरिष्ठ नेता का रूमानी चेहरा चर्चा का विषय बना हुआ है। ये वरिष्ठ नेता अपनी पार्टी में बड़ी हैसियत तो रखते ही हैं, साथ ही विपक्षी भी इन्हें भरपूर सम्मान देते हैं। सालों तक केंद्र की राजनीति करने वाले ये माननीय कुछ सालों से मप्र की राजनीति का चर्चित चेहरा बने हुए हैं। लेकिन उक्त नेता का एक चैट इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल होने की वजह यह है कि उन्होंने एक महिला के साथ कुछ ऐसा चैट किया है कि उसे प्रेमालाप माना जा रहा है। उनके प्रेमालाप चैट को प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में लोग अपने-अपने तरीके से चटखारे लगाकर सुना रहे हैं। यही नहीं कुछ लोग तो उक्त नेता का बॉलीवुड से भी संबंध जोड़ रहे हैं और कईयों के साथ उनका नाम जोड़कर किस्से सुनाए जा रहे हैं। वैसे उनके करीबी बताते हैं कि उक्त माननीय रसिया किस्म के नेता हैं। इस कारण उनका परिवार बिखरते-बिखरते बचा है। हालांकि नेताजी के करीबी लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह चैट उन्हें बदनाम करने के लिए वायरल किया गया है। अब इसमें सच्चाई क्या है, यह तो उक्त नेता ही जानें, लेकिन उसकी आड़ में उनके कई और किस्से गुणा-भाग कर खोजे जा रहे हैं।

मरता क्या नहीं करता...

ग्वालियर-चंबल अंचल के एक जिले के पुलिस अधीक्षक की पदस्थापना इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा इसलिए हो रही है कि एक कद्दावर नेता की अनुशंसा पर उक्त अधिकारी को उस जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले कुछ ऐसी शर्तें रख दी गई थीं जिसे न चाहते हुए भी उक्त अधिकारी को पूरी करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार सत्तारूढ़ पार्टी के कद्दावर नेता और केंद्र में मंत्री पद पर आसीन एक माननीय ने उक्त प्रमोटी आईपीएस का नाम ग्वालियर-चंबल अंचल के एक जिले में एसपी के लिए आगे बढ़ाया था। दिग्गज नेता की अनुशंसा पर उक्त अधिकारी को आनन-फानन में उस जिले का एसपी बना दिया गया। लेकिन शर्त रखी गई कि ज्वाइनिंग से पहले उन्हें आकर रसीद कटवानी पड़ेगी। उक्त प्रमोटी आईपीएस को शुरू में तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बुलाई गई जगह पर जब वे पहुंचे तो उनसे मोटी रकम की मांग कर दी गई। साथ ही एहसान भी जताया गया कि उक्त वरिष्ठ नेता के कारण तुमसे छोटी रकम ली जा रही है, वरना कई अधिकारी मोटी-मोटी रकम देकर जिले में उक्त कुर्सी लेना चाहते हैं। अब बेचारा प्रमोटी आईपीएस करता भी तो क्या करता। उसे अपने नेताजी का मान भी रखना था। सो मरता क्या न करता की तर्ज पर उसने रसीद कटवाकर रकम जमा करवाई, तब जाकर उसे जिले की कमान सौंपी गई।

एक और मंत्री रूठे

देशभर में समन्वय की मिसाल बनी प्रदेश सरकार में असंतुष्ट मंत्रियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में प्रदेश के एक बड़े विभाग सहित कई विभागों की जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्रीजी की नाराजगी की बात सामने आई थी कि अब एक और मंत्रीजी रूठ गए हैं। ये मंत्री भी प्रदेश के एक महत्वपूर्ण विभाग की कमान संभाल रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी तनिक भी सुनी नहीं जा रही है। सूत्रों का कहना है कि हाल ही में सरकार ने जिस एक प्रमुख विभाग को बंद किया है, मंत्रीजी चाहते थे कि उक्त विभाग 50 वर्ष से चल रहा था, जिसे बंद न किया जाए। इसके लिए उन्होंने अपना पूरा दम लगा दिया था। लेकिन उनकी एक नहीं चली और विभाग बंद कर दिया गया। इससे नाराज होकर मंत्रीजी ने अब विभागीय नोटशीट पर हस्ताक्षर करना बंद कर दिया है। उनका कहना है कि जब मेरी सुनी ही नहीं जा रही है तो मेरे हस्ताक्षर की क्या जरूरत है। गौरतलब है कि उक्त मंत्रीजी सत्ता, संगठन में बड़ी हैसियत के नेताओं में गिने जाते हैं। इन्हें सरकार का भी सबसे प्रमुख मंत्री माना जाता है। लेकिन इनकी भी नहीं सुनी जा रही है।

धीमा करंट जोर से लगा...

लापरवाही, भर्राशाही के लिए ख्यात मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों की चाल इन दिनों बदल गई है। सुस्ती के लिए चर्चित अफसरों को नए साहब ने 440 वोल्ट का करंट दे दिया है। साहब कंपनी क्षेत्र में निरंतर दौरे तो कर ही रहे हैं, साथ ही साहब ने हफ्ते में एक दिन वर्चुअल मीटिंग शुरू की है। हर दिन की रिपोर्ट तो पहले ही मांगी जा रही थी लेकिन कागजों के साथ साहब जमीनी हकीकत भी जांच रहे है। ऐसा ही पिछले दिनों हुआ। साहब ने मीटिंग में सवालों की बौछार कर दी। कुछ साहबों ने पुराने ढर्रे पर जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन नए साहब के आगे उनकी चल नहीं पाई। अब स्थिति यह है कि बिजली कंपनी का हर अफसर डरा हुआ है कि न जाने कब साहब उसकी क्लास लगा दें। नौकरी के अंतिम पड़ाव पर आ चुके एक अफसर तो इस रवैये से बेहद परेशान हैं। वे चिंता में हैं कि किसी तरह उनका समय कट जाए। कुछ जो बच गए हैं वो भी अब तेजी से अपने कामकाज को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। साहब ने भी साफ कर दिया है कि बहाना नहीं काम ही बोलेगा।

2023 की दावेदारी या 2024 की तैयारी

मप्र की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के तेवर आजकल बदले हुए हैं। उमा भारती मप्र में अचानक से बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। लोगों से लगातार मुलाकात, शराब बंदी के खिलाफ अभियान और शराब दुकान में तोड़फोड़ के मायने निकाले जा रहे हैं। उनकी राजनीतिक गतिविधियों का बड़े पैमाने पर केंद्र मप्र ही है। इससे कयास लगाया जा रहा है कि उमा 2023 के विधानसभा या 2024 के लोकसभा चुनाव में मप्र से दावेदारी ठोक सकती हैं। खुद उमा भारती ने भी 2024 में मप्र से लोकसभा चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। हालांकि वह कहां से यह चुनाव लड़ेंगी यह जाहिर नहीं किया है। गौरतलब है कि उमा 1989 से 1998 तक चार बार खजुराहो से लोकसभा के लिए चुनी गई थीं। इसके बाद 1999 से दिसंबर 2003 में मप्र की मुख्यमंत्री बनने तक उमा ने भोपाल का प्रतिनिधित्व किया। 2014 में उमा भारती ने उप्र के झांसी से चुनाव जीता था।

दुष्यंत कुमार की यह पंक्तियां तो आपने पढ़ी ही होगी... कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों...! इन पंक्तियों को प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की कद्दावर नेता उमा भारती ने हद से अधिक गंभीरता से ले लिया है। शायद यही वजह है कि अपने राजनीतिक लक्ष्य को साधने के लिए उन्होंने भी हाथ में पत्थर उठा लिया है। गत दिनों उन्होंने शराबबंदी के नाम पर एक शराब दुकान पर पत्थर बरसाए। दरअसल, ये पत्थर शराब की दुकान में चले हैं, लेकिन उनका लक्ष्य राजनीतिक कुर्सी पर है।

दरअसल, 2004 में मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद से उमा भारती की राजनीतिक महत्वाकांक्षा उछाल मार रही है। उनकी महत्वाकांक्षा को देखते हुए भाजपा ने केंद्र में मंत्री तक बनाया, लेकिन वे मप्र में राजनीति की उच्च कुर्सी की मंशा पाले हुए हैं। इसके लिए पार्टी पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने पिछले कुछ माह से शराबबंदी को मुद्दा बनाया है। साध्वी के इस मुद्दे को सत्ता और संगठन में स्वीकार भी किया है। और उन्हें आश्वासन दिया है कि सरकार और संगठन मिलकर नशाबंदी के खिलाफ अभियान चलाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग हर मंच से नशाबंदी अभियान चलाने की बात करते हैं। लेकिन उमा भारती की मंशा तो कुछ और ही है।

हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उमा भारती से मुलाकात कर उनकी मंशानुसार प्रदेश में नशाबंदी अभियान चलाने को कहा था, लेकिन मुलाकात के दो दिन बाद ही पूर्व मुख्यमंत्री अचानक भेल बरखेड़ा पठानी की आजाद नगर बस्ती में पहुंचीं और शराब दुकान में गईं और पत्थर मारकर शराब की बोतलें फोड़ दीं। सवाल उठता है कि आखिर उमा भारती ने इतना उतावलापन क्यों दिखाया। दुकान के खिलाफ वे शासन-प्रशासन से शिकायत कर सकती थीं। उनकी बात कोई नहीं टालता। दरअसल 2005 में शिवराज का मुख्यमंत्री बनना उमा भारती को पसंद नहीं आया। तभी से वे शिवराज के खिलाफ मोर्चाबंदी करती रही हैं। लेकिन शिवराज की विनम्रता के आगे उनके सारे प्रयास असफल हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने सरकार को बदनाम करने के लिए शराबबंदी को मुद्दा बनाया है।

दरअसल **हर तरफ से अकेली पड़ी** उमा भारती सक्रिय राजनीति में वापसी के लिए फड़फड़ा रही हैं। प्रदेश में अब उनका कोई साथी नहीं बचा है। जो थे वे सब साथ छोड़कर जा चुके हैं। वे लगातार बोल रही हैं। लेकिन उनके बोले पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। परिणाम सामने हैं। उमा पत्थर मारने लगी हैं। लेकिन उनका यह कदम उनको भारी पड़ सकता है।

उमा भारती ने नवंबर 2005 में अपनी ही पार्टी से नाराज होकर बगावत कर दी थी। भोपाल के भाजपा कार्यालय में अगले मुख्यमंत्री के नाम पर शिवराज सिंह चौहान की मुहर लगते ही तल्ख मिजाज उमा भारती ने अपने साथ पार्टी के कई विधायकों को लेकर पैदल राम रोटी यात्रा शुरू कर दी थी। बाद में अलग पार्टी भी बनाई। उमा भारती ने इस दौरान कई बार पार्टी और उनके नेताओं को जमकर कोसा था। उमा भारती ने भले ही भाजपा में घर वापसी कर ली हो लेकिन उनके भीतर की आग कहीं न कहीं अभी भी धधक रही है। उमा भारती को सदस्यता देने के बाद से ही पार्टी ने उन्हें मप्र से अलग-थलग रखा लेकिन उनका मप्र से ऐसा लगाव रहा है कि वे ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाती।

● **लोकेंद्र शर्मा**

अपनी सरकार में क्यों नहीं की शराबबंदी?

उमा भारती की पत्थरबाजी पर अब विपक्ष चुटकियां ले रहा है। पार्टी और नेताओं से सवाल किए जा रहे हैं। इन सबके बीच सवाल यह भी है कि उमा भारती को शराब की बिक्री पर इतना ही ऐतराज था तो उन्होंने अपनी सरकार रहते हुए खुद शराबबंदी क्यों नहीं की? क्या साध्वी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध नहीं जता सकती थीं। क्या वे अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री से सीधे बात कर शराबबंदी को लागू नहीं करवा सकती। शायद या तो ये सारे रास्ते वे अपनाना नहीं चाहती या फिर एक बार फिर वे मप्र में शराबबंदी के मुद्दे पर जनता को अपनी तरफ फिर से केंद्रित करना चाहती हैं। वे यह भी जानती हैं कि प्रदेश की खस्ताहाल आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए शराब से मिलने वाला राजस्व ही सबसे बड़ा मददगार है। ऐसे में उनका यह कदम किसी दूसरी तरफ ही इशारा करता है।

सस्ती हुई शराब...पर बेचने वाले नहीं तैयार

मप्र की नई आबकारी नीति सरकार और शराब कारोबारियों के गले की फांस बन गई है। शराब कारोबारी नई आबकारी नीति के अनुसार शराब की दुकानें लेने को तैयार नहीं हैं।

पंकज उधास की यह गजल तो आपने सुनी ही होगी कि महंगी हुई शराब, थोड़ी-थोड़ी पिया करो। लेकिन इसके उलट मप्र में सरकार ने शराब सस्ती कर दी है और पीने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है, लेकिन शराब बेचने के लिए कोई तैयार नहीं है। इससे सरकार के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। दरअसल, प्रदेश में दिनों-दिन जिस रफ्तार से शराब के खरीदार बढ़ रहे हैं, उस रफ्तार से उन्हें बेचने वालों (ठेकेदार) की संख्या नहीं बढ़ रही। प्रशासन से लेकर आबकारी विभाग तक ने इसमें इजाफा करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन बेचने वाले तलाशने से भी नहीं मिल रहे। हुआ यह है कि इस बार शराब सस्ती कर दी है, लेकिन इसे बेचने की प्रक्रिया और शुल्क दोनों पिछले बार से ज्यादा हो गया है। अब बेचने वाले मायूस हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सस्ती शराब में वे अपना फायदा कहां लेंगे। इधर विभाग टेंडर पर टेंडर किए जा रहा है।

गौरतलब है कि शराब की बिक्री प्रदेश सरकार के लिए राजस्व का बड़ा स्रोत है। सरकार को हर साल औसतन 12,500 करोड़ रुपए शराब की बिक्री से राजस्व मिलता है। लेकिन इस बार स्थिति यह है कि अभी तक 7,600 करोड़ रुपए के ही ठेके हो पाए हैं। उधर, सरकार 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू करने जा रही है। अगर समय पर शेष दुकानों के ठेके नहीं होते हैं तो या तो सरकार को औने-पौने दामों में ठेके करने होंगे या फिर उन दुकानों को खुद चलाना पड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के कारण पिछले दो साल से शराब का टेंडर नहीं हो पाया था। इस दौरान आबकारी विभाग ने शराब की दरों में 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी कर दी थी। इस बार 20 प्रतिशत और बढ़ा दिया गया है। यहां तक तो ठीक था, इस बार शराब को एमएसपी और एमआरपी पर बेचने की बाध्यता कर दी गई है। यानी प्रदेश में एक समान भाव से शराब बेची जाएगी। व्यवसायी एमआरपी से 25 प्रतिशत अधिक की दर पर शराब बेच सकेंगे। इससे व्यवसायियों को तकरीबन 35 फीसदी आय प्रभावित हो रही है। इसलिए बड़े ठेकेदार इस बार शराब की दुकान लेने से कतरा रहे हैं।

दरअसल, प्रदेश में अवैध और जहरीली शराब को रोकने के लिए सरकार ने इस बार नई आबकारी नीति में कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं, जो व्यावसायियों को पसंद नहीं हैं। इस बार सरकार ने शराब व्यावसायियों के सिंडीकेट को तोड़ दिया है। इससे अवैध शराब का कारोबार रुकेगा। वहीं उपभोक्ताओं को 35 फीसदी सस्ती शराब मिलेगी। जानकारों का कहना है कि इससे प्रदेश में शराब की बिक्री बढ़ेगी और अधिक राजस्व मिलेगा। लेकिन शराब ठेकेदार ठेका लेने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि यह घाटे का सौदा है। जबकि सरकार का मानना है कि प्रदेश में शराब सस्ती होने से दूसरे राज्यों से यहां शराब नहीं आएगी। वहीं दूसरे राज्यों में मप्र की शराब बिकेगी।

ठेकेदारों का कहना है कि नई पॉलिसी के चलते ठेके नीलाम नहीं हो रहे हैं। इसके चलते विभाग ठेकेदारों पर दवाब बना रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद प्रदेश में इस बार अभी तक पूरी दुकानों का ठेका नहीं हो पाया है। उधर, 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी। जिसमें शराब सस्ती हो जाएगी। शिवराज सरकार ने विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी 10 फीसदी घटाने का फैसला लिया है। इससे विदेशी शराब के दामों में 50 से 500 रुपए प्रति बोतल तक की गिरावट होगी। व्हिस्की, बीयर, वाइन सभी के दाम घटेंगे। इसके अलावा देसी शराब भी सस्ती होगी। देसी शराब का 110 रुपए में मिलने वाला पउवा 85 रुपए में मिलेगा। नई शराब नीति के तहत कोई भी व्यक्ति जिसकी सालाना आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, वह 50 हजार रुपए जमा कर निजी बार का लाइसेंस ले सकेगा। उन्हें घर पर एक छोटा बार खोलने की अनुमित दी जाएगी। साथ ही घर पर शराब रखने की लिमिट भी सरकार ने 4 गुना तक बढ़ा दी है। अब देखना यह है कि नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश सरकार शेष बची शराब दुकानों का ठेका कैसे करती है।

● सुनील सिंह

पॉलिसी में 3 बिंदुओं का विरोध

मप्र में नई शराब पॉलिसी का शराब ठेकेदार खुलकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पॉलिसी में 3 ऐसे बिंदु हैं, जो ठेकेदारों की कमर तोड़ रहे हैं। देसी-विदेशी शराब दुकानें एक ही जगह खोलने, मार्जिन कम होने और माल उठाने की पाबंदियां तय करना प्रमुख है। वहीं, रूटीन चेकअप के बहाने अफसर दुकानें सील भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि आबकारी विभाग के अफसर विगत दिनों राजधानी की शराब दुकानों की चेकिंग करने भी पहुंचे थे। इस दौरान कुछ दुकानों को सील भी कर दिया गया। इसके बाद शराब ठेकेदार सड़क पर उतर गए। उनका कहना था कि अफसरों ने रूटीन चेकिंग के बहाने छापा मारकर कई दुकानें सील कर दी। चेकिंग के दौरान शराब की बिक्री भी नहीं कर पाए। इसके विरोध में दुकानें बंद की गई हैं। वहीं देसी-विदेशी शराब एक ही दुकान से बेची जाएगी। ठेकेदारों का मानना है कि इससे बिक्री पर असर पड़ेगा। मार्जिन कम होने से डायरेक्ट-इनडायरेक्ट होने वाले खर्च को वहन नहीं कर सकेंगे। माल उठाने की पाबंदियां की गई हैं। इससे मुश्किलें खड़ी होंगी। प्रदेश के 17 जिलों में सिंगल की जगह ग्रुप में दुकानों के टेंडर किए जा रहे हैं। इनमें भोपाल, राजगढ़, इंदौर, खंडवा, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, कटनी, रीवा, सतना, उज्जैन, नीमच, सागर, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड और मुरैना जिले शामिल हैं। वर्ष 2020-21 और 2021-22 में यह सिंगल ठेके की व्यवस्था थी। यानी एक ही ठेकेदार जिले की दुकानों का संचालन करते थे। वर्ष 2022-23 के लिए यहां पर 3-3 दुकानों के ग्रुप बना दिए गए हैं। यानी, ठेकेदार ग्रुप में दुकान चलाएंगे। हालांकि, इन जिलों में ठेकेदार दुकानें लेने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।

मप्र विधानसभा का 13 दिवसीय बजट सत्र के 7 दिनों में सदन के अंदर केवल कागजी घोड़े दौड़ाए गए हैं। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण, बजट का प्रस्तुतिकरण, विधायक निधि में बढ़ोत्तरी के अलावा और कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे प्रदेश की 8 करोड़ आबादी को राहत मिले। सरकार ने न तो पेट्रोलियम पदार्थों के वेट टैक्स कम किए और न ही अन्य तरह की राहत दी है। इस कारण प्रदेश की जनता के सामने महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी अभी भी मुंह फैलाए खड़ी हुई है।

कागजी साबित हुआ बजट सत्र

7 मार्च से शुरू हुए बजट सत्र से लोगों को उम्मीद थी कि प्रदेश सरकार इस सत्र में राहत भरी घोषणाएं करेगी। लेकिन न तो सत्तापक्ष और न ही विपक्ष जनता की चिंता में दिखा। सत्तापक्ष ने वोट बैंक को साधने के लिए चुनावी घोषणाएं कर डाली। वहीं विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने के लिए बेवजह के मुद्दों पर हल्ला करता रहा। जिस तरह सदन में स्थिति दिख रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि इस बार भी सत्र पूरे दिन नहीं चल पाएगा। हालांकि अभी तक जितनी बैठकें हुई हैं, उसमें सत्तापक्ष ने मिशन 2023 को देखते हुए घोषणाओं की बौछार कर दी है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान दो घंटे से अधिक समय तक सरकार का पक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं और शासन की उपलब्धियां गिनाईं। हालांकि ये सभी घोषणाएं 2023 को ध्यान में रखकर की गईं लगती हैं। मप्र में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। जिसकी तैयारियां सभी दल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की घोषणाओं को भी इसी नजर से देखा जा रहा है। इस सबके बीच एक बात और कि शिवराज की घोषणाओं में वे सभी बातें शामिल दिख रही हैं, जिसके दम पर कई राज्यों में सरकार बनती देखी गई हैं।

विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है, जिससे प्रदेश के किसानों को कर्ज के ब्याज से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार में कर्ज माफी नहीं होने से किसान डिफाल्टर हो गए। इसलिए डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान की। मुख्यमंत्री शिवराज ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 48 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ किया जाएगा। कोविड काल के दौरान का बिजली बिल सरकार माफ करेगी।

इसी के साथ मुख्यमंत्री आवास मिशन शहरी और स्व-सहायता समूह के सदस्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले हितग्राहियों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अंकुर अभियान और एक जिला-एक उत्पाद योजना के हितग्राहियों से सीधे बात भी करेंगे। और उनकी गतिविधियों की जानकारी लेंगे। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा, जो समय पर कर्ज नहीं भर पाए थे और डिफाल्टर हो गए थे, चूंकि उस कर्ज पर ब्याज लगता जा रहा है, इस कारण सरकार ने इस ब्याज की राशि को भरने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 30 लाख हितग्राहियों को आवास देने का प्रविधान किया गया है। 23 लाख मकान बनाकर दिए जा चुके हैं। इस साल के अंत तक सभी 30 लाख आवास पूरे कर दिए जाएंगे। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 लाख 21 हजार हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराएंगे। प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में 27 लाख नए आवास बनेंगे। बड़े परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना में भूखंड के पट्टे दिए जाएंगे इसके लिए सर्वे कराया जाएगा। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल में जो नाम काटे गए थे वे सभी नाम जोड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना धूमधाम से प्रारंभ होगी। जनजातीय कल्याण सरकार की प्राथमिकता में है। वन

मप्र में अब 2 से बढ़ाकर 3 करोड़ की जाएगी विधायक निधि

मप्र विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि विधायक निधि को 2 से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए किया जाएगा। 50 लाख रुपए विधायकों को स्वेच्छा अनुदान राशि दी जाएगी। इससे जनता को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण पर 7 मार्च को पेश किए गए कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए यह घोषणा की। उन्होंने लगभग दो घंटे के जवाब के दौरान विपक्षी सदस्यों की टोकाटाकी के बीच कहा कि विधायक सार्वजनिक जीवन जीते हैं और आम लोगों को उनसे काफी अपेक्षाएं रहती हैं। इसलिए सरकार ने विधायक निधि और स्वेच्छानुदान राशि बढ़ाने का फैसला लिया है। बता दें कि वर्तमान में मप्र के विधायकों को 1 करोड़ 85 लाख रुपए की विधायक निधि मिलती है। वे राशि से अपनी अनुशंसा से जनकार्य, विकास कार्य, खेल, शिक्षा आदि पर खर्च कर सकते हैं। इसके लिए प्रस्ताव विधायक की अनुशंसा पर ही मंजूर होते हैं और राशि भी इसी आधार पर दी जाती है।

अधिकार पट्टे सभी पात्र व्यक्तियों को दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए भरपूर राशि दी जाएगी। इन सभी वर्गों के कल्याण में कोई कसर सरकार नहीं छोड़ेगी। लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण में उच्च शिक्षा के लिए निशुल्क पढ़ाई का इंतजाम किया जाएगा। भोपाल और इंदौर में महिला उद्यमियों के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण और शहरी विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। 29 मार्च को रोजगार दिवस मनाया जाएगा। भू-माफिया के खिलाफ सरकार का अभियान जारी रहेगा। अभी तक 21 हजार एकड़ भूमि माफिया से मुक्त कराई गई है, उन पर गरीबों के आवास बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा, कर्मचारी के हित में काम करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायक निधि तीन करोड़ रुपए करने की घोषणा की जिसमें 50,00,000 स्वेच्छा अनुदान के रहेंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि भू-माफियाओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है। 21 हजार एकड़ जमीन मुक्त कराई है। जो जमीन मुक्त कराई गई है, वह गरीबों को मकान बनाने के लिए दे दी जाएगी। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। भोपाल में हाल ही संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं। चिटफंड घोटाले वालों से राशि वसूल कर लोगों को लौटा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि अनुसूचित जनजाति सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार को जितना कर्जा लेना पड़े लेंगे। हम ही नहीं हर राज्य सरकार कर्जा लेती है, जबकि कर्जा लेने में अंतर होता है। गरीब कल्याण में भू अधिकार पट्टा देकर जमीन का मालिक बनाएंगे। भोपाल-इंदौर में महिलाओं के लिए अलग से क्लस्टर पार्क बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता एक-दूसरे की हार की खुशी मनाने में लगे हुए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को खुद की हार के दुख से ज्यादा चन्नी के हारने की खुशी है। सदन में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मामला गूंजा। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि कोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस ने कोर्ट में एडवोकेट ही खड़े नहीं किए। भाजपा की सरकार 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण दिलाकर ही दम लेगी। 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे। वक्तव्य के दौरान कांग्रेस के टोकने पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये टोका-टोकी अब मैं सहन नहीं करूंगा। लाडली लक्ष्मी-2 योजना लागू की जाएगी।

मुख्यमंत्री शिवराज ने आगे कहा कि हमने कभी बदले की कार्यवाही नहीं की है। पिछली सरकार में हमारे मंत्री नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, भूपेंद्र सिंह सहित कईयों को परेशान किया गया। मैं किसी से मिलने गया, तो उसे भी परेशान किया गया। बुलडोजर चलवाए गए, जमींदोज कर दिया गया। राजनीति में भेदभाव और अन्याय 15 माह की सरकार में हुआ। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। हम ही नहीं हर राज्य कर्जा लेती है, जबकि कर्जा लेने में अंतर होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोविड काल के बिजली बिल माफ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बिलों का भुगतान कर दिया है, उनकी राशि अगले बिलों में समायोजित की जाएगी। कोरोनाकाल में 88 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का 6,000 करोड़ रुपए का बकाया बिल माफ किया जाएगा। दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। आप की घोषणाओं में बिजली मुफ्त देना, बिल माफ करना प्राथमिकता में था। अब शिवराज भी इसी रास्ते फिर सत्ता की रहा तलाशते दिख रहे हैं। 2018 में कमलनाथ सरकार भी यही कर चुकी है। शिवराज ने इसे कोरोना के नाम से आगे बढ़ाने की कोशिश की है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को भी राहत देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमलनाथ सरकार के दौरान किसानों की कर्ज माफी नहीं होने से कई किसान डिफाल्टर हो गए। जो किसान डिफाल्टर हो गए हैं, उनके कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। 2018 के चुनावों की बात करें तो कांग्रेस ने किसानों के कर्ज की बात करके ही मप्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सरकार बनाई थी। किसान हर चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दा रहते हैं। केंद्र सरकार भी किसानों के मुद्दे को केंद्र में रखते हुए कई योजना बना चुकी है। हाल ही में हुए उप्र के चुनावों में भी किसानों के लिए लगभग हर दल ने घोषणा पत्र में जगह दी थी।

मुख्यमंत्री ने एक बात और कही कि प्रदेश सरकार भूमाफिया पर लगातार कार्रवाई कर रही है। भूमाफिया से 21 हजार एकड़ जमीन मुक्त कराई गई है। इस जमीन पर गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे। उप्र में योगी सरकार के फिर दमदारी से लौटने के पीछे अपराधियों पर सख्ती को भी एक कारण माना जा रहा है। अपराधियों के ठिकानों पर जमकर बुलडोजर चला। परिणाम के बाद तो लोगों ने बुलडोजर पर रैलियां की। योगी को बुलडोजर बाबा भी कहा जाने लगा। शिवराज ने भी माफिया पर सख्ती वाला रूप धरना शुरू कर दिया है। ये घोषणा भी उप्र चुनाव से प्रेरित बताई जा रही है। हालांकि मप्र में अपराधियों पर लगाम कसने के लिए पहले से ही इस तरह की कार्रवाई की जाती रही हैं। लेकिन उप्र के अपार बहुमत के बाद फिर बुलडोजर चर्चा में आया है।

● **कुमार राजेन्द्र**

जनता को बजट के फायदे गिनाएंगे विधायक

गत दिनों भाजपा की विधायक दल की बैठक भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित हुई। दो भागों में हुई बैठक में पहले में बजट पर चर्चा हुई और दूसरे में राजनीतिक विषयों पर चर्चा की गई। भाजपा बजट के फायदे गिनाने अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री निवास पर बैठक में सुशासन संस्थान के वीसी सचिन चतुर्वेदी ने बजट पर प्रजेंटेशन दिया। इसमें बजट के प्रमुख बिंदुओं और उनसे आमजन को कैसे लाभ मिलेगा विधायकों को बताया गया। इसमें वित्त विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक के बाद बताया कि बैठक में बजट पर प्रजेंटेशन दिया गया। इसमें विधायकों को बजट की बारीकियों को बताया गया। बैठक में मप्र के बजट को आम जनता तक पहुंचाने के लिए विस्तार से चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि कोरोना की विपदा के बाद भी प्रदेश में ग्रोथ हुई है। सरकार ने जनहित में राहत देने के लिए निर्णय लिए और योजना लेकर आई। इनको मंत्री, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी जनता को बताएंगे। गृहमंत्री ने कहा कि अप्रैल में सरकार के मंत्री और विधायक जनता तक बजट और सरकार की उपलब्धियां और कामों को जनता को बताएंगे। बता दें प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने आगामी 2023 चुनाव की तैयारी शुरू कर ली है। दोनों ही राजनीतिक दल वोट बैंक को साधने में जुट गए हैं।

नाम का महाकौशल विकास प्राधिकरण

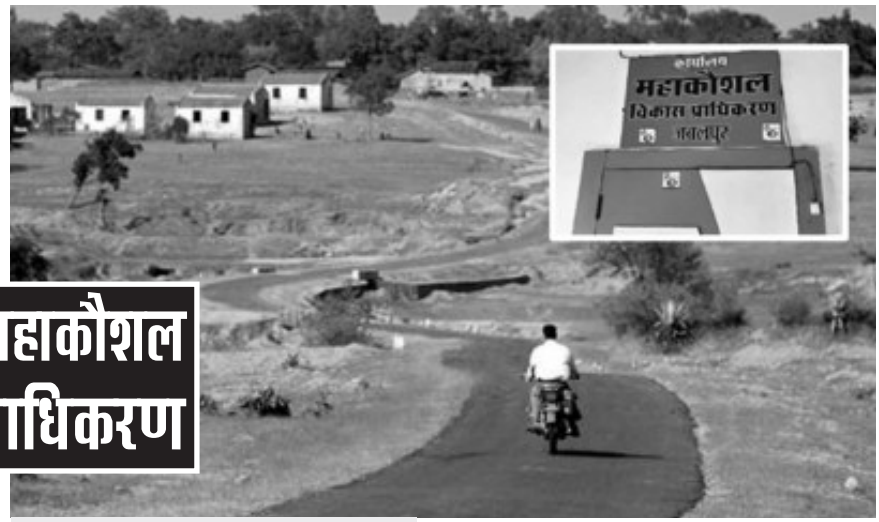

महाकौशल क्षेत्र के पिछड़ेपन, आर्थिक और सामाजिक विकास के उद्देश्य से गठित हुए महाकौशल विकास प्राधिकरण को स्वयं ही विकास की दरकार है। स्थापना के 14 साल बीतने के बाद भी यह प्राधिकरण कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं कर सका। कह सकते हैं कि सरकार की ओर से प्राधिकरण की घोषणा करने के बाद अनाथ छोड़ दिया गया। प्राधिकरण के अंतगर्त संभाग के सात जिले हैं, लेकिन विकास और कार्ययोजना के नाम पर यहां कुछ भी खास नहीं किया गया।

महाकौशल विकास प्राधिकरण का गठन प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 2008 में किया था। जिसमें महाकौशल अंचल के सात जिले जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा जिले के विकास को पंख लगाने के सपने दिखाए गए थे। क्षेत्र में विकास की जो नई संभावनाएं हैं उनकी विधिवत योजना कार्य करना उद्देश्य था। प्राधिकरण केवल राजनीतिक नियुक्ति के लिए ही रह गया है। 14 वर्षों के दौरान यहां अध्यक्ष के रूप में तीन राजनीतिक नियुक्ति हुई। मौजूदा स्थिति में अभी यहां पर संभागीय आयुक्त प्रशासक हैं।

प्राधिकरण के लिए कुल पांच पद स्वीकृत हैं, परंतु अभी यहां मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अलावा एक लिपिक है। यहां पर पांच पद प्रतिनियुक्ति पर भरे जाना है परंतु प्राधिकरण की स्थापना के बाद से अब तक किसी भी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई। बोर्ड बैठक भी बीते वर्षों से नहीं हुई। हर तीन माह में बोर्ड बैठक होनी चाहिए। इसमें सांसद, विधायक व पदाधिकारी शामिल होते हैं। विकास कार्य **संबंधी विषयों** पर प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन, बजट नहीं है। महाकौशल विकास प्राधिकरण में विकास कार्यों के लिए बजट का रोना है। प्राधिकरण को 14 वर्षों में लगभग कुल 25 करोड़ का बजट मिला है जिसमें से 3 कार्य किए गए। इनमें डुमना नेचर पार्क में कॉटेज व प्रजेंटेशन हाल का निर्माण कराया गया। निर्माण के बाद यह नगर निगम को सौंप दिया गया। इसके अलावा कटनी में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य एवं मंडला के तारागढ़ में मेला स्थल का निर्माण कराया गया है। बीते 5 वर्षों के दौरान प्राधिकरण को 25 लाख का ही बजट मिल रहा है।

महाकौशल क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक विकास, पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। प्राधिकरण जनप्रतिनधियों के माध्यम से व विभिन्न योजनाओं के माध्यम से यहां के विकास कार्यों की योजना बनाते। इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्राधिकरण के माध्यम से होना था। क्रियान्वयन के लिए एजेंसी का गठन होना था। उसके माध्यम से स्वीकृत कार्य होने थे। लेकिन, सरकार ने प्राधिकरण का गठन किया। बाद में इसके बजट घटाकर 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिया। महाकौशल विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष प्रभात साहू का कहना है कि महाकौशल विकास प्राधिकरण का गठन सात जिलों के विकास को गति देना है। अध्यक्ष रहते मैंने सबसे पहले पूर्णकालिक सीईओ, सिविल इंजीनियर, योजना अधिकारी सहित आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति, प्राधिकरण स्वयं ही एजेंसी के रूप में अपने कार्य करा सके, इसके लिए भी प्रस्ताव दिया था। यहां सांसद, विधायकों की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर विकास योजना बनाकर निर्माण कार्य करवाया जाए।

गौरतलब है कि वर्ष 2007-08 में प्रदेश की शिव सरकार द्वारा महाकौशल, बुंदेलखंड और विंध्य विकास प्राधिकरण का अलग-अलग गठन किया गया था। यह समय प्रदेश में होने वाले आम विधानसभा चुनाव के ठीक पहले का था। यही वजह है कि लोगों का तो ठीक सरकार की उपेक्षा के चलते नेताओं में भी इनको लेकर कोई रूचि नहीं रह गई। सरकार ने इनका गठन किया और फिर उनसे पूरी तरह से मुंह फेर लिया जिसके चलते इनका अपना कोई भवन भी अब तक नहीं बन सका है। लिहाजा अंचलों के विकास का जिम्मा उठाने वाले यह प्राधिकरण खुद ही विकास की राह देखने को मजबूर बने हुए हैं। अब तो हालत यह है कि इनमें नाम के लिए ही कर्मचारी रह गए हैं। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का दफ्तर तो महज एक कमरे तक ही सीमित रह गया है। यही नहीं उसमें भी तीन निचले स्तर के ही कर्मचारी हैं। खास बात यह है कि अब तो सरकार इनको बंद करने की तैयारी कर चुकी है। इसके लिए दो माह पहले प्रस्ताव तक तैयार कर लिया गया है। यह प्रस्ताव योजना विभाग द्वारा तैयार किया गया है। दरअसल इनके गठन के बाद से ही यह प्राधिकरण सरकार की प्राथमिकता में कभी नही रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 15 और भाजपा की शिव सरकार के एक साल में अब तक इनमें से किसी में भी कोई राजनीतिक नियुक्ति तक नहीं की गई है। दरअसल इन प्राधिकरणों का गठन उस समय विधानसभा के आम चुनाव के ठीक पहले राजनीतिक फायदे के लिए किया गया था। यह वह समय था, जब प्रदेश में पृथक बुंदेलखंड और विंध्य को नया प्रदेश बनाने की मांग जोर पकड़ रही थी।

● **जयसिंह**

बंद होंगे मप्र के तीन विकास प्राधिकरण

मप्र के तीन प्रमुख अंचलों के विकास के लिए पूर्व में भाजपा की शिवराज सरकार के समय गठित किए गए तीनों विकास प्राधिकरणों को बंद करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव की तैयारी बीते साल कर ली गई थी। हालांकि इस पर अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है, लेकिन अघोषित रूप से यह प्राधिकरण बंद ही पड़े हुए हैं। हालत यह है कि न तो इनमें कोई पदाधिकारी लंबे समय से है और न ही बजट में इनके लिए किसी तरह की कोई राशि का प्रावधान किया गया है। यही वजह है कि अब यह तीनों शोभा की सुपारी बन चुके हैं। जनता की जगह राजनीतिक फायदे के लिए गठित किए गए इन प्राधिकरणों को लेकर सरकार की अरुचि इससे ही समझी जा सकती है कि बीते डेढ़ दशक में इन्हें पर्याप्त बजट तक नहीं दिया गया। यही नहीं दो मौकों को छोड़ दिया जाए तो सरकार उनमें राजनीतिक स्तर की नियुक्तियां तक ही नहीं कर सकी है। इन तीनों में शामिल विंध्य और महाकौशल में 8-8 तो बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण में नव गठित निवाड़ी शामिल होने के बाद अब 7 जिले आते हैं। इनमें से अधिकांश जिले बेहद पिछड़ेपन का शिकार हैं।

टोलों-मजरों में भाजपा की बैठकें

बीते विधानसभा चुनाव परिणामों से सबक लेते हुए भाजपा संगठन आगामी आम विधानसभा चुनाव में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि इस बार टीम वीडी द्वारा बीते कई माह से लगातार पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है। दरअसल बीते चुनाव में बहुमत में कुछ सीटों से पिछड़ जाने की वजह से भाजपा को लगातार चौथी बार सरकार बनाने से वंचित रहना पड़ा था। यही वजह है कि भाजपा का प्रदेश संगठन चुनाव के दो साल पहले से लगातार चुनावी मोड में काम कर रहा है। आमजन से लगातार संपर्क और संवाद के लिए अब संगठन ने बस्तियों, गांवों, मजरों टोलों में परिवार बैठकों का आयोजन करने की रणनीति तैयार की है। यह पूरी कवायद बूथ को मजबूत करने के लिए की जा रही है। इस कार्यक्रम के लिए बूथ विस्तारक अभियान को आधार बनाया गया है।

गौरतलब है कि संगठन ने तय किया हुआ है कि हर हाल में भाजपा के वोट शेयर में 11 फीसदी की बढ़ोतरी की जाए, जिससे की भविष्य में 2018 जैसी स्थिति का सामना पार्टी को न करना पड़े। पार्टी द्वारा इसी कवायद की मंशा से हर बूथ पर तीन लोगों की टीम का गठन किया गया है, जिन्हें प्रशिक्षित कर पहले संगठन विस्तार फिर चुनाव के काम में लगाया जाने की तैयारी की जा रही है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ही पार्टी द्वारा एक महीने पहले बूथ विस्तारक अभियान शुरू किया था। इसके तहत उसके नेता और कार्यकर्ता को हर गांव में 100 घंटे का समय देने के निर्देश दिए थे। तीन सप्ताह से अधिक समय तक चले इस अभियान में पार्टी ने सभी 65 हजार बूथों तक जाकर लोगों से उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं को संपर्क के लिए उतारा था। पार्टी के इस अभियान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर केंद्रीय मंत्री, प्रदेश संगठन के नेताओं और मंत्री, सांसद, विधायकों तक ने मैदानी स्तर पर उतरे थे। इसके बाद टीम वीडी ने अब लोगों तक अपनी विचारधारा और योजनाएं पहुंचाने के उद्देश्य से तय किया है कि हर बूथ पर तीन लोगों की टीम बनाई जाएगी। इस टीम में बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए, बूथ लेबल एजेंट को रखा गया है। इन्हें प्रशिक्षण देने के लिए बाकायदा पाठ्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है।

संगठन द्वार बूथ की ग्रेडिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत बूथ की ग्रेडिंग तीन स्तर पर की जाने की व्यवस्था बनाई गई है। इसके तहत बूथ को ए, बी और सी में श्रेणी में बांटा गया है। पिछले दो विधानसभा और एक लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर बूथ की ग्रेडिंग की गई है। पार्टी को 70 से 75 फीसदी सतत् वोट मिलने वाले बूथ को ए प्लस तो पचास फीसदी के ऊपर वोट मिलने वाले को बी और इससे कम वोट मिलने वाले को सी श्रेणी में रख उसकी ग्रेडिंग का काम किया जा रहा है। इसके आधार पर ही बूथ स्तर पर उठाए जाने वाले कदमों को तय किया जाना है।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में संगठन और राजनीति से जुड़े विशेषज्ञों द्वारा बूथ स्तर पर गठित की जा रही तीन सदस्यीय टीम के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम तैयार करवाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इसमें भाजपा की पंच निष्ठाएं, संगठन के तत्व, संगठन गढ़े और अपनी बात को सरल तरीके से लोगों तक पहुंचाने जैसे विषयों को शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा विचारधारा और योजनाओं को कैसे लोगों को बताएं और कैसे उन्हें पार्टी से जोड़कर संगठन का विस्तार करें, इसके तरीके भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं। इस टीम को एक दिन में तीन सत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह सत्र पूरी तरह से चर्चात्मक होंगे। इसमें बूथ के बारे में टीम के विचार भी लिए जाएंगे और फिर उनसे चर्चा कर उन्हें लोगों तक कैसे संगठन का विचार पहुंचाना है, इस बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही मतदान संबंधी कई प्रकार की जानकारी भी टीम को दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि किस मतदान केंद्र पर कौन एजेंट होगा, यह भी भाजपा अभी से तय करने में लग गई है। प्रशिक्षण टीम में दो सदस्य होंगे। इसके बाद इनकी मंडलवार बैठक भी आयोजित की जाएगी।

भाजपा ने हर बूथ पर किए जाने वाले 7 कामों की सूची तैयार की है। इसमें 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस, 14 अप्रैल डॉ. अम्बेडकर जयंती, 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस, जन्माष्टमी, कुशाभाऊ ठाकरे जयंती, 25 सितम्बर दीनदयाल जयंती और 25 दिसम्बर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने के कार्यक्रम और पार्टी द्वारा चलाए जा रहे अभियानों से लोगों को जोड़ने का काम शामिल है। इसके अलावा मतदाता सूची के पन्ना अनुसार पन्ना समिति का गठन करना। जिसमें एक प्रमुख और चार से पांच सदस्यों को शामिल किया जाएगा।

● **राजेश बोरकर**

टीम वीडी के नवाचार को पूरे देश में लागू करेगी भाजपा

संघ और भाजपा की प्रयोगभूमि मप्र में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की टीम ने बूथ विस्तारक योजना को जिस तरह सफल बनाया है उससे भाजपा आलाकमान और संघ भी गदगद है। भाजपा आलाकमान अब टीम वीडी के फॉर्मूले से बूथ विस्तारक योजना को देशभर में लागू करने की कार्ययोजना बना रही है। इसका संकेत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंदौर में प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों व अन्य नेताओं की बैठक में दिए। गौरतलब है कि मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की जोड़ी देश की राजनीति में सबसे आदर्श जोड़ी बनी हुई है। सत्ता और संगठन के समन्वय से प्रदेश में कई नवाचार किए गए हैं जो आज देश में मिसाल बने हुए हैं। इसी में से एक है बूथ विस्तारक योजना। टीम वीडी के इस नवाचार को भाजपा पूरे देश में लागू करना चाहती है।

एक आनार कई बीमार

उप्र को देखकर बनेगी मप्र कांग्रेस की रणनीति

5 राज्यों में कांग्रेस की जो हालत हुई है, उससे अब प्रदेश कांग्रेस भी सीख लेगी। चूंकि अभी विधानसभा चल रही है, इसलिए सभी नेता उसमें व्यस्त हैं। विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद कांग्रेस की एक बड़ी बैठक आयोजित की जाना है, जिसमें उप्र जैसा हाल प्रदेश में न हो, इसके लिए रणनीति तैयार की जाएगी। गत दिनों पहले कमलनाथ के निवास पर होने वाला फाग उत्सव भी निरस्त कर दिया गया है। उप्र में कांग्रेस के जो हाल हुए हैं, उसने कांग्रेस संगठन को एक बार सोचने को मजबूर कर दिया है। ऐसे समय में जब संगठन चुनाव सिर पर हैं और उसके पहले घर चलो, घर-घर चलो तथा सदस्यता अभियान के माध्यम से संगठन को मजबूत करने की कवायद की जा रही है, लेकिन पूरे प्रदेश में इन अभियानों का व्यापक असर नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के प्रभारी इन पर निगाह रखे हुए हैं। वहीं अन्य चार राज्यों में कांग्रेस की हालत को लेकर भी राष्ट्रीय स्तर पर मंथन किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में इंदौर के कद्दावर तथा मुंहफट कांग्रेस नेता कह चुके हैं कि अब आत्ममंथन या आत्मचिंतन करने की बजाय मैदानी तौर पर सक्रिय रहना होगा। ये नेता नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी बार-बार सवाल उठाते रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस जल्द ही एक बड़ी बैठक आयोजित करने वाली है, जिसमें उप्र में किस प्रकार की गलतियां हुईं और उन गलतियों को दूर करने के लिए क्या किया जाए, इस पर भी मंथन किया जाएगा ताकि मप्र में ऐसी स्थिति न आए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि महिलाओं को टिकट देकर आगे करने तथा लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा भी फ्लॉप साबित हो गया।

20 अगस्त तक कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा के साथ इस पद के लिए जद्दोजहद शुरू हो गई है। मौजूदा अध्यक्ष कमलनाथ की कोशिश है कि वे 2023 के विधानसभा चुनाव तक पद पर काबिज रहें। इसके लिए उन्हें पार्टी की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी के समर्थन का भरोसा है। वरिष्ठ नेताओं दिग्विजय सिंह, अजय सिंह एवं अरुण यादव की तिकड़ी कमलनाथ की राह का रोड़ा बन सकती है। इन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी की मदद से ये कमलनाथ को एक पद से हटा लेंगे और यह पद प्रदेश अध्यक्ष का ही होगा। लिहाजा, कांग्रेस के अंदर दोनों ओर से योजना के साथ नए अध्यक्ष को लेकर लॉबिंग, जोड़तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। कमलनाथ, अजय सिंह, अरुण यादव के अलावा सज्जन सिंह वर्मा, विवेक तन्खा, बाला बच्चन, ओमकार सिंह मरकाम, जीतू पटवारी, राम निवास रावत के नाम प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार के रूप उभर रहे हैं।

कमलनाथ कांग्रेस के वरिष्ठमत नेताओं में से एक हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस विधानसभा के पिछले चुनाव के बाद सत्ता में काबिज हुई थी। सत्ता मिलने के बाद कमलनाथ के खाते में असफलताएं ज्यादा दर्ज हुई हैं। सबसे खास यह कि वरिष्ठ होने के बावजूद वे पार्टी नेताओं को एकजुट नहीं रख पाए। इसके कारण पहले ज्योतरादित्य सिंधिया 19 विधायकों के साथ पार्टी छोड़ गए और सरकार गिर गई। कमलनाथ की कार्यशैली से नाराज होकर कुछ और विधायकों ने पार्टी छोड़ी। इससे कमलनाथ ने कोई सबक नहीं लिया और अब दिग्विजय सिंह, अजय सिंह एवं अरुण यादव जैसे नेताओं के उनसे नाराज होने की खबरें हैं। इस बीच विधानसभा के जितने भी उपचुनाव हुए उनमें कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा। यह खामी कमलनाथ के पद छोड़ने की वजह बन सकती है।

कहने के लिए दिग्विजय सिंह को संगठन चुनाव से कोई लेना देना नहीं है और वे कमलनाथ के साथ हैं, लेकिन अजय सिंह एवं अरुण यादव के साथ मिलकर अंदर ही अंदर राजनीतिक खिचड़ी पकने की भी खबरें हैं। दरअसल, मुख्यमंत्री निवास के सामने दिग्विजय सिंह के धरने के दौरान के वायरल एक वीडियो से सार्वजनिक हो चुका है कि दिग्विजय-कमलनाथ के संबंध अब पहले जैसे नहीं रहे। इसलिए यह तिकड़ी चाहती है कि कमलनाथ के स्थान पर कोई नया प्रदेश अध्यक्ष बनें। कोशिश अजय सिंह एवं अरुण यादव में से किसी एक को चुनने की है। अरुण यादव चूंकि एक बार अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए इस बार अजय सिंह के लिए ज्यादा लाबिंग हो रही है। अजय-अरुण पहले ही आपस में हाथ मिला चुके हैं। कोई व्यवधान आने पर ये ओमकार सिंह मरकाम, जीतू पटवारी जैसे किसी युवा पर दांव लगा सकते हैं।

पहले तो कमलनाथ की पूरी कोशश प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहने की है। इस मंशा के साथ वे विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर चुके हैं। बावजूद इसके यदि हालात ऐसे बने कि उन्हें अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा तो वे अपनी पसंद के किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देखना चाहेंगे। उनकी ओर से विवेक तन्खा, सज्जन सिंह वर्मा, बाला बच्चन, कमलेश्वर पटेल जैसे किसी नेता का नाम आगे बढ़ाया जा सकता है। ज्यादा कोशिश विवेक तन्खा एवं सज्जन वर्मा में से किसी को पद दिलाने की हो सकती है। ऐसी स्थिति में कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष बने रहकर संगठन को अपने तरीके से चलाते रह सकते हैं।

कमलनाथ फिलहाल मप्र कांग्रेस के अध्यक्ष के अलावा नेता प्रतिपक्ष भी हैं और मप्र में दौहरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे में अगर कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ते हैं तो इस पद के लिए मप्र में कई दावेदार हैं। जिनमें जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, अरुण यादव, अजय सिंह, बाला बच्चन, सहित कई दावेदार हैं। खास बात यह है कि इन नेताओं में कोई दिग्विजय सिंह का खास माना जाता है तो कोई कमलनाथ समर्थक है। ऐसे में अगर कमलनाथ पद छोड़ते हैं तो यह जिम्मेदारी किसे मिलेगी यह कहना फिलहाल मुश्किल है। जीतू पटवारी, अरुण यादव और अजय सिंह यह नेता दिग्विजय सिंह समर्थक माने जाते हैं। अरुण यादव कांग्रेस के दिग्गज नेता सुभाष यादव के पुत्र हैं और अजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे। अरुण यादव पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं तो अजय सिंह के पास नेता प्रतिपक्ष का लंबा अनुभव है। जबकि जीतू पटवारी मप्र में कांग्रेस का बड़ा युवा चेहरा हैं। ऐसे में ये तीनों नेता भी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में शामिल हैं। वहीं बात अगर सज्जन सिंह वर्मा और बाला बच्चन की करें, तो यह दोनों नेता कमलनाथ के समर्थक माने जाते हैं। सज्जन सिंह और बाला बच्चन कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। जबकि कांग्रेस में उनका लंबा अनुभव रहा है। ऐसे में अगर कमलनाथ पद छोड़ते हैं तो इन नेताओं की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है।

● **राकेश ग्रोवर**

2024 में चलेगी मेट्रो

ग्वालियर में मेट्रो की तैयारी

प्रदेश की राजधानी भोपाल व इंदौर के बाद अब ग्वालियर में भी मेट्रो चलाने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए एलीवेटेड फ्लाई ओवर पर मेट्रो चलाने प्रस्ताव बनाकर भोपाल भेजा गया है। हालांकि 2016-17 में भी शासन की ओर से ग्वालियर में मेट्रो चलाने के लिए प्लान बनाया गया था। लेकिन बाद में राज्य सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। इसके लिए शहर में फिजिबिलिटी सर्वे भी कराया गया था, इसमें मेट्रो रेल को ग्वालियर में चलाए जाने के लिए उपयुक्त नहीं मना गया था, लेकिन अब एलीवेटेड रोड की मंजूरी मिलने के बाद एलीवेटेड फ्लाई ओवर रोड पर मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए एक प्रस्ताव बनाकर भोपाल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार इसके लिए जल्द ही ग्वालियर में टीम जाकर फिजिबिलिटी सर्वे करेगी। यदि सब कुछ अच्छा रहा तो जल्द ही ग्वालियर को मेट्रो की सौगात भी मिल जाएगी। फ्लाईओवर पर मेट्रो ट्रेन चलाने को स्वीकृति मिलती है तो प्रोजेक्ट की लागत करीब दो गुना तक पहुंच जाएगी। अभी ग्वालियर में बनने वाले एलीवेटेड लिए पीडब्ल्यूडी सेतु संभाग द्वारा ट्रिपल आईटीएम से फूलबाग तक 5.7 किमी दूरी पर करीब 446 करोड़ की डीपीआर तैयार की गई है और फूलबाग से एबी रोड तक 8 किमी रोड के लिए लगभग 600 करोड़ की डीपीआर तैयार की जा रही है। भेजे गए प्रस्ताव के बाद प्लानिंग में जुटे अधिकारियों द्वारा डीपीआर तैयारी के साथ ही एलीवेटेड रोड पर मेट्रो ट्रेन चलाने की प्लानिंग शुरू हो गई है और रोड के पिलरों को रेल के हिसाब से डिजाइन करने व लागत के अनुसार डीपीआर बदलने पर कार्य शुरू कर दिया गया है।

राजधानी में मेट्रो परियोजना का काम वर्ष 2018 में शुरू किया गया है। एम्स से सुभाष नगर तक पहली लाइन के लिए 80 फीसदी हिस्से में पिलर खड़े कर उन पर गार्डर लांच किए जा चुके हैं। इसके बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि अब तक इस प्रोजेक्ट का चार फीसदी काम ही हो पाया है। इस पर करीब 500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। हालांकि आगामी दो महीने भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए अहम होंगे। निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए 2500 करोड़ रुपए के तीन टेंडर अप्रैल माह में जारी कर दिए जाएंगे।

बता दें कि अभी भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में 8 किलोमीटर, एम्स से सुभाष नगर तक पिलर व रेलवे लाइन डालने का काम किया जा रहा है। इसके बाद सुभाष नगर से करोंद चौराहा तक करीब 7 किलोमीटर की अंडर ग्राउंड लाइन डाली जाएगी। वहीं दूसरे चरण में रत्नागिरी चौराहा से भदभदा तक करीब 12 किलोमीटर का रूट बनाने का काम होगा। सरकार ने इस रेल प्रोजेक्ट के तहत दो रूटों पर मेट्रो संचालन वर्ष 2024 में शुरू करने का लक्ष्य रखा है। इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ष 2022 अहम साबित हो सकता है। आगामी दो महीनों में इसमें करीब 2500 करोड़ रुपए से काम शुरू होंगे। इसमें मेट्रो ट्रेन के संचालन एवं रखरखाव, सिग्नलिंग, ट्रेन नियंत्रण और दूर संचार प्रणाली, रेलवे ट्रैक पर पावर सप्लाई और मेट्रो रेल के लिए डिपो के लिए टेंडर जारी किया जाना है। अधिकारियों का कहना है कि पहले चरण में एम्स से लेकर सुभाष नगर तक 8 किलोमीटर के रूट का सिविल वर्क मार्च आखिरी तक पूरा कर लिया जाएगा।

राजधानी में मेट्रो संचालन को लेकर साल 2024 तक की समयसीमा निर्धारित की गई थी। लेकिन कोरोनाकाल में लॉकडाउन व रास्ते से अतिक्रमण नहीं हटने की वजह से काम काफी पिछड़ गया है। अधिकारियों का कहना है कि 2024 तक पहले चरण में मेट्रो का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए एम्स से सुभाष नगर तक कर्षण एवं बिजली आपूर्ति के लिए 700 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इसमें मेट्रो के लिए सब स्टेशन भी बनाने का प्रविधान है। इसके साथ ही 1300 करोड़ रुपए से रोलिंग स्टॉक का काम होगा। इससे रूट में ट्रेन नियंत्रण एवं दूर संचार प्रणाली का विस्तार किया जाएगा।

एम्स से सुभाष नगर अंडरब्रिज तक 8 मेट्रो स्टेशन बनेंगे। इनमें एम्स, अलकापुरी, डीआरएम ऑफिस, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, डीबी सिटी, एमपी नगर जोन-1, आयकर भवन और सुभाष नगर अंडरब्रिज शामिल हैं। 2022 के आखिरी महीने तक इन स्टेशनों का निर्माण पूरा करना है। यह स्टेशन 100 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े होंगे। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और डीबी सिटी पर फुटओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को भोपाल मेट्रो से जोड़ने की योजना है। स्टेशन के ठीक सामने मेट्रो की लाइन रहेगी। पिलर का काम करीब पूरा हो गया है। ऊपर के स्लैब लगते ही रानी कमलापति स्टेशन से मेट्रो लाइन कनेक्ट हो जाएगी।

सुभाष नगर अंडर ब्रिज के पास स्थित आजाद नगर बस्ती को शहर के दूसरे स्थान पर विस्थापित किया जाएगा। यहां अतिक्रमण होने से मेट्रो प्रोजेक्ट में अभी रुकावट आ रही है। यहां करीब ढाई एकड़ जमीन पर मेट्रो ट्रेन के लिए डिपो तैयार होगा। इसमें चार मेट्रो खड़ी करने की क्षमता होगी। अप्रैल में इसके लिए टेंडर जारी होंगे। तीन साल में निर्माण एजेंसी को यहां डिपो तैयार करना होगा। शहर के तीन स्थानों पर ऑल इंडिया रेडियो के पास, करोंद में केंद्रीय कृषि संस्थान और सुभाष नगर फाटक स्थित डिपो की जमीन पर बिजली का सब स्टेशन बनाया जाना है।

भोपाल-इंदौर मेट्रो परियोजना की एमडी छवि भारद्वाज का कहना है कि साल 2024 तक भोपाल में मेट्रो का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए एम्स से करोंद तक करीब 15 किलोमीटर के प्रायोरिटी रूट पर अभी काम चल रहा है। इसमें एम्स से सुभाष नगर तक 8 किलोमीटर का सिविल वर्क अप्रैल माह में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद रोलिंग स्टॉक, ट्रेन सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रैक्शन एंड पावर सप्लाई और डिपो के निर्माता के लिए टेंडर जारी होंगे। मई में ये सभी काम शुरू कर दिए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक एजेंसियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं।

● **विकास दुबे**

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मप्र के जन-जन को खुशहाल बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए उन्होंने आत्मनिर्भर मप्र का सपना संजोया है। मुख्यमंत्री के सपने को साकार करने के लिए सरकार ने वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया है। 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ रुपए के बजट में हर वर्ग की खुशहाली का ध्यान रखा गया है। इस बजट से अब मप्र आत्मनिर्भर बनेगा।

मिशन 2023 पर फोकस

वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने मप्र के संतुलित विकास के लिए 2022-23 का ऐसा बजट पेश किया है, जिसे देशभर में सराहा जा रहा है। मप्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में सारे प्रावधान शामिल किए गए हैं। जानकारों का कहना है कि यह बजट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सपनों को साकार करेगा। बजट में सभी वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है। बजट की खास बात यह रही कि इस बार कोई भी **नया टैक्स** नहीं लगाया गया है। न ही कोई टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है। बजट में किसी धार्मिक-सांस्कृतिक एजेंडे के बजाय अनुसूचित जाति, जनजाति जैसे विस्तृत सामाजिक वर्गों के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे बड़े सेक्टरों पर फोकस रखा गया है। गौरतलब है कि मप्र का अगला विधानसभा चुनाव वर्ष 2023 के उत्तरार्ध में होगा। जाहिर है, राज्य सरकार को चुनाव से ठीक पहले अगले वर्ष एक और बजट पेश करने का अवसर मिलेगा। यद्यपि इस वर्ष के बजट में भी ठोस कार्यक्रमों की योजना से संकेत मिलता है कि सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल की उपलब्धियों के बल पर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति को अप्रत्याशित महत्व देकर शिवराज सरकार ने कांग्रेस की रीढ़ पर तगड़ा प्रहार किया है। इस रणनीति के जरिए यदि भाजपा इन वर्गों को आकृष्ट करने में सफल होती है, तो अगले चुनाव की दृष्टि से इसे उसका मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है।

मप्र देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा- बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास पर ध्यान देना जरूरी है। इसलिए पहली बार चाइल्ड बजट लाया जा रहा है। इसके जरिए बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सकेंगी। अभी तक 17 विभागों में बच्चों के लिए चल रही योजनाओं को चिन्हित किया गया है। इनमें चलने वाली योजनाओं को पहली बार एक साथ लिया गया है। सरकार ने बजट में इसके लिए 57 हजार 800 रुपए का प्रावधान किया है। यूनिसेफ की गाइडलाइन के अनुसार 18 साल से कम उम्र को चाइल्ड माना गया है। चाइल्ड बजट को महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत ही रखा गया है। बजट में कहा गया है कि प्रदेश में जो भी योजनाएं 0 से लेकर 18 से **कम उम्र के बच्चों** के लिए चल रही हैं, अब उनका अलग से बजट होगा। जैसे पार्क, आंगनबाड़ी, स्कूल, एजुकेशन और खेलकूद पर होने वाला खर्च इसमें शामिल होगा। इससे सरकार यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि सरकार बच्चों पर कितना खर्च कर रही है और उसका रिजल्ट क्या है। अभी यह 17 अलग-अलग विभागों में बंटा हुआ था।

चाइल्ड बजट में खेल एवं युवक कल्याण

शिवराज की सोच का रोडमैप

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की तमाम लोकप्रियता के बावजूद वर्ष 2018 में हुए मप्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को पछाड़ दिया था। उस वक्त इसकी दो मुख्य वजहें मानी गई थीं। पहली, कांग्रेस द्वारा किसानों की कर्जमाफी की घोषणा, और दूसरी कांग्रेस के परंपरागत अनुसूचित जाति-जनजाति वोटबैंक का पार्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहना। कांग्रेस के आंतरिक कारणों से सिर्फ 15 महीने बाद कमलनाथ सरकार गिर जाने पर जब शिवराज सिंह एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुए, तो उन्होंने चुनाव परिणाम से सबक लेते हुए किसानों की खुशहाली और अनुसूचित जाति-जनजाति की बेहतरी पर विशेष ध्यान दिया। सरकार के बजट में मुख्यमंत्री की इसी सोच-रणनीति का रोडमैप साफ नजर आता है। भाजपा नेतृत्व, खासकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को अच्छी तरह पता है कि करीब डेढ़ वर्ष बाद जब भाजपा मप्र के चुनाव मैदान में उतरेगी तब कांग्रेस के साथ सीधे मुकाबले में सरकार की उपलब्धियां कसौटी पर होंगी। मप्र में कांग्रेस की स्थिति अधिकतर अन्य प्रदेशों के विपरीत कुछ बेहतर है क्योंकि यहां क्षेत्रीय दलों की नामौजूदगी के चलते मतदाताओं के समर्थन का ध्रुवीकरण भाजपा और कांग्रेस पर ही केंद्रित रहेगा। ऐसे में समय रहते कांग्रेस समर्थक वोटबैंक को अपने पाले में लाने की रणनीति को शिवराज सरकार का राजनीतिक चातुर्य माना जाना चाहिए।

विभाग, श्रम विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, संस्कृति, पर्यटन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, महिला एवं बाल विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, ग्रामीण विकास व घूमन्तू और अर्द्धघूमन्तू जनजाति विभागों में बच्चों के लिए योजनाएं हैं।

वित्तमंत्री देवड़ा ने कहा- कोविड के समय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आव्हान से प्रेरित होकर हमारी सरकार ने आत्मनिर्भर मप्र का रोडमेप 2023 तैयार किया। इस रोडमैप के तहत प्रदेश के विकास की परिकल्पना के चार प्रमुख आधार स्तंभ हैं। पहला भौतिक अधोसंरचना, दूसरा अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, तीसरा स्वास्थ्य एवं शिक्षा तथा चौथा सुशासन। सरकार के इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 17 हजार करोड़, फसल उपार्जन में लगभग 66 हजार 684 करोड़, शून्य प्रतिशत दर पर फसल ऋण लगभग 30 हजार करोड़ दिया है। यह बजट आत्मनिर्भर मप्र का संकल्प है। सरकार पूरी तरह से अन्नदाताओं के साथ है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर में पहुंची है। 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था, 21 हजार करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी दी गई। 2500 करोड़ बिजली सब्सिडी देने का प्राविधान। इस साल 4000 किमी सड़के बनाने का लक्ष्य। अटल प्रगति पथ का काम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मंशानुसार बजट में कन्यादान और लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण शुरू करने की बात कही गई है। इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्वसहायता समूहों को आसानी से लोन मिल सके, इसके लिए उन्हें नए क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा। इससे प्रदेश की 2 करोड़ 58 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स को साधे रखने की कोशिश की गई है। प्रदेश में 41 लाख से भी अधिक लाडली लक्ष्मियां हैं। एनएचएफएस-5 सर्वे के अनुसार मप्र में जन्म के समय प्रति हजार बेटों

पर बेटियों की संख्या बढ़कर 956 हो गई है। लाडली लक्ष्मी योजना में लगभग 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, तीर्थ दर्शन योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने इसे बंद कर दिया था। भाजपा सरकार इसे फिर से लागू करेगी और 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थयात्रा कराएगी।

प्रदेश में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि एक साल में 6 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हुए हैं। इसको लेकर विपक्ष, सरकार को घेर रहा है। प्रदेश में युवा वोटर्स की संख्या 1 करोड़ 77 लाख से ज्यादा है। इस वर्ग की नाराजगी को दूर करने के लिए 60 हजार नौकरियां देने की बात कही गई है। बजट में 13 हजार शिक्षकों की भर्ती की बात कही गई है। 6 हजार कॉन्स्टेबल की भर्ती के साथ प्राइवेट सेक्टर में 41 हजार नौकरियों का वादा बजट में किया गया है। पढ़ने-लिखने वाले युवाओं के लिए मेडिकल और नर्सिंग की सीटें बढ़ाने के साथ 46 ब्लॉक में आईटीआई खोले जाएंगे। सिंगरौली में माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला जाएगा। नए बजट को लेकर सबसे ज्यादा खुश सरकारी कर्मचारी ही हैं। उनको मिलने वाले महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत वृद्धि की गई है। केंद्रीय कर्मचारियों की तरह उन्हें भी अब 31 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। जबकि 3 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को बड़ी राहत दी गई है, लेकिन पुरानी पेंशन लागू करने का ऐलान नहीं किए जाने से साढ़े **तीन लाख** से ज्यादा शिक्षक और अन्य विभागों के कर्मचारी सरकार से नाराज हैं। हालांकि, वित्तमंत्री ने कहा है कि मौजूदा पेंशन योजना में कुछ संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार का फोकस स्वरोजगार पर ज्यादा है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार अब उद्यम क्रांति योजना को बड़े पैमाने पर लागू करने जा रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तरह स्वसहायता समूहों के लिए लागू योजनाओं के लिए बजट में 1 हजार करोड़ से ज्यादा राशि का प्रावधान किया गया है।

● **कुमार विनोद**

दो साल से बिना उपाध्यक्ष के चल रही विधानसभा

प्रदेश की सत्ता में वापसी किए शिवराज सरकार को दो साल पूरे होने को हैं, लेकिन अब तक विधानसभा बिना उपाध्यक्ष के चल रही है। प्रदेश में विधानसभा उपाध्यक्ष नहीं होने से विधानसभा का काम प्रभावित हो रहा है। विधानसभा उपाध्यक्ष विधानसभा की पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति और विधायनी मंडल के संयोजक होते हैं। वे विधायकों की वेतन भत्ता निर्धारण समिति के सभापति होते हैं। उपाध्यक्ष का पद खाली होने से ये समितियां नहीं बन पा रही हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए विधायक केदार शुक्ला को विधायकों की वेतन भत्ता निर्धारण समिति का सभापति बना दिया है। खास बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल को हाल में एक साल पूरा हो चुका है पर उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। मप्र विधानसभा में परंपरा रही है कि अध्यक्ष का पद सत्तापक्ष का और उपाध्यक्ष विपक्ष का होता है, लेकिन कांग्रेस ने यह परंपरा तोड़ दी थी। तत्कालीन कमलनाथ सरकार के समय कांग्रेस के एनपी प्रजापति विधानसभा अध्यक्ष थे और हिना कांवरे उपाध्यक्ष थीं। ऐसे में भाजपा कांग्रेस को उपाध्यक्ष पद नहीं देना चाह रही है। इस कारण अभी तक उपाध्यक्ष का पद खाली पड़ा है।

विवादों में 632 करोड़ का टेंडर!

मप्र में डायल 100 के 632 करोड़ का टेंडर एक बार फिर विवादों में फंस गया है। विधानसभा में प्रस्तुत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कैग) के प्रतिवेदन में कहा गया कि वर्ष 2015 में आमंत्रित इस टेंडर में वरीयता क्रम में पहला बोलीदार (मेसर्स पीडब्ल्यूसी प्राइवेट लिमिटेड) चयनित हुआ था, लेकिन तकनीकी मूल्यांकन को आधार बनाकर इसे चयन से बाहर कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि डायल 100 योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए सलाहकार कंपनी के चयन में पुलिस महानिदेशक स्तर पर गड़बड़ी की गई। इससे विवाद एक बार फिर गहरा गया है।

गौरतलब है कि मप्र में डायल 100 का टेंडर शुरू से विवाद में रहा है। अब कैग की रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया है कि निर्धारित शर्त में बदलाव कर दूसरे बोलीदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। डायल 100 परियोजना के 632 करोड़ के टेंडर की प्रक्रिया दोषपूर्ण रही। इसके आधार पर मेसर्स ग्रांट थार्नटन प्राइवेट लिमिटेड पात्र हो गया। कैग ने कहा कि यह सारी प्रक्रिया दोषपूर्ण थी और दूसरे बोलीदार को अनुचित फायदा पहुंचाया गया। कैग ने राज्य सरकार के उस तर्क को भी नामंजूर कर दिया, जिसमें कहा गया था कि तत्कालीन पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने अपनी सूझबूझ से 1.19 करोड़ की बचत की। कैग ने कहा कि डीजीपी को मामले में पुनर्विचार के लिए इसे क्रय समिति को वापस करना था या नया टेंडर कराना था।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के इंटरवेशन और उद्यम संसाधन योजना समाधान सहित डायल 100 के प्रोजेक्ट के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) एवं प्रस्ताव के लिए मुंबई की मेसर्स केपीएमजी एडवाइजरी सर्विस लिमिटेड को बतौर कंसल्टेंट 6 महीने के लिए नियुक्त किया गया। इसके लिए 1 करोड़ का भुगतान भी किया गया। इसने आरएफपी का मसौदा जून 2014 में प्रस्तुत किया। लेकिन विभाग ने डीपीआर आने से पहले **सिस्टम इंटीग्रेटर** के लिए सितंबर 2014 में निविदा जारी की गई। सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन में भी अनियमितता पाई गई है। इसमें बीवीपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया था और मई 2015 में सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए ठेका दिया गया। डीपीआर बनाने के लिए तैनात की गई कंसल्टेंट कंपनी 2009-19 के दौरान विभाग द्वारा चयनित कंपनी के लेखापरीक्षक थे। लेकिन केपीएमजी ने इस हित के टकराव की जानकारी नहीं दी। शासन ने भी बात स्वीकार की और कहा कि चयन के समय केपीएमजी विभाग का सलाहकार नहीं था।

गृह विभाग ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (परियोजना प्रबंधन सलाहकार) के चयन के लिए दोबारा से निविदा जारी की। इसमें चार बिडर शामिल हुए। इसमें से दो योग्य पाए गए। केंद्रीय क्रय समिति ने मेसर्स पीडब्ल्यूसी प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दिए जाने की सिफारिश की, लेकिन डीजीपी ने तय मानदंड को स्कोर कार्ड से हटा दिया। ऐसे में 100 कुल को प्रभावी रूप से 100 से 85 कर दिया। ऐसा करने से मेसर्स ग्रांट थॉर्नटन को इसका ठेका चला गया। कैग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि डीजीपी ने बोलियों के प्राप्त होने के बाद क्वालीफाइंग क्राइटेरिया को कम करने को संदिग्ध बताते हुए दूसरी कंपनी को अनुचित लाभ दिया। वहीं, डीजीपी को महसूस हुआ कि मानदंड वैध नहीं है, तो उन्हें प्रकरण को तकनीकी मूल्यांकन के दौरान ढील देने से वापस भेजना चाहिए था या फिर क्रय समिति को दोबारा विचार करने के लिए भेजना चाहिए था। यह तर्क दिया कि डीजीपी के निर्णय से 1.19 करोड़ की बचत हुई है।

कैग ने विश्लेषण में पाया कि वर्ष 2016 से 2020 की अवधि में डायल 100 में सालाना 102.9 लाख कॉल प्राप्त हुए थे, जिनमें 20.7 लाख कॉल ही कार्रवाई के योग्य पाए गए। 82.2 लाख कॉल ब्लैंक, अनुचित या ऐसे थे जिनका पता नहीं मिल सका। विभाग को इसकी समीक्षा करके यह पता करना था कि गैर कार्रवाई योग्य कॉल के रूप में जिन्हें वर्गीकृत किया गया, वे वास्तव में गैर कार्रवाई योग्य ही थे या नहीं पर ऐसा नहीं किया गया। मिस्ड कॉल डेस्क भी स्थापित नहीं की गई। 2015 से 2020 के दौरान किसी भी मिस्ड या ब्लैंक कॉल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि ऐसे कॉल की **समीक्षा का तंत्र** स्थापित होना चाहिए। महिलाओं से संबंधित घटनाओं में डायल 100 वाहन के पहुंचने में विलंब हुआ। कैग ने निष्कर्ष निकाला कि एक वाहन प्रति पुलिस स्टेशन में उपलब्ध कराने की अवधारणा दोषपूर्ण थी क्योंकि इसमें जिलेवार अपराध, अपराधों के प्रकार, भौगोलिक स्थिति, यातायात एवं सड़क की स्थिति जैसे कारकों का ध्यान नहीं रखा गया। इसके कारण वाहन को निश्चित समय के भीतर पहुंचने में विलंब हुआ।

● **लोकेंद्र शर्मा**

सरकार की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही डायल 100

प्रदेश में किसी भी अपराध या संकट की स्थिति में चंद मिनट के भीतर पुलिस की मदद पहुंचाने की मंशा से शुरू की गई डायल 100 ने सरकार की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कैग की रिपोर्ट में डायल 100 सेवा की पोल खुल गई है। रिपोर्ट के अनुसार दुष्कर्म, घरेलू हिंसा, महिला अपहरण जैसी गंभीर घटनाओं में एफआरवी (फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल) दल घटनास्थल पर 12 घंटे देरी से पहुंची। कैग ने 2016 से 2019 के दौरान की घटनाओं को लेकर असेसमेंट किया था। डायल-100 की परिकल्पना थी कि एफआरवी दल डिस्पैचर से घटना की सूचना प्राप्त होने के बाद शहरी क्षेत्रों में 5 मिनट में और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंचेंगी। कैग ने असेसमेंट में पाया कि डायल 100 सिर्फ 13.2 प्रतिशत मामलों में ही 5 मिनट में घटनास्थल पर पहुंची। कई मामलों में गाड़ी आधे घंटे से लेकर 12 घंटे देरी से पहुंची। खास बात यह है कि 49 प्रतिशत घटनाओं में यह असेसमेंट किया गया। 51 प्रतिशत घटनाओं में डिस्पैच या एफआरवी को घटनाओं की जानकारी नहीं मिली।

46 लाख घरों तक नल से जल

प्रदेश की ग्रामीण आबादी के वे सभी ग्राम हर घर-जल ग्राम घोषित किए जा रहे हैं, जहां ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। ऐसे 4045 ग्राम हैं, जिनमें यह शुरूआत हो रही है। इन ग्रामों में अब नल के माध्यम से पेयजल मिल रहा है। इनमें 46 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार यह सुविधा पाकर हर्षित हैं। ग्रामीण माताएं और बहनें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दुआएं दे रही हैं। उनके जीवन की एक बड़ी कठिनाई तो दूर हुई, साथ ही मानव श्रम और समय की भी बचत संभव हुई है। ग्रामीण माताएं और बहनें जिन पर घर में पीने का पानी लेकर आने का दारोमदार होता है, उनके जीवन की कठिनाइयां दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की पहल जल जीवन मिशन से रंग ला रही है। मप्र में 4 हजार से अधिक ग्रामों में नल से पेयजल प्रदाय की व्यवस्था फलीभूत हुई है। इस कार्य को मजबूत संकल्प और संवेदनशील मन के साथ ही किया जा सकता था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल कर बीते 2 वर्ष में अनेक बार जल जीवन मिशन के कार्यों की जानकारी ली और नियमित बैठकें कर कार्य प्रगति की समीक्षा की। सामने आई कमियों को दूर करने की हिदायत दी और अच्छे परिणाम लाने के लिए अमले को प्रोत्साहित भी किया। इसके फलस्वरूप मप्र मिशन के कार्यों में देश में अग्रणी है।

मप्र जल जीवन मिशन के कार्यों में यूं ही अग्रणी नहीं है। इसके लिए यहां सतत् समीक्षा का कार्य मुख्यमंत्री स्तर पर हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की शहरी और ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने पर जोर देते रहे हैं। उनका कहना है कि आत्मनिर्भर मप्र के लिए निर्मित रोडमैप में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रदेश में समस्त नलजल योजनाओं के कार्य संपन्न होना जरूरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजनाओं के बेहतर संधारण के लिए ग्राम इंजीनियर पदस्थ करने को कहा है। उन्होंने वृहद परियोजना के कार्यों में समय पर कार्यों की पूर्णता के लिए संबंधित एजेंसी और अधिकारी-कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विलंब से होने वाले कार्यों पर जिम्मेदारी तय कर दोषियों के विरूद्ध सख्त कदम उठाए जाएं। नलजल योजनाओं का कार्य पूर्ण होने पर ग्रामों में विशेष ग्राम सभा आयोजित कर ग्राम को हर घर जल ग्राम श्रेणी का ग्राम घोषित किया जाए। योजना के निर्माण कार्य पूरे होने पर संबंधित पंचायत को योजना हस्तांतरित की जाए। ग्राम जल और स्वच्छता समिति के पदाधिकारी ग्रामवासियों से जन-संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसी महत्वाकांक्षी और उपयोगी योजना लागू करने के लिए ग्रामवासियों द्वारा आभार-पत्र भी भेजे जाएंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मानना है कि ग्राम स्तर पर ऐसे ग्रामीण इंजीनियर को तैनात किया जाए जो विद्युत कनेक्शन, पेयजल प्रदाय व्यवस्था, सिंचाई पम्पों से संबंधित प्रबंध, आवास निर्माण के तकनीकी पहलुओं आदि की जानकारी रखता हो। पम्प और वाल्व ऑपरेटर का प्रशिक्षण कुछ ही दिनों में दिया जा सकता है। बेरोजगार युवाओं को इन कार्यों के लिए तीन से छह माह के छोटे प्रशिक्षण कोर्स का लाभ दिलवाकर ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना और अन्य योजनाओं में मेंटेनेंस का दायित्व सौंपा जाए। मप्र में इस क्षेत्र में एक मॉडल तैयार कर उसके क्रियान्वयन की पहल की जाए। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग नोडल विभाग की भूमिका का निर्वहन करे। बड़े ग्रामों में एक से अधिक युवक भी यह जिम्मेदारी वहन कर सकते हैं।

मप्र में मार्च 2021 तक ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन द्वारा जल प्रदाय की उपलब्धता 30.55 प्रतिशत हो गई, जो वर्तमान में 37.10 प्रतिशत है। विभिन्न नलजल योजनाओं पर 42 हजार 643 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो रही है। गत वित्त वर्ष में 26 लाख घरों तक पेयजल कनेक्शन के लक्ष्य के विरूद्ध करीब 20 लाख घरों में नल कनेक्शन दिए गए, जो लक्ष्य का तीन चौथाई है। वर्ष 2024 तक मप्र के सभी लगभग 122 लाख ग्रामीण परिवारों तक पेयजल उपलब्धता के **लक्ष्य के मुकाबले** गत दिसंबर तक 45 लाख 10 हजार परिवारों तक पेयजल उपलब्ध करवाया जा चुका था। अभी यह संख्या 46 लाख से अधिक हो गई है। अगले तीन माह में 52 लाख 62 हजार परिवारों तक पेयजल उपलब्ध होगा।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

50 हजार मैकेनिक हो रहे तैयार

नल और बिजली से जुड़े मरम्मत कार्यों के लिए 50 हजार मैकेनिक प्रशिक्षित करने की योजना है। इस लक्ष्य पूर्ति के लिए मप्र राज्य कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड के माध्यम से आईटीआई और अन्य संस्थाएं प्रशिक्षण प्रारंभ कर चुकी हैं। जल जीवन मिशन में ग्राम और एफएचटीसी (फंक्शनल हाउस होल्ड टेप कनेक्शन) कार्य-योजना में 25 हजार 399 ग्रामों की समूह नल जल योजनाओं में से 9 हजार 351 कार्य प्रगति पर हैं। कुल 26 हजार 186 ग्रामों की एकल ग्राम नल जल योजना में 8 हजार 176 कार्य प्रगति पर हैं। यह व्यवस्था भी की गई है कि योजना के क्रियान्वयन के लिए सड़क खुदाई की अनुमति के लिए कांट्रेक्टर जल निगम के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेगा। यह अनुमति अलाइनमेंट परीक्षण के बाद प्रदान की जाएगी और उसके बाद ही कांट्रेक्टर रोड कटर का उपयोग करेगा। पाइप लाइन डालने के बाद कांट्रेक्टर द्वारा सड़क की आवश्यक मरम्मत करवाई जाएगी। सड़क को पूर्वास्था में लाने के लिए योजना की डीपीआर में प्रावधानित राशि का भुगतान किया जाएगा।

नक्सली बनेंगे पुलिस के मददगार

देश के हृदय प्रदेश मप्र के आधा दर्जन से अधिक जिलों में नक्सली सक्रिय हैं, लेकिन अभी तक वे घातक सिद्ध नहीं हुए हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार की कोशिश है कि नक्सलियों को मुख्य धारा में लाया जाए, साथ ही उनकी सहायता लेकर अन्य नक्सलियों का आत्मसमर्पण कराया जाए।

मप्र को नक्सल मुक्त बनाने के लिए सरकार ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण की नीति बनाई है। इस नीति के तहत नक्सलियों को आत्मसमर्पण करवाकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। साथ ही आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुलिस का मददगार बनाकर प्रदेश को नक्सलमुक्त करने का अभियान चलाया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस नीति से प्रदेश में सक्रिय नक्सलियों को आत्मसमर्पण करवाने में सफलता मिलेगी।

जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार ने आत्मसर्मपण को लेकर जो नीति तैयार की है, वह छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से अलग है। बताते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। पुलिस मुख्यालय ने मसौदा तैयार कर गृह विभाग को भेज दिया है। जल्दी इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में पेश किया जाएगा। नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराकर उनके राहत और पुनर्वास का इंतजाम सरकार की ओर से किया जाएगा।

नक्सल प्रभावित अन्य राज्यों की तरह प्रदेश सरकार ने नक्सलियों और माओवादियों को मुख्य धारा में लौटाने के लिए आत्मसमर्पण नीति बनाई है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुलिस से जोड़ा जाएगा और उनसे मददगारों की जानकारी हासिल की जाएगी। मसलन, हथियार कहां से आते हैं, फंडिंग कहां से होती है, किस मार्ग से नक्सलियों का आना-जाना होता है, बड़े ईनामी नक्सली को सरेंडर कराने अथवा पकड़वाने में मदद करते हैं, तो ऐसे माओवादियों को इंटेलीजेंस में रखा जाएगा। उन्हें पुलिस में भर्ती भी किया जाएगा।

सूत्रों की मानें तो पिछले 5 साल में एक भी नक्सली ने प्रदेश में आत्मसमर्पण नहीं किया है। लिहाजा प्रदेश के बालाघाट, डिंडोरी और मंडला में नक्सलियों का मूवमेंट बढ़ा है। तीनों जिलों में नक्सलियों की मदद करने वाले बढ़े हैं। बहुत सारे तो नक्सलियों के साथ हो गए हैं। प्रदेश में आत्मसमर्पण नीति नहीं होने के कारण संख्या में इजाफा हुआ और नक्सलीगढ़ बनना शुरू हो गया है। नक्सलियों की जो गतिविधियां बालाघाट तक सीमित थी, वे अब मंडला और डिंडोरी तक पहुंच गई हैं। 5 साल में एक भी नक्सली ने मप्र में आत्मसमर्पण नहीं किया है।

मप्र में आत्मसपर्मण नीति के अभाव में पिछले एक साल में अन्य राज्यों में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। बता दें कि मप्र के सात ईनामी माओवादियों ने महाराष्ट्र में आत्मसमर्पण किया था, जिन पर 31 लाख 50 हजार रुपए का इनाम था। इसी के चलते प्रदेश सरकार ने यह नीति बनाने का फैसला किया है। मप्र में कोई शीर्ष माओवादी नेता नहीं है। इसलिए केवल निचले कैडर वाले आत्मसमर्पण कर सकते हैं। शीर्ष नेता ज्यादातर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में हैं।

सरेंडर करने वाले अविवाहित माओवादियों को शादी के लिए 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर और खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन दिया जाएगा। पुलिस की मदद करने वाले नक्सलियों को एसपी अपने जिलों में आरक्षक के पद पर भर्ती कर सकते हैं। नक्सलियों द्वारा मारे गए लोगों के परिवार को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि माओवादी विरोधी अभियानों में मारे गए सुरक्षाकर्मियों के परिवार 20 लाख की राहत राशि प्रदान की जाएगी। सजा के बाद जेल में बंद नक्सलियों को साल में तीन बार 15-15 दिन के लिए पैरोल पर छोड़ा जाएगा।

● **अरविंद नारद**

पुनर्वास की बेहतर व्यवस्था

नक्सलियों के पत्र और हथियार के हिसाब से उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। मसलन, अगर कोई नक्सली बड़े हथियार, एसएलआर, एके-47 जैसे हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करता है, तो उसे 5 लाख रुपए तक देने का प्रावधान किया गया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति भी बन रही है। इसमें कहा गया है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के निवास के लिए सुरक्षित स्थान पर मकान बनाने के लिए आवश्यक राशि दी जाएगी। नक्सलियों की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार शासकीय सेवा अथवा सुरक्षित स्थान पर कृषि योग्य भूमि और स्वयं का व्यवसाय चलाने के लिए प्रशिक्षण एवं आवश्यक लागत राशि भी प्रदान की जाएगी। पुनर्वास के लिए राहत राशि 5 लाख से 12 लाख रुपए तक दिए जाने का प्रावधान है। नक्सली आत्मसमर्पण के योग्य है या नहीं? यह तय करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर समिति बनाई जाएगी। आत्मसमर्पण करने वालों को 5 लाख रुपए अथवा उनकी गिरफ्तारी पर ईनाम के बराबर राशि (जो भी अधिक हो) दी जाएगी। यदि कोई नक्सली सरेंडर करने के बाद व्यावसायिक जिंदगी जीना चाहता है, तो उसकी पढ़ाई के लिए 36 महीने तक 6000 रुपए दिए जाएंगे।

करोड़ों खर्च फिर भी सुरक्षित नहीं बाघ

मार्च माह के शुरू में पेंच टाइगर रिजर्व के मोगली अभयारण्य में एक बाघिन का शव मिला। बाघिन की उम्र एक साल बताई गई। बाघिन की मौत का कारण बाघों के आपसी संघर्ष को बताया जा रहा है। हालांकि वन विभाग मौत के कारणों का पता लगाने में जुटा है। प्रदेश में लगभग हर माह बाघ की मौत आम बात होती जा रही है। कभी आपसी संघर्ष, कभी शिकार तो कभी दुर्घटना में बाघों की मौत हो रही है। वह भी उस स्थिति में जब सरकार बाघों के संरक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। आलम यह है कि बाघों का घर कहे जाने वाले मप्र में बीते एक दशक में 254 से ज्यादा बाघों की अलग-अलग कारणों से मौत हो चुकी है। प्रदेश में बाघों की मौत के आंकड़ें चौंकाने वाले हैं। 2012 से 2020 तक 8 सालों में जहां प्रदेश में 202 बाघों की मौत हुई। तो वहीं, महज 2021 से अब तक 15 महीनों में ही 52 से ज्यादा बाघ दम तोड़ चुके हैं।

2010 में जब बाघों की गणना की गई थी तो देशभर में 1706 बाघ थे, जिसके बाद 2020 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। 2018 की गणना के अनुसार वर्तमान में देश में 2967 बाघ हैं, जिसमें से 526 बाघ अकेले मप्र में हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बाघों वाले राज्य में ही सबसे ज्यादा बाघों की जान भी जा रही है। बाघों की मौत के पीछे आपसी संघर्ष, बीमारी और शिकार जैसी वजहें भी शामिल हैं। अलग-अलग कारणों के चलते ही प्रदेश में एक दशक के भीतर ही 254 से ज्यादा बाघों की मौत हुई है। बाघों की मौत का मुद्दा बीते साल विधानसभा में भी उठ चुका है।

मप्र सरकार हर साल बाघों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश में बाघ दम तोड़ रहे हैं। राज्य सरकार ने 2018-19 में बाघों के संरक्षण, सुरक्षा और निगरानी में 283 करोड़ रुपए, 2019-20 में 220 करोड़ और 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः 264 करोड़ और 128 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। राष्ट्रीय पशु की सुरक्षा में करोड़ों का बजट व्यय करने के बाद भी 2017 के बाद प्रदेश में बाघों की आईडी नहीं बनी है। आईडी के जरिए ही वन विभाग बाघों की निगरानी करता है, लेकिन 2017 के बाद प्रदेश के कई टाइगर रिजर्व में बाघों की आईडी बनाने का काम बंद है। हाल ही में जारी विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले बांधवगढ़ में 50 से ज्यादा बाघ बिना आईडी के विचरण कर रहे हैं।

मप्र के बाघ संरक्षित क्षेत्रों में क्षमता से ज्यादा बाघों का होना भी मौतों का एक बड़ा कारण है। बाघों के आपसी संघर्ष और जंगल से रिहायशी इलाकों में भटकने से रोकने के लिए बाघ कॉरिडोर बनाने की जरूरत है। प्रदेश के टाइगर रिजर्व में वर्तमान में क्षमता से डेढ़ से दो गुना तक बाघ हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की क्षमता 75 बाघ की है, लेकिन यहां 124 बाघ (2018 की गणना) हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व की क्षमता 70 के मुकाबले यहां 108 बाघ हैं। यही स्थिति पेंच (82) और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (50) की है। सिर्फ संजय दुबरी टाइगर रिजर्व सीधी ही ऐसा है, जहां महज 6 बाघ हैं। कान्हा पार्क में इस साल अभी तक तीन घटनाएं बाघ के मौत की हुई हैं। जिसमें 8 फरवरी को कान्हा परिक्षेत्र कक्ष क्रमांक 106 में गश्ती के दौरान अमला ने 8 माह से शावक का तीन दिन पुराना शव देखा था, इसके बाद 17 फरवरी को किसली परिक्षेत्र कक्ष क्रमांक 633 (18) में 10 दिन पुराने बाघ का शव मिला है। तीसरी घटना हाल ही में नैनपुर से सटे अतरिया बीट में सामने आई, जहां एक मादा बाघ का शव मिला है। मादा बाघ की उम्र लगभग 2 वर्ष की बताई जा रही है, प्रबंधन द्वारा मादा बाघ की मौत का कारण कटई घास के नुकीले सिरे का शरीर में चुभने से बताया गया है। मादा बाघ के सभी अंग सुरक्षित बताए गए हैं। मौके पर मोहगांव प्रोजेक्ट की टीम ने पहुंचकर जांच और कार्रवाई की, इसके बाद पोस्टमार्टम कराकर बाघिन के शव का दाह संस्कार कराया गया। इस वर्ष तीन बाघ की मौत में दो प्रकरणों में बाघ की मौत आपसी वचर्स्व की लड़ाई बताई जा रही है।

टाइगर स्टेट मप्र में वर्तमान में 7 टाइगर प्रोजेक्ट हैं, जिनमें कान्हा किसली, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, रातापानी अभ्यारण्य शामिल हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में हैं, वहीं बंगाल टाइगर की जनसंख्या घनत्व के मामले में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व दुनिया में पहले स्थान पर है। मप्र के टाइगर रिजर्व में सैलानियों को आसानी से बाघों का दीदार हो जाता है, जिसके चलते यहां देश के साथ ही विदेश से भी पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। टाइगर रिजर्व से हर साल सरकार को अच्छी खासी आमदनी होती है।

● **जितेंद्र तिवारी**

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फिर से आबाद हुए बायसन

मप्र के प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कभी खत्म हो चुके बायसन (जंगली भैंसा) एक बार फिर इसे गुलजार कर रहे हैं। यह सफलता इंट्रोडक्शन ऑफ गौर इन बांधवगढ़ नाम के प्रयास से मिली। 12 साल पहले शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट इन दिनों अपनी सफलता के चरम पर है। इसकी शुरुआत में 49 बायसन कान्हा टाइगर रिजर्व से यहां लाए गए थे, अब इनकी संख्या 140 से ज्यादा हो चुकी है। प्रदूषण और बदलते मौसम के कारण वन्य जीवों के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव के बाद बायसन बांधवगढ़ में खत्म हो गए थे। जानकारी के अनुसार बायसन बांधवगढ़ के बड़े क्षेत्रफल में काफी विस्तारित हो गए थे और उन स्थानों तक पहुंच गए थे, जहां जंगल की परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थीं। ऐसे में बाघों व मनुष्यों द्वारा उनका शिकार होता गया और एक समय ऐसा आया कि बांधवगढ़ बायसन विहीन हो गया। वर्ष 2005 से 2010 तक यहां बायसन को पुनः बसाने पर शोध किया गया। परिणाम के आधार पर रणनीति बनी कि बायसन को अगर पूरे जंगल में अलग-अलग रहने दिया गया तो वे नहीं बचेंगे। इसके लिए कल्लवाह रेंज को चुना गया और अनुकूल परिस्थितियां तैयार कीं। कान्हा टाइगर रिजर्व से भी बायसन लाए गए। धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी। कान्हा के पूर्व रिसर्च अधिकारी डॉ. राकेश शुक्ला का कहना है कि बायसन वन्य जीवन के पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा हैं। इसमें से अगर कोई भी प्राणी या वनस्पति कम होती है तो तंत्र प्रभावित होता है।

चंबल में दिखीं महिला डकैत

चंबल में एक बार फिर डकैत गिरोह ने दस्तक दी है। गिरोह में दो लेडी डकैत समेत 11 पुरुष हैं। ये लेडी डकैत जींस और शर्ट पहनती हैं। भिंड के एक किसान का सामना इस गिरोह से हो गया। वे किसान को उठाकर ले गए। जब किसान गिरोह के साथ चलने में असमर्थ रहा तो डकैत उसे छोड़कर आगे बढ़ गए। यह सूचना मिलने पर अटेर पुलिस दो घंटे बाद मौके पर पहुंची। पुलिस ने रात में फिर दिन भर सर्चिंग ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। मामला शुक्लपुरा गांव का है।

55 वर्षीय किसान लल्लूराम शाक्य गत दिनों पहले रात करीब साढ़े सात बजे अपने खेत में पहुंचा। यहां उसे दो युवक मिले। वे हथियारों से लैस थे। उन्होंने किसान को अपने साथ चलने को कहा। आगे चलकर दो महिला जींस-शर्ट पहने हुए 9 हथियारबंद डकैतों के साथ मिलीं। वे किसान को अपने साथ ले जाने लगे। कुछ दूर चलने पर पैरों से कमजोर किसान चलने में असमर्थता जाहिर करने लगा। गिरोह उसे तीन खेत आगे तक बीहड़ की ओर ले गए। जब किसान चल ही नहीं पाया तो डकैत उसे छोड़कर आगे बढ़ गए।

हालांकि, गिरोह के सदस्यों ने किसान के साथ कोई मारपीट या फिर अन्य तरह की पूछताछ नहीं की। गिरोह से मिलने के बाद भयभीत हो चुका किसान सीधे गांव में आया और अपने रिश्तेदार रामसेवक शाक्य को आपबीती सुनाई। इसके बाद यह जानकारी सरपंच पति और उसके भाजपा मंडल अध्यक्ष को लगी। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। रात करीब साढ़े नौ से दस बजे के बीच पुलिस फोर्स गांव पहुंची।

किसान लल्लूराम के बेटे शिव सिंह का कहना है कि खेत पर फसल खड़ी हुई है। फसल और ट्यूबवेल की रखवाली के लिए पिताजी हर रोज खेत पर सोने जाते थे। वे उस दिन भी सोने गए थे। दो घंटे देरी से पुलिस आई। पिताजी ने घर आकर पूरे मामले की जानकारी दी थी। शिव सिंह का कहना है कि गांव में इससे पहले भी दो बार फायरिंग हो चुकी है। ये गिरोह पहले भी लोगों को मिल चुका है। इस सूचना के बाद रात में पुलिस पहुंची। इस दौरान गोरमी फूप, सुरापुरा और अटेर का पुलिस बल पहुंच गया। अटेर एसडीओपी द्वारा किसान लल्लूराम के बयान लिए गए। इसके बाद पुलिस ने रात में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। दिन में भी पुलिस बीहड़ों में सर्चिंग अभियान चलाती रही। करीब आठ से दस किलोमीटर दूर तक सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा।

गौरतलब है कि चंबल के बीहड़ों में 5 महिला डाकू ऐसी रही हैं जिनसे पुलिस भी डरती थी। चंबल की पहली महिला डाकू पुतली बाई को माना जाता है। पुतली का असली नाम गौहरबानो था। उसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। बड़ी हुई तो नाच-गाने करने लगी। एक बार मशहूर डाकू सुल्ताना की उस पर नजर पड़ी। वह उसे बीहड़ में नाचने के लिए बुलाने लगा। दोनों में इश्क हुआ। यहीं से वह डकैत बन गई। सुल्ताना की मौत के बाद पुतलीबाई गिरोह की सरदार बन गई थी। पचास के दशक में उसका खूब आतंक था। बीहड़ में सबसे कुख्यात डाकू फूल देवी को माना जाता है। फूलन के साथ गैंगरेप हुआ था। इसका बदला लेने के लिए वह डाकू बनी थीं। उसने कानपुर देहात जिले के बेहमई गांव में राजपूत समाज के 22 लोगों को सरेआम गोलियों से भून दिया था। वर्ष 1983 में फूलन देवी ने सरेंडर कर दिया था। सपा के टिकट पर उसने मिर्जापुर से दो बार लोकसभा चुनाव लड़ा और वह सांसद रहीं। वर्ष 2001 में फूलन देवी की दिल्ली में उनके सरकारी आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई।

डाकू लाला राम और डाकू कुसुमा नाइन ने 13 साल की उम्र में सीमा परिहार को अगवा कर लिया था। बीहड़ में रहने के दौरान सीमा को डकैतों ने की जीवन शैली इतनी पसंद आई कि उसने भी डाकू बनने की ठान ली। युवा होने के बाद सीमा परिहार का नाम चंबल में आतंक बन गया था। सीमा पर कई लोगों की हत्या और अपहरण का मामला दर्ज हुआ। उसने वर्ष 2000 में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। सालों पहले वह चर्चित टीवी शो बिग बॉस में भी दिखाई दी थी। बीच में चुनाव लड़ने की भी तैयारी की थी। कुसमा नाइन बीहड़ की फूलदेवी के बाद सबसे बेरहम डाकू थी। कहा जाता है कि कानपुर देहात के बेहमई कांड का बदला लेने के लिए उसने 14 मल्लाहों को मौत की नींद सुला दिया था। उसने संतोष और राजबहादुर नामक दो मल्लाहों की आंखें निकालकर बेरहमी की नई इबारत लिख दी थी। रेणु का जन्म का ओरैया जिले के जमालीपुर गांव में हुआ था। स्कूल से लौटते समय 29 नवंबर 2003 को डाकू चंदन यादव के गिरोह ने उसे अगवा कर लिया था। परिवार से फिरौती मांगी गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। वह डकैतों के साथ रहने लगी और खुद डकैत बन गई। चंबल के बीहड़ में वो डाकू चंदन यादव के साथ रही थी। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण और डकैती के कई मामले दर्ज थे। बाद में उसने इटावा में समपर्ण कर दिया था।

● **बृजेश साहू**

गांव में दहशत फैली

सरपंच पति छोटे सिंह भदौरिया का कहना था कि गांव में हथियारों से लैस बदमाशों के घूमने की अब तक खबरें आ रही थीं। अब गांव के किसान को ये बदमाश मिल चुके हैं। गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। किसान को बदमाश मिलने पर पुलिस द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया गया। किसान लल्लूराम ने सभी को बताया कि दो महिला समेत 11 लोगों का गिरोह था। एएसपी कमलेश खरपुसे का कहना है कि बदमाश आने की खबर आई थी। पुलिस ने किसान के बयान लिए। रात में सर्चिंग कराई गई। दिनभर सर्चिंग चली, लेकिन अब तक कोई मूवमेंट और साक्ष्य नहीं मिले।

पानी संकट को लेकर गोलबंदी शुरू

बुंदेलखंड कभी पानीदार इलाका हुआ करता था, मगर वक्त गुजरने के साथ यहां की पहचान ही सूखा, पलायन और गरीबी बन गई है, इसकी बड़ी वजह यहां की जल संरचनाओं के दफन होने के अलावा सरकार और समाज की बेरुखी रही है। इस इलाके की पानी संबंधी समस्या के निदान के लिए तमाम योजनाएं आईं, करोड़ों का बजट मिला, मगर हालात नहीं बदले। यही कारण है कि हर साल गर्मी के मौसम में वही नजारे देखने को मिलते हैं जो वर्षों पहले से देखने को मिलते रहे हैं। यह बात अलग है कि कागजी तौर पर बदलती तस्वीर दिखाने की खूब कोशिशें चलती रहती हैं।

बुंदेलखंड उप्र और मप्र के सात-सात जिलों को मिलाकर बनता है, यह वह इलाका हैं जहां नदियों से लेकर जल संरचनाओं की भरमार है। बेहतर प्रबंधन के अभाव और इन जल संरचनाओं के सुनियोजित तरीके से खत्म करने की साजिश ने आमजन को सालभर पानी उपलब्ध कराने के तमाम रास्तों को ही बंद कर दिया। इस इलाके में तमाम सरकारी योजनाओं-परियोजनाओं से लेकर अन्य **दानदाता संस्थाओं** द्वारा दी गई राशि से यहां की तस्वीर बदलने की मुहिम लगातार जारी है, मगर हालात नहीं बदले, अब पहली बार यहां के सियासी, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग गोलबंद हुए हैं। यह सभी मिलकर मंदाकिनी नदी के संरक्षण का अभियान शुरू कर रहे हैं। मंदाकिनी वह नदी है जिसके तट पर चित्रकूट में भगवान श्रीराम ने वनवास काल का लंबा कालखंड गुजारा था।

मंदाकिनी नदी के संरक्षण के लिए बुंदेलखंड के राजनीतिक, सामाजिक और धर्म जगत से जुड़े लोग एक मंच पर आए हैं। अब वे 22 मार्च से एक यात्रा शुरू करने वाले हैं। 30 मार्च तक चलने वाली इस यात्रा में नदी की वास्तविक स्थिति का आंकलन किया जाएगा, अतिक्रमणों के साथ नदी में आ रही गंदगी के स्थानों को भी चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद अभियान शुरू होगा। इस अभियान से जुड़े शोध छात्र रामबाबू तिवारी का कहना है कि बुंदेलखंड में पानी माफियाओं ने पानी के नाम पर सरकारी योजनाओं से लेकर विभिन्न माध्यमों से आने वाले बजट की लूट के अलावा कुछ नहीं किया है। सब का ध्यान प्रोजेक्ट पर होता है। अब बगैर किसी सरकारी फंड के नदी को संरक्षित करने की कोशिशें शुरू हो रही हैं। यह अभियान पूरी तरह जनता का अभियान होगा, जब तक जल योद्धा घर-घर में पैदा नहीं होंगे, तब तक बुंदेलखंड को पानीदार बना पाना मुश्किल काम होगा।

जानकारों की माने तो बुंदेलखंड के लगभग हर गांव में एक जल संरचना हुआ करती थी, यहां के लोगों ने पहले कभी यह जाना ही नहीं था कि पानी का भी संकट होता है, मगर अब तो यहां की पहचान ही पानी का संकट बन गई है। यह आमजन को अंदर तक आहत करने वाली भी है। केंद्र सरकार ने केन-बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दी है और इसके प्रावधान भी बजट में किए है। खजुराहो के सांसद और भाजपा की मप्र इकाई के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का कहना है कि यह परियोजना इस क्षेत्र में खुशहाली लाने वाली होगी, यहां की पानी संबंधी समस्या से मुक्ति मिलेगी और यहां की तस्वीर बदलेगी।

जल संकट से जूझ रहे इस क्षेत्र में एक कृषि वैज्ञानिक डॉ. आरबी सिंह तोमर पटेल ने उम्मीद की किरण जगाई है। दो दशक के प्रयास से उस फील्ड को पेड़-पौधों से हरा-भरा कर दिया, जिसमें वर्षों से घास भी नहीं उगती थी। जिन्होंने बांदा में ऐसा काम किया है जिस पर इंसान एक बार सोचने पर मजबूर हो जाता है। राजीव गांधी डीएवी महाविद्यालय बांदा की फील्ड में पानी अंदर जाता ही नहीं था। वह पूरा बह जाता था। जमीन पानी को सोखती ही नहीं थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। उनका कहना है कि बुंदेलखंड में सभी लोग रिचार्जिंग सिस्टम अपनाएं तो सिंचाई और पीने के लिए पानी की दिक्कत नहीं होगी। पटेल का दावा है कि बुंदेलखंड के किसान इस मॉडल को स्वीकार कर लें तो उन्हें पीने और सिंचाई के लिए पानी की दिक्कत नहीं होगी। उसकी उपज दोगुनी होगी और बांदा को रेगिस्तान होने से बचाया जा सकेगा। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार भारत में करीब 90 प्रतिशत पानी का इस्तेमाल कृषि में होता है। ऐसे में पानी के संकट का खेती पर बड़ा असर पड़ने वाला है। इस बंजर जमीन पर पटेल ने अब तक लगभग 10 हजार पेड़ तैयार किए हैं। बुंदेलखंड में वैसे भी भीषण पेयजल और सिंचाई का संकट होता है। ऐसे में इनके मॉडल को अपनाकर इस संकट से निपटा जा सकता है। कृषि वैज्ञानिक ने 6 हेक्टेयर में वाटर रिचार्जिंग सिस्टम को डेवलप कर रखा है। इसके दो बोर के जरिए बारिश के दौरान पूरे कॉलेज की बिल्डिंग का पानी आकर सीधे जमीन के अंदर पहुंच जाता है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

केन-बेतवा के लिए झांसी में खुलेगा एसपीवी का कार्यालय

केन-बेतवा लिंक परियोजना का मुख्यालय झांसी में बनाए जाने की तैयारी है। उप्र के हिस्से के लिए झांसी में मुख्यालय बनना तय है। वहीं, मप्र हिस्से की निगरानी भोपाल से होगी। बुंदेलखंड की दो बड़ी नदी केन एवं बेतवा को जोड़ने वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना करीब 19 साल बाद जमीन पर उतरने जा रही है। जलशक्ति मंत्रालय के साथ सिंचाई विभाग इसकी तैयारियों में जुटा है। वहीं, ढोढ़न बांध से निर्माण की शुरुआत की जाएगी। लिंक परियोजना का काम शुरू होने पर झांसी कार्यालय में करीब 200 अधिकारी एवं कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। परियोजना को वर्ष 2030 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। मुख्यालय बनने के बाद झांसी में परियोजना के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता समेत विभिन्न खंड़ों के लिए एक्सईएन तैनात होंगे। इस परियोजना के लिए डेपुटेशन पर भी अभियंता तैनात किए जा सकते हैं। शासन स्तर पर मंथन चल रहा है। मुख्यालय बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव अगले माह तक मंजूर होने की उम्मीद है। परियोजना को अमली जामा पहनाने के लिए स्पेशल व्हीकल परपज (एसपीवी) गठित की जा चुकी है। इसकी कमान मुख्य कार्यपालिक अधिकारी के पास होगी। इस पद पर केंद्र सरकार के अपर सचिव रैंक के अधिकारी तैनात होंगे। इनकी मदद के लिए पांच अलग-अलग अपर मुख्य कार्यपालिक अधिकारी भी होंगे। प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार 90 प्रतिशत धनराशि खर्च करेगी, जबकि दोनों प्रदेशों को कुल दस प्रतिशत धनराशि का खर्च उठाना होगा।

मोदी अभी भी असरदार ब्रांड!

उप्र सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम से एक बार फिर से इस बात पर मुहर लग गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी देश की राजनीति में सबसे असरदार ब्रांड हैं। इस ब्रांड के आधार पर भाजपा ने 4 राज्यों को जीतकर 2024 की राह आसान कर ली है। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, आर्थिक बदहाली के इस दौर में माना जा रहा था कि भाजपा बड़े नुकसान में रहेगी, लेकिन ब्रांड मोदी के असर के सामने विपक्ष के सारे हथियार पस्त हो गए।

● राजेंद्र आगाल

2014 से राष्ट्रीय राजनीति में आए नरेंद्र मोदी के आगे आज विपक्ष विकल्पहीन नजर आ रहा है। वहीं उप्र, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के मतदाताओं ने ब्रांड मोदी को और दमदार बना दिया है। उधर, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जबरदस्त जीत हासिल कर अपने आपको कांग्रेस के विकल्प के रूप में लाकर खड़ा कर दिया है। यानी 5 राज्यों के चुनाव में मात्र 4 नेताओं का प्रभाव मतदाताओं पर दिखा है। पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा अरविंद केजरीवाल और तीसरा और चौथा योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। यह देश की **राजनीति** में एक बड़ा मोड़ है। कुछ साल पहले तक मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच हुआ करता था, लेकिन इस बार क्षेत्रीय दलों का दबदबा देखने को मिला। सबसे बड़ा उभार आम आदमी पार्टी का हुआ है। पार्टी ने पंजाब में बड़ी जीत हासिल कर संकेत दे दिया है कि आने वाले चुनावों में उसे हल्के में न लिया जाए।

उप्र में सपा और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला था, लेकिन शासन और प्रशासन के असर ने अन्य लोगों के साथ महिला मतदाताओं का रुख भाजपा की ओर करने में प्रमुख भूमिका निभाई। प्रदेश में समाज कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाओं और इंटरनेट मीडिया पर चलाए गए प्रचार अभियान ने भी अपना रंग दिखाया, जिसके चलते भाजपा पर लोगों का भरोसा मजबूत हुआ। इसके अलावा भाजपा ने अपने चुनाव अभियान के दौरान आवास, पेंशन, किसान सम्मान निधि, शौचालय, कामगारों के लिए कैश-क्रेडिट, ई-श्रम कार्ड और कानून एवं व्यवस्था में सुधार को भी मुद्दा बनाया और यह कारगर भी रहा।

भाजपा का दमदार प्रदर्शन

भाजपा ने 4-1 की जीत के साथ यह साबित कर दिया कि निकट भविष्य में उसका मुकाबला करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। चुनाव वाले राज्यों में भाजपा पर कई तरह के आरोप लगाए गए। जैसे उप्र में हाथरस कांड, कोविड कुप्रबंधन, महंगाई और बेरोजगारी आदि के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन चुनाव परिणामों पर इन आरोपों का कुछ खास असर नहीं दिखा। भाजपा ने अपने मौजूदा वोट बैंक के साथ-साथ जाटव और ओबीसी के वोट भी हासिल कर एकतरफा जीत हासिल की। पार्टी ने महिलाओं को अपनी हर योजना का मुख्य लाभार्थी बनाकर उनके वोट भी अपने नाम कर लिए। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारा देकर महिलाओं का ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन धरातल पर किए गए कामों और महिला सुरक्षा के कारण भाजपा ने बड़ी संख्या में महिलाओं के वोट हासिल करने में सफलता पाई। विपक्ष जहां बेरोजगारी, पक्षपात, कृषि कानूनों, लखीमपुर खीरी कांड के मुद्दों पर भाजपा को घेरने की कोशिश में था, वहीं राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, पूर्वांचल एक्सप्रेस के साथ मोदी लहर ने न केवल पूर्वांचल में अपना जोर बनाए रखा, बल्कि पूरे प्रदेश में मोदी ब्रांड का दबदबा बनाया। कांग्रेस तमाम उपाय आजमाने के बावजूद मतदाताओं का भरोसा जीतने में नाकाम रही। वहीं दलितों ने भी इस बार बसपा से किनारा कर लिया। पिछड़े वर्ग के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की पराजय क्षेत्र में भाजपा के प्रभाव का आभास कराती है। स्वामी प्रसाद का पलायन उन्हीं के लिए घातक साबित हुआ। फाजिलनगर में भाजपा प्रत्याशी ने उन्हें लगभग 45 हजार वोटों के भारी अंतर से हराया। स्वामी प्रसाद 5 बार विधायक रह चुके हैं। पिछले चुनाव में वह बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। माना जा रहा था कि उनका जाना भाजपा के लिए बहुत **नुकसानदायक** साबित होगा, लेकिन चुनाव नतीजों ने साफ कर दिया कि फिलहाल मोदी-योगी की जोड़ी का कोई तोड़ नहीं।

उप्र के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने भी राष्ट्रहित, देश की सुरक्षा, धार्मिक पर्यटन और सैनिक कल्याण जैसे मुद्दों पर भाजपा को वोट दिया। कांग्रेस द्वारा नौकरियां देने, महंगाई से निपटने, सस्ती एलपीजी उपलब्ध कराने के वादे यहां भी नहीं टिक पाए। प्रधानमंत्री यहां गृहमंत्री के साथ तीन दिनों तक रहे। मोदी ब्रांड के सहारे भाजपा बार-बार मुख्यमंत्री बदलने के कारण हुई राजनीतिक उथल-पुथल और कोविड प्रबंधन पर उठ रहे सवालों से निपटने में सफल रही।

लचर दिखा विपक्षी खेमा

आप नतीजों में सीटों के समीकरण देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी, जो कि इन चुनावों में साफ होती दिखती है, वह साफ नहीं हुई है बल्कि उसने कड़ी टक्कर दी है, लेकिन यह कड़ी टक्कर उसके लिए फायदा साबित होने के बजाय समाजवादी पार्टी के लिए खतरनाक साबित हुई। यही हाल कांग्रेस के कुछ प्रत्याशियों का रहा है। हालांकि कांग्रेस को 2 से 3 सीटों से ज्यादा की उम्मीद पहले भी नहीं जताई गई थी। अब यदि मुद्दों की बात करें तो उप्र का पूरा चुनाव बिल्कुल भी चौंकाने वाला नहीं रहा। भाजपा के पक्ष के मुद्दों की बात करें तो अपराधियों पर लगाम, ऑर्गेनाइज्ड क्राईम को खत्म करने का दावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार द्वारा दी गई योजनाओं की एक लंबी लिस्ट, जिस पर पक्ष-विपक्ष की लंबी बहस होती थी, लेकिन फिर भी बताने के लिए बहुत सारी योजनाएं थे। उदाहरण के लिए पक्के मकान बनाना, शौचालय बनाना, उज्ज्वला योजना, मुफ्त राशन आदि। यदि भाजपा के खिलाफ और समाजवादी पार्टी के पक्ष के मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी पर भाजपा बुरी तरह से घिरी, क्योंकि वह युवा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी के चेहरे से प्रभावित थे, वह भी बेरोजगारी पर उनसे नाराज दिखे। कई परीक्षाओं में लीक होने वाले पर्चों ने भी युवाओं की नाराजगी बढ़ाई। दूरस्थ ग्रामीण इलाकों से शहरों में 1 दिन पहले आकर अपने एग्जाम के लिए रुकने वाले बच्चों के जब पेपर लीक होते हैं, तो उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसे भी लोगों ने देखा। हालांकि यह बात तभी स्पष्ट हो गई थी कि चुनाव में यह बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा।

हालांकि पुष्कर सिंह धामी अपनी ही सीट बचाने में नाकाम रहे।

पंजाब में आप का दम

पंजाब ने साफ तौर आम आदमी पार्टी को चुना। अपने वोटों में 17 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ आप ने शानदार जीत हासिल की। यहां कई बड़े चेहरों को हार का सामना करना पड़ा। दलित मुख्यमंत्री चन्नी के सहारे खुद को दलित हितैषी साबित करने की कोशिश कांग्रेस के काम नहीं आई। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी ने पहली बार 92 सीटों पर जीत हासिल कर इतिहास रचा। संभव है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरे और केजरीवाल एक राष्ट्रीय नेता के रूप में अपनी जगह बना लें। भविष्य में उत्तर भारत में आम आदमी पार्टी भाजपा के सामने प्रतिद्वंद्वी के रूप में भी उभर सकती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार सिमटती जा रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली मॉडल पंजाब में कारगर साबित हुआ। शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस की हार मतदाताओं की उनसे नाराजगी को ही उजागर करती है। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की नई पंजाब लोक कांग्रेस के भाजपा से जुड़ने का भी कोई असर नहीं हुआ। यहां भाजपा को कैडर न होने का नुकसान उठाना पड़ा। बदलाव की चाह में पंजाब ने आप को चुना। अब यह देखना रोचक होगा कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी पंजाब में कैसी पारी खेलती है?

मणिपुर में भी भाजपा के लिए शासन, प्रशासन और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करना कारगर साबित हुआ। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने बड़ी जीत हासिल की। गोवा में भी भाजपा ने प्रमोद सावंत के चेहरे के साथ मोदी के भरोसे चुनाव लड़ा और विकास को प्रमुख मुद्दा बनाया। भाजपा ने यहां 40 में से 20 सीटों पर जीत हासिल कर अपनी रणनीति को सही साबित किया। कुल मिलाकर 2024 के लिए चुनावी माहौल तैयार करते हुए मतदाताओं ने यह संदेश दे दिया है कि भाजपा अपनी प्रतिद्वंदी पार्टियों से बहुत आगे है। यह संदेश ऐसे समय आया है, जब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का दबदबा लगातार कम होता जा रहा है।

कांग्रेस का विकल्प बनती आप

5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का बड़ा हंगामा था। इसे दिल्ली का सेमीफाइनल तक कहा गया। उप्र से लगाकर मणिपुर तक भाजपा को घेरने के हर संभव प्रयास हुए, पर नतीजा सिफर रहा! यहां तक तो ठीक है, पर कांग्रेस और भाजपा की इस रस्साकशी में आम आदमी पार्टी ने जो किया, वो भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा चमत्कार है। उसने पंजाब से कांग्रेस की सरकार को बाहर करके कब्जा जमा लिया। चुनाव परिणाम भले भाजपा की मंशा के अनुरूप आए हों, पर आप की जीत उसके लिए भी खतरे की घंटी है। पंजाब में सत्ता के गलियारों से दूर हुई कांग्रेस को देखकर यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांग्रेस विहीन भारत की मुहिम को एक और सफलता हासिल हुई। लेकिन, इसी के साथ भारतीय राजनीति के क्षितिज पर एक दल ने राजनीति में एक नया अध्याय जरूर लिख दिया। ये नया अध्याय लिखा है आप ने। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे सत्तारूढ़ आप पार्टी ने अब राष्ट्रीय स्तर पर पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। भाजपा और कांग्रेस के बाद आप ऐसी **तीसरी राजनीतिक पार्टी** हो गई है जिसकी एक से अधिक राज्यों में सरकार है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांग्रेस विहीन भारत की कल्पना को भले ही पंजाब में स्वीकार किया गया हो और कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया हो! लेकिन, इसका फायदा भाजपा को नहीं मिला। जैसा दिल्ली में हुआ वैसा ही पंजाब में भी हुआ। दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकार थी, जो अब नहीं है। लेकिन, इन जगहों पर कांग्रेस के बाद भाजपा अपने पैर नहीं जमा सकी। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार के बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी और दोबारा भी यही सरकार कायम हुई। यानी जहां कांग्रेस थी वहां आप ने अपना कब्जा जमा लिया। इसी तरह पंजाब में भी चन्नी सरकार के बाद आप की सरकार बनने जा रही है। जहां कांग्रेस का शासन था वहां अब कांग्रेस नहीं है। लेकिन, भाजपा को भी लोगों ने उसके विकल्प के रूप में नहीं चुना। कांग्रेस के मैदान से हटते ही जो रिक्त स्थान हुआ, उस पर भाजपा नहीं बल्कि आप कब्जा करती जा रही है। कहा जा सकता है कि अब देश में कांग्रेस की जगह आप ही भाजपा को टक्कर देने के लिए खड़ी हो रही है। इसका क्या यह आशय निकाला जाए कि अब देश में कांग्रेस के विकल्प के रूप में आप को स्वीकारा जाने लगा है! हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनाधार अपनी दूसरी पारी में भी कायम है। आज भी अपनी पार्टी के साथ देश के लोगों में वे उतने ही लोकप्रिय हैं, जितने अपने पहले कार्यकाल में थे। उनकी कई कल्याणकारी योजनाएं उन्हें लोकप्रिय बनाने में सहयोगी हैं। नोटबंदी की ही तरह बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन जैसे अनेक मुद्दे उन्हें और उनकी पार्टी को नहीं डिगा सके। विधानसभा चुनावों के पहले उनकी गंगा में लगाई डुबकी में ये सारे मुद्दे डूब

'बुल्डोजर बाबा' शब्द का जलवा

उप्र में योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे उपयोगी मुद्दा साबित हुआ अपराध मुक्त उप्र का। अखिलेश यादव ने अपनी सभाओं में तीखे प्रहार किए और उनकी सभाओं को अच्छा प्रतिसाद भी मिला। इन्हीं की वजह से उनका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर था लेकिन इन्हीं रैलियों के दौरान वो एक बड़ी गलती कर गए। उन्होंने एक अखबार का जिक्र करते हुए 'बुल्डोजर बाबा' शब्द को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। भाजपा ने इस जुमले को पकड़ लिया। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ की रैलियों में बुलडोजर खड़े दिखाई देने लगे। इन बुल्डोजरों को देखकर प्रसन्नता जाहिर करते, योगी आदित्यनाथ के वीडियो वायरल हुए। इससे स्पष्ट था कि भाजपा ने इसे एक आरोप की तरह ना लेकर एक सम्मान की तरह लिया। हकीकत तो यही है कि भाजपा दो बातों में पूर्णतः सफल रही। पहला स्वयं को अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने वाला बताने में और दूसरा समाजवादी पार्टी को अपराधियों का समर्थन करने वाली पार्टी बताने में। योगी का कहना था कि उप्र के व्यापारियों व्यवसायियों ने मेरे लगभग हर कार्यक्रम में चौथ वसूली, गुंडागर्दी की बातें कहीं और वह वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था से प्रसन्न दिखाई दिए। हालांकि बढ़ती महंगाई कच्चे माल के बढ़ते दाम आदि पर उनकी नाराजगी बहुत स्पष्ट थी। फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि आने वाले समय में भाजपा जो कर सकती है, वह समाजवादी पार्टी नहीं कर पाएगी।

गए और राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मथुरा मंदिर जैसे धर्म आस्था में मोदी और उनकी पार्टी इन चुनावों को पार कर गई। अब, जबकि आने वाले दिनों में गुजरात विधानसभा के चुनावों के बाद लोकसभा के भी चुनाव होना है। लगता नहीं कि कोई बाधा प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के आड़े आएगी। मगर ये तय है कि स्वच्छ भारत के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस झाड़ू को उठाया था, वही झाड़ू उनके सामने आ सकता है। देश की राजनीति में कांग्रेस का विकल्प बनी आप पार्टी के कर्ताधर्ताओं में कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला नहीं है। इस कारण आप अभी तक राजनीतिक प्रपंच से भी दूर है। यदि इसी तरह की राह पर वह चलती रही तो देश की राजनीति के शिखर पर भी जाने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता।

भाजपा को 10 राज्यों में फायदा

उप्र, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव में जीत से भाजपा ने कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने नया इतिहास रच दिया है। उप्र में साढ़े तीन दशक बाद किसी पार्टी की सरकार रिपीट हुई है। आजादी के बाद ये पहली बार होगा कि अपनी पार्टी को सत्ता में वापसी कराने वाले योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ऐसी पहली क्षेत्रीय पार्टी बन गई है, जो एक राज्य से आगे बढ़कर दूसरे राज्य यानी दिल्ली से आगे बढ़कर पंजाब में सरकार बनाएगी। वहीं केंद्र की सियासत में भी इस चुनाव के नतीजों का असर दिखेगा।

योगी का कद बढ़ेगा

उप्र किला फतेह के बाद योगी आदित्यनाथ भाजपा में पूरी तरह से स्थापित हो जाएंगे। मोदी और अमित शाह के बाद तीसरे नंबर के सबसे बड़े नेता बन जाएंगे। आजादी के बाद योगी ऐसे पहले नेता होंगे, जिन्हें उप्र में सरकार रिपीट कराने के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। गुजरात मॉडल की तरह भाजपा उप्र मॉडल का भी देशभर में प्रचार कर सकती है। खासतौर पर उन राज्यों में जहां भाजपा कमजोर है, वहां भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया जा सकता है। अप्रैल से अगस्त के बीच राज्यसभा की 70 सीटों के लिए चुनाव होंगे। इसमें भाजपा को 5 सीटों का नुकसान हो रहा था, लेकिन उप्र, उत्तराखंड में सरकार बनने से इस नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सकती है। इसमें से उप्र की 11, पंजाब की 7 और उत्तराखंड की एक सीट पर चुनाव होंगे। पार्टी की उप्र और उत्तराखंड से दो से तीन सीटें बढ़ सकती है। वहीं पंजाब में आप की सरकार बनने से पार्टी को राज्यसभा में 6 सीटों का फायदा हो सकता है। फिलहाल राज्यसभा में आप के पास तीन सीटें हैं।

हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण

हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण एक ऐसी घटना है जिसको समझने के लिए आपको मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण समझना होगा। मुस्लिम-यादव समीकरण समाजवादी पार्टी के साथ थे और यह स्पष्टतः देखा गया, लेकिन जब मुस्लिम मतदाता पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ एकजुट होता है, तो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण अपने आप शुरू हो जाता है। एक माहौल बनने लगता है जिसमें हिंदू मतदाता को लगता है कि सारे मुस्लिम मतदाता एक साथ जा रहे हैं, तो हमें भी यही करना चाहिए। यूं तो उप्र की राजनीति जातियों में बंटी हुई है और इसका असर हमेशा देखा जाता है। सातवें चरण में पूर्वांचल की सीटों पर किस तरह पटेल समाज का जोर चलता है और किस तरह बहुजन समाज पार्टी कई क्षेत्रों में आज भी अपने वोट बैंक को पूरी तरह बरकरार रख पाई है, यह इससे स्पष्ट है। जब भी वोटों का ध्रुवीकरण होता है तब जातियों का यह समीकरण पीछे छूट जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी हर रैली में इस बात का ध्यान रखा। प्रधानमंत्री मोदी अब केंद्र की राजनीति का चेहरा हैं, उनके बयान बहुत सोचे समझे होते हैं। वह इन विषयों पर बहुत खुलकर नहीं बोलते हैं, उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विषय में कई जगहों पर कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो बहुत खुलकर ईद पर बिजली आती थी, दिवाली पर नहीं आती थी जैसे बयान दिए। उन्होंने कहा मैं भगवा पहनता हूं और पूरा उप्र भगवा है। ऐसी बातों को भी खुले मंच से कहा। आप यदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषणों को सुने तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि वह हिंदुत्व के एजेंडे पर बिल्कुल खुलकर मैदान में उतरे। उनका आत्मविश्वास सही था कि उनका हिंदुत्व का चेहरा हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करेगा।

राष्ट्रपति चुनाव पर असर

राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से अभी भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के पास विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव पर भी भाजपा का असर रहेगा। भाजपा जिसे प्रत्याशी बनाएगी, उसकी जीत तय मानी जा रही है। दोनों सदनों के 776 सांसद और राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों के 4,120 विधायक मिलकर राष्ट्रपति चुनते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज 10,98,903 वोट्स का है। राष्ट्रपति बनने के लिए 5,49,452 वैल्यू वोट्स चाहिए होते हैं। उप्र के हर विधायक के वोट की वैल्यू 208 है, जो देश में सबसे अधिक है। यानी उप्र के विधायकों के वोट की कुल वैल्यू 83,824 है। यह वैल्यू आबादी के अनुपात में तय होती है। इसके बाद महाराष्ट्र (50,400) और पश्चिम बंगाल (44,394) का नंबर आता है। इस वजह से उप्र के विधायक राष्ट्रपति चुनावों में भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली में क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें हैं। मप्र में भाजपा-कांग्रेस के विधायक करीब-करीब बराबर ही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें हैं। अगर कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर किसी संयुक्त उम्मीदवार को सामने लाती है तो उसकी जीत की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। एचडी देवीगौड़ा से शरद पवार तक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं।

राष्ट्रपति चुनावों के लिए क्षेत्रीय पार्टियों के मुख्यमंत्रियों की लामबंदी भी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी तृणमूल कांग्रेस को पूरे देश में फैलाना चाहती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.

अब केजरीवाल का और बढ़ेगा कद...

2020 में दिल्ली विधानसभा की दूसरी बंपर जीत के बाद यह माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब राष्ट्रीय राजनीति में उतरेंगे। उन्होंने कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी की थी। वहां पर जब नेतृत्व की बात आती तो ममता बनर्जी या शरद पवार सरीखे नेताओं का नाम सामने आने लगता। इस बात को आप संयोजक केजरीवाल अच्छी तरह समझते थे। जब उन्होंने पंजाब चुनाव के लिए सक्रियता दिखाई तो भाजपा नेताओं की तरफ से ऐसी प्रतिक्रियाएं आईं कि वे दिल्ली छोड़कर पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। केजरीवाल और उनका मंत्रिमंडल जब कई दिनों तक एलजी आवास में धरने पर बैठा तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, केजरीवाल के आवास पर पहुंचे थे। इसके बाद जब कुछ सामान्य हुआ तो केजरीवाल को विपक्षी दलों के बीच विशेष स्थान नहीं मिल सका। यहीं से केजरीवाल ने अपनी रणनीति बदल दी। इन सभी बातों ने केजरीवाल को यह संदेश तो दे ही दिया कि अभी राष्ट्रीय राजनीति में कदम बढ़ाने का सही वक्त नहीं है। उन्होंने पार्टी के विस्तार पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह की जल्दबाजी दिखाकर 400 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए थे, अब वैसा कदम नहीं उठाया। उन्होंने आप के विस्तार पर ध्यान दिया। कांग्रेस के गिरते ग्राफ को आम आदमी पार्टी ने अच्छे से कैश कर लिया। पंजाब में आप की भारी सफलता इसका एक बड़ा उदाहरण है। पंजाब में सरकार बनने के बाद अब केजरीवाल, राष्ट्रीय राजनीति पर फोकस कर सकते हैं। केजरीवाल को लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना था कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत जटिल है। बहुत से लोगों की राय जुदा होती है। राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा बनने के लिए केजरीवाल को अब अधिक वक्त नहीं लगेगा। वे लोगों के सामने राजनीति का एक अलग प्लेटफार्म रखते हैं। उनकी बात को लोग सुनते हैं। उसे सियासत की बहस का हिस्सा बनाया जाता है। दिल्ली के बाद पंजाब में आप को मिले प्रचंड बहुमत के बाद राष्ट्रीय राजनीति में केजरीवाल का कद अब बढ़ना तय है। आज की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर गत वर्ष से काफी सक्रिय हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने केजरीवाल को पूर्ण सहयोग दिया था। इस चुनाव में प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक ने आप के लिए रणनीति तैयार की थी।

चंद्रशेखर राव यूं तो महत्वपूर्ण कानूनों पर केंद्र की मोदी सरकार का समर्थन करते रहे हैं, पर उन्हें भी राज्य में तेजी से बढ़ने के ख्वाब देख रही भाजपा का खतरा तो है ही। राव ने भी पिछले दिनों शिवसेना चीफ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। केसीआर की तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन के अलावा ममता से भी मीटिंग फिक्स है। एचडी देवीगौड़ा को राव का सपोर्ट मिल सकता है। महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों में 200 से अधिक लोकसभा सीटें हैं। साथ ही अगले राष्ट्रपति चुनावों के इलेक्टोरल कॉलेज की आधी वैल्यू इन्हीं राज्यों से है। एनसीपी चीफ शरद पवार भी तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल, तेलंगाना राष्ट्रसमिति, वायएसआर सीपी, माकपा और भाकपा समेत अन्य पार्टियों का समर्थन जुटा सकते हैं। इससे भाजपा की राह और मुश्किल हो जाएगी।

राज्यसभा पर असर

इस साल राज्यसभा की 75 सीटें खाली होने वाली हैं। इनमें से 73 को राष्ट्रपति चुनावों से पहले भरा जाएगा। ज्यादातर सदस्य अप्रैल में रिटायर होंगे। इनके चुनाव जून और जुलाई में हो जाएंगे। 7 नॉमिनेटेड सदस्यों को छोड़ दें तो इन 73 में से 66 सांसद राष्ट्रपति चुनावों में वोट डालेंगे। इनमें 19 सीटें 3 चुनावी राज्यों से है। उप्र से 11, पंजाब से 7 और उत्तराखंड से 1 सीट है। उप्र में खाली हो रही 11 राज्यसभा सीटों में से 5 भाजपा के पास है। 2017 के चुनावों जैसी सफलता नहीं मिली तो भाजपा को अपनी सीटें सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाएगा। अन्य 54 राज्यसभा सीटें महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, झारखंड, केरल, कर्नाटक, ओडिशा, असम, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मप्र और हिमाचल प्रदेश से है।

5 राज्यों के चुनाव नतीजों में विपक्ष के लिए भी सबक छिपे हैं। ऐसा नहीं कि विपक्ष मौके को भुना नहीं पाया। केंद्र की कोरोनाकाल की विफलताएं, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने काफी काम किया। सपा ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में काफी हद तक अपनी इमेज को मजबूत किया है। इसका असर भी दिखा। हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है।

पंजाब जीतने के बाद आप दूसरे राज्यों में करेगी विस्तार

आम आदमी पार्टी पहली ऐसी क्षेत्रीय पार्टी बन गई है, जो एक राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में सरकार बनाएगी। इससे एक और संकेत मिलते हैं कि कांग्रेस जहां-जहां नीचे की ओर जा रही है, वहां आम आदमी पार्टी उभर रही है। पंजाब चुनाव में जीत के बाद आप को कांग्रेस के विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है। इस चुनाव में सबसे अधिक झटका कांग्रेस को लगा है। 5 साल की सत्ता विरोधी लहर के बाद भी कांग्रेस उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में सरकार नहीं बना पाई। पंजाब में जहां जीतने संभावना थी, आपसी गुटबाजी के कारण थाली में परोसकर सत्ता आम आम आदमी पार्टी को सौंप दी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लंबे समय से काम कर रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की उम्मीद थी, लेकिन तब कांग्रेस की जीत हुई थी।

फर्जीवाड़े पर नकेल

फर्जी कंपनियों का खेल

यह कोई नई बात नहीं है कि हिन्दुस्तान में फर्जी नामों से फर्जी कंपनियां चलती हैं। कई बार जांच एजेंसियों ने ऐसी फर्जी कंपनियों का समय-समय पर पर्दाफाश किया है। हैरानी की बात यह है कि इन फर्जी कंपनियों से हर साल फर्जी लोग अरबों-खरबों रुपए का घोटाला करके गायब हो जाते हैं और बाद में इसी तर्ज पर नई फर्जी कंपनियां ऐसे घोटालों के लिए खड़ी हो जाती हैं। कई ऐसी कंपनियों के जरिए ये फर्जी लोग मोटा ऋण बैंकों से लेकर चंपत हो जाते हैं। पिछले सात साल में ऐसे चंपत होने वाले लोगों की फेहरिस्त में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। अब इन लोगों पर कौन-से बाबा का हाथ है, यह तो नहीं पता; लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि बैंकों का पैसा लेकर भागने वाले इन लोगों में गुजरात के भगोड़े सबसे ज्यादा हैं। खैर, फर्जी नाम पर चलने वाली फर्जी कंपनियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार ने 2014 में सत्ता हासिल करने के बाद काला धन पर रोक लगाने का दावा करते हुए देश में चलने वाली हजारों फर्जी कंपनियों पर नकेल कसने की बात कही। लेकिन साल 2017 में जब 13 बैंकों से लोन लेकर चंपत हुए लोगों का खुलासा हुआ, तब पता चला कि देश में हजारों फर्जी कंपनियां चल रही हैं और इनमें से कई कंपनियों के तो 100-100 बैंक खाते भी थे। इस दौरान बैंकों की ओर से 5,800 फर्जी कंपनियों की लिस्ट जारी की गई और सरकार ने तब दावा किया कि उसने करीब दो लाख से ज्यादा फर्जी कंपनियों पर रोक लगा दी है। इस दौरान हैरानी की बात यह सामने आई कि एक कंपनी के तो करीब 2,134 बैंक खाते थे। और नोटबंदी के दौरान इन फर्जी कंपनियों ने करीब 4,573.87 करोड़ रुपए का लेन-देन भी किया।

इन दिनों एक ऐसे बाबा का जिक्र पूरे देश में हो रहा है, जिसके इशारों पर देश का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) चल रहा था। यह बाबा कौन है? कहां रहता है? इस बात का किसी को कुछ पता नहीं है। यह बाबा वेदों के नाम से बनी ईमेल्स के जरिए एनएसई चलाता था और उसके आदेशों के आधार पर ही वहां सब कुछ होता था। लंबे समय तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कब्जा करके रखने वाला यह बाबा जो-जो हुक्म ईमेल के जरिए उस समय की एनएसई की सीईओ चित्रा रामकृष्ण को देता था, मैडम उस हुक्म का तत्काल पालन करती थीं। यह बाबा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ और अन्य बड़े पदों पर नियुक्तियां भी एक ईमेल के जरिए करता था। गजब बात यह है कि इन बड़े पदों पर नौकरी करने वालों की तनख्वाह भी करोड़ों में रही।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण की पदोन्नति किस बाबा के इशारे पर हो जाती है? वो कैसे एक अदृश्य बाबा के संपर्क में आ जाती हैं? और इसी अज्ञात बाबा के इशारे पर काम क्यों करती हैं? यह सवाल सेबी भी नहीं खोज सका है। इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार इस पर खामोशी साधे हुए है। सात साल में अब जब सेबी की जांच पूरी हुई, तो भी वह यह बताने में नाकाम है कि चित्रा रामकृष्ण को **कौन-सा बाबा अपने इशारे पर** चला रहा था? 70 फीसदी का लाभ कमाकर देने वाले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इतनी बड़ी साजिश चल रही थी, इसकी खबर सरकार को न होना हैरान कर देने वाली बात है। सन् 1963 में जन्मीं चित्रा रामकृष्ण सन् 1992 में बने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की स्थापना करने वाली टीम में शामिल थीं। बाद में वह एनएसई के उच्च पद सीईओ तक पहुंचीं। यह पद और प्रबंध निदेशक का पद उन्होंने अप्रैल, 2013 में संभाला था। उनका कार्यकाल मार्च, 2018 को समाप्त होना था, लेकिन गलत गतिविधियों के कारण उन्हें 2016 में इस्तीफा देना पड़ा। अब जाकर उनके मामले में सेबी की जांच सामने आई है, जिसमें बाबा की कहानी किसी को हजम नहीं हो रही। पूरी दुनिया में इतने बड़े स्टॉक एक्सचेंज को बाबा द्वारा चलाने वाली बात का मजाक बन रहा है। सेबी ने चित्रा रामकृष्ण पर महज तीन करोड़ रुपए, रवि नारायण तथा आनंद सुब्रमण्यम पर दो-दो करोड़ रुपए और वीआर नरसिम्हन पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा सेबी ने एनएसई को चित्रा के अलावा अवकाश के बदले भुगतान किए गए 1.54 करोड़ रुपए और 2.83 करोड़ रुपए के बोनस (डेफर्ड बोनस) को जब्त करने का भी निर्देश दिया है। एनएसई की पूर्व प्रबंध निदेशक चित्रा रामकृष्ण के घर आयकर विभाग ने भी छापा मारा और बाकी आरोपियों से भी पूछताछ की। हालांकि चित्रा रामकृष्ण और सुब्रमण्यम की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी पर कार्रवाई का इंतजार है।

हैरानी की बात यह है कि चित्रा बाबा के एक ईमेल के इशारे पर ही नई नियुक्तियां कर देती थीं, लोगों को पदोन्नति देती थीं, उनकी तनख्वाह बढ़ा देती थीं। आनंद सुब्रमण्यम को चित्रा रामकृष्ण बाबा के कहने पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एक बड़ा पद देती हैं। वह भी नया पद बनाकर एक 15 लाख की तनख्वाह सालाना पाने वाले को पांच करोड़ रुपए की तनख्वाह देती हैं और प्रथम श्रेणी की हवाई यात्रा के साथ-साथ उन्हें मनमर्जी के खर्चे करने की छूट भी मिलती है। यहां तक बाबा ईमेल से कहता है कि आनंद को हफ्ते में पांच दिन नहीं, बल्कि तीन दिन ही काम करना चाहिए। इस प्रकार आनंद सुब्रमण्यम हफ्ते में केवल तीन दिन काम करने की छूट भी मिल जाती है। सवाल यह है कि सरकार एक तरफ देशभर में काम करने वालों के काम के घंटे बढ़ाती है, तो वहीं दूसरी ओर एक बाबा जो कि आज भी अज्ञात है, एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को महज तीन दिन अपनी मर्जी से काम करने की छूट दिलवा देता है। इसी तरह अन्य कई नियुक्तियां बाबा के ईमेल के इशारे पर होती हैं और कोई आवाज तक नहीं उठती है।

कहा जा रहा है कि बाबा हिमालय में रहता है, और ईमेल उस जगह से चलाता है, जहां नेटवर्क ही नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यही बाबा सरकार भी चला रहा है। चित्रा रामकृष्ण की बाबा से बातचीत वाली ईमेलों से पता चला है कि बाबा बालों की सज्जा (हेयर स्टाइल) के बारे में भी अच्छी जानकारी रखता है और बताता है कि किस प्रकार का हेयर स्टाइल होना चाहिए। बाबा अज्ञात है और चित्रा व कुछ लड़कियों के साथ देश-विदेश घूमने का शौकीन भी है। सेबी ने जब चित्रा रामकृष्ण से पूछा कि वो बाबा कौन हैं? आपकी उनसे मुलाकात कैसे हुई? तो चित्रा कहती हैं कि बाबा योगी हैं और परमहंस हैं। वह उन्हें गंगा के एक तट पर 20 साल पहले मिले थे।

● **अक्स ब्यूरो**

देश में कांग्रेस की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की परफॉरमेंस चिंताजनक रही। ऐसे में पार्टी में ही नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठने लगी है। लेकिन आलाकमान राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि खुद राहुल गांधी भी ताजपोशी के लिए तैयार हैं। अब देखना है पार्टी का अगला कदम क्या होता है।

राहुल ताजपोशी को तैयार!

राहुल गांधी ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। कांग्रेस को वो पांडव मानते हैं क्योंकि भाजपा को वो कौरवों की सेना समझते हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गुजरात में उनके गढ़ में घेरने का एक्शन प्लान भी तैयार कर चुके हैं। हालांकि, राहुल गांधी का ये भी मानना है कि कांग्रेस में भी कुछ कौरवों के वंशज हैं और चाहते हैं कि उनकी पहचान करके जल्द से जल्द भाजपा को एक्सपोर्ट कर दिया जाए। बस एक ही तस्वीर अब भी काफी धुंधली नजर आ रही है, वो है राहुल गांधी के अपने रोल को लेकर। अब ये संकेत भी मिल चुके हैं कि कौरवों से लड़ने के लिए वो गुजरात को ही कुरुक्षेत्र बनाने में जुट गए हैं, लेकिन अब तक ये नहीं मालूम हो सका है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में वो खुद किस भूमिका में होंगे? लिहाजा सवाल ये उठता है कि अगर राहुल गांधी अपने लिए कृष्ण का किरदार चुनते हैं तो गुजरात में अर्जुन कौन होगा?

कांग्रेस के चिंतन शिविर में राहुल गांधी के मोटिवेशनल स्पीच से तो एकबारगी लगता है कि कृष्ण का किरदार ही उनको ज्यादा पसंद है। वैसे भी उनके पास ऐसी भूमिका निभाने का लंबा अनुभव रहा है। 2004 से लेकर अभी तक, अगर 2017 से 2019 वाले बीच के रोल को अलग करके देखा जाए तो ऐसा ही लगता है। कुछ महीनों के लिए वो अर्जुन की भूमिका में भी रहे हैं, लेकिन कृष्ण वाले रोल में खुद को काफी कम्फर्टेबल पाते हैं, ऐसा उनकी कार्यशैली को देखकर लगता है। सवाल ये भी है कि अगर राहुल गांधी अपने लिए अर्जुन का किरदार चुनते हैं तो कृष्ण की भूमिका में कौन होगा? और एक सवाल ये भी है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा अपने अर्जुन की सारथी बनने को तैयार हैं? और ये भी कि क्या कांग्रेस के मौजूदा आधिकारिक या अंतरिम नेतृत्व ने भी मंजूरी दे दी है, या फिर भाई-बहन के संयुक्त निर्णय में किसी और की बहुत गुंजाइश भी नहीं बचती, भले ही वो सोनिया गांधी ही क्यों न हों।

कथनी और करनी का फर्क देखना हो तो बिहार के दो-लड़कों की पसंद की तरफ भी एक बार झांक सकते हैं - लालू के दो लाल की तरफ। तेज प्रताप यादव खुद को कृष्ण और तेजस्वी यादव को अर्जुन बताते तो हैं, लेकिन लगता है ऐन उसी वक्त वो खुद को भी अर्जुन की भूमिका में होने की चेष्टा में रहते हैं और साजिशें हैं कि ख्वाहिशों पर पानी फेर देती हैं। कभी-कभी तो प्रियंका गांधी वाड्रा को भी तेज प्रताप जैसा ही महसूस होता होगा, जबकि हकीकत उसके उलट ही प्रतीत होती है। राहुल गांधी जब चेन्नई के स्टेला कॉलेज जैसे कैंपस में होते हैं तो चेहरे पर गजब की चमक देखने को मिलती है और जब बोलते हैं, नाम तो सुना ही होगा, मन की बात फटाफट कंफर्म भी हो जाती है। द्वारका में आयोजित कांग्रेस के चिंतन शिविर में भी राहुल गांधी को अंदर से वैसा ही खुश देखा और सुना भी गया।

राहुल गांधी ने गुजरात के नेताओं को 10 दिसंबर से पहले हार न मानने की सलाह दी है (अब ये विधानसभा चुनाव से जुड़ी तारीख तो हो भी नहीं सकती) तो क्या राहुल गांधी ने अपनी ताजपोशी की तारीख बताई है? चिंतन शिविर के सेंस ऑफ ह्यूमर से भी लगता है, राहुल गांधी मन बना चुके हैं। करत-करत अभ्यास के **जड़मति होत सुजान**, जैसी परिकल्पना और की हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी लगातार मिल रही नाकामियों से ऊब चुके लगते हैं और यथाशीघ्र निजात पाना चाहते हैं। आर या पार। न कम, न ज्यादा। कुछ तो राहुल गांधी ने कांग्रेस के चिंतन शिविर में कहा है और कुछ चीजें हाल फिलहाल उनका पीछा कर रही

क्या राहुल गांधी को हुआ जिम्मेदारी का एहसास?

राहुल गांधी का दावा है कि भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए उनको सिर्फ पांच नेताओं की जरूरत है। ये बात राहुल गांधी ने गुजरात के प्रसंग में कही है, दिल्ली को लेकर ये संख्या घट या बढ़ सकती है। असल बात तो वही जानते होंगे। 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले अपने गुजरात दौरे को याद करते हुए राहुल गांधी ने बताया कि गुजरात कांग्रेस के नेताओं को शुरू में ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद नहीं थी। बगैर नाम लिए एक वरिष्ठ नेता का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनका मानना था कि गुजरात की 182 सीटों में से महज 40-45 सीटें कांग्रेस जीतेगी। राहुल गांधी कहते हैं... लेकिन अंत में हम चुनाव जीतने से सिर्फ 7 सीटों से पीछे रह गए... मैं इस बार भी यही स्थिति देख रहा हूं। 2017 में कांग्रेस को 77 सीटें मिली थीं जबकि भाजपा को 99। अब सवाल ये है कि क्या ये कॉन्फिडेंस ताजपोशी की नई संभावना से मिला है? अब क्या ये समझा जाए कि राहुल गांधी फिर से कांग्रेस की कमान संभालने के लिए मन बना चुके हैं? ये तो साफ है कि सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का पद मजबूरी में ढो रही हैं। यूपीए की चेयरपर्सन की पोस्ट के साथ भी यही चीज लागू होती है, लेकिन क्या सोनिया गांधी की बढ़ती उम्र और सेहत की फिक्र ने ही राहुल गांधी को जिम्मेदारी का एहसास कराया है या कोई और भी वजह हो सकती है?

लगती हैं। मुश्किल ये है कि दिल्ली की डगर अब भी बहुत ही मुश्किल लगती है।

राहुल गांधी का बयान आने के बाद समझा गया कि उनके निशाने पर कांग्रेस के बागी जी-23 गुट के नेता हैं। पद्म पुरस्कार मिलने के बाद से गुलाम नबी आजाद तो आंखों की किरकिरी बने ही हुए हैं, पंजाब चुनाव के दौरान मनीष तिवारी भी कटु सत्य वचन बोल रहे थे, लेकिन सत्य तो सबका अपना-अपना होता है। मनीष तिवारी की बातें सच तो तभी मानी जाएंगी, कम से कम कांग्रेस के भीतर, जब राहुल गांधी भी उसे सच मानेंगे। भले ही वो खुद को कदम-कदम पर सच का सिपाही बताते फिरते हों। कांग्रेस के चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं से सबसे पहले कौरवों की एक इंटरनल लिस्ट तैयार करने को कहा। एक मौखिक गाइडलाइन भी बता दी जिससे ऐसे तत्वों की पहचान करना थोड़ा आसान हो।

राहुल गांधी बता रहे थे, एक तरफ वो लोग... जो 24 घंटे लगे रहते हैं... जमीन से जुड़े हैं... भाजपा से लड़ते हैं... लाठी खाते हैं... दूसरी तरफ बहुत सारे लोग... जो एसी में बैठते हैं... मौज करते हैं... लंबे-लंबे भाषण देते हैं... हमें अब ये स्पष्टता लानी है- वे कौरव हैं। राहुल गांधी की नजर में ये वे लोग हैं जो अपने एसी दफ्तरों में बैठ कर बातों के अलावा कुछ भी नहीं करते और हां, दूसरों को परेशान करते रहते हैं। सवाल तो ये है कि ऐसे लोगों से परेशान कौन-कौन होता है। सिर्फ गांधी परिवार या बाकी कांग्रेसी भी, करीबियों के अलावा। और भी स्पष्टता लाते हुए राहुल गांधी ने बोल भी दिया, ऐसे लोग आखिरकार भाजपा में चले जाते हैं।

मतलब, वे लोग जिनके देर सवेर कांग्रेस छोड़ देने की संभावना लग रही हो। मतलब, अब कांग्रेस के भीतर ऐसे कौरवों की तलाश में मुखबिरों की ड्यूटी लगने वाली है। मतलब, कांग्रेस में कमेटियों की तरह ऐसे तत्वों को आइडेंटिफाई करने का काम भी गांधी परिवार से करीबी साबित करने में काम आ सकता है? लेकिन राहुल गांधी के पास क्या ऐसा भी कोई उपाय है जिससे वो चेक कर सकें कि अगर उनका कोई करीबी नेता किसी और नेता से दुश्मनी साधने के लिए इनपुट के तौर पर अपडेट करता है कि फलां नेता भाजपा जाने की तैयारी कर रहा है। सचिन पायलट को तो अशोक गहलोत निकम्मा, नकारा, पीठ में छुरा भोंकने वाला और न जाने क्या-क्या करार दिए थे, लेकिन सचिन पायलट के खिलाफ तो ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिल पाया।

क्या राहुल गांधी के पास किसी और अशोक गहलोत के किसी और को सचिन पायलट बनाने से बचाए रखने का भी कोई मेकैनिज्म है भी या ये सब यूं ही चलता रहेगा। उप्र चुनाव के दौरान

कांग्रेस में कोई और चेहरा नजर आता है क्या

कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी एक बड़ी वजह बन रही हैं? जिस तरह से उप्र चुनाव से राहुल गांधी ने दूरी बनाई है और जिस तरीके से प्रियंका गांधी, एक दायरे में ही सही, सब कुछ हैंडल करने लगी हैं, सवाल तो पैदा होंगे ही। खासकर उप्र में कांग्रेस के चेहरे को लेकर मीडिया के सवाल पर प्रियंका गांधी का बगैर लाग-लपेट वाला रिएक्शन। बाद में भले ही प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया को बार-बार पूछे जाने से चिढ़कर कही गई बात बताई हो, लेकिन क्या ये गुस्सा ही था? ये सफाई में पेश किया गया डिस्क्लेमर जैसा लगता है। ये तो मन की बात लगती है, जो अचानक जुबान पर आ गई और बाद में बोल दिया कि जुबान फिसल गई थी या तोड़-मरोड़ कर पेश कर दिया गया। क्या आपने ठीक उस वक्त राहुल गांधी के चेहरे पर ध्यान दिया था? एक पल के लिए तो राहुल गांधी का चेहरा भावशून्य हो गया था। कंट्रोल तो किया ही होगा, लेकिन मुस्कुराए तो बिलकुल नहीं। अगर ये बात हंसी-मजाक वाली होती तो क्या वो एक स्माइल नहीं दे सकते थे? हर बार गम को छुपाने के लिए इंसान मुस्कुराए ही, जरूरी भी तो नहीं!

ही आरपीएन सिंह के भाजपा में चले जाने के बाद, प्रियंका गांधी ने भी राहुल गांधी जैसा ही रिएक्शन दिया था। समझाने की कोशिश रही कि संघ और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई काफी मुश्किल है और काफी लंबी भी। लिहाजा हर किसी के लिए लंबे समय तक लड़ाई के मैदान में टिके रहना काफी मुश्किल हो सकता है। बेहतर है वे अपने लिए कोई अच्छा इंतजाम कर लें।

राहुल गांधी पहले ऐसे नेताओं को डरपोक का तमगा भी दे चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि ऐसे नेताओं को संघ और भाजपा में भेज दो... और हां, जो वहां निडर नेता हैं उनको कांग्रेस में लाओ। कांग्रेस में कौरवों की तलाश का राहुल गांधी का नया नुस्खा भी उसी लाइन पर आगे बढ़ता लगता है। राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद का रास्ता गुजरात से होकर वैसे ही निकलता है, जैसे उप्र से देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी की राह। 2017 के आखिर में राहुल गांधी गुजरात विधानसभा का चुनाव खत्म होने के बाद और नतीजे आने से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एक तरफ जबकि राहुल गांधी गुजरात में कांग्रेस के कौरवों की सूची तैयार कराने में लगे हैं, दिल्ली में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी तलब किया गया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में बेहतरीन बजट पेश करने को लेकर गहलोत पीठ ठोकने के लिए दिल्ली दरबार में बुलाए गए हैं।

राहुल गांधी के आवास पर कांग्रेस नेताओं की एक बैठक भी हुई है। अशोक गहलोत के अलावा बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप्र की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए। कहा जा रहा है कि कांग्रेस चुनाव समिति सितंबर, 2022 तक अपना नया अध्यक्ष चुन सकती है। 5 साल पहले जब राहुल गांधी कांग्रेस के गुजरात मिशन पर थे तो मंचों पर उनकी एक तरफ अशोक गहलोत और दूसरी तरफ अहमद पटेल नजर आते थे, क्या अशोक गहलोत को फिर से उसी भूमिका में लिया जाने वाला है? और ऐसा होता है तो क्या सचिन पायलट के सपनों को हकीकत में बदले जाने की भी कोई संभावना बनती है?

2017 गुजरात दौरे में राहुल गांधी के साथ-साथ गहलोत और पटेल तो सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद होते थे, राहुल गांधी के दो करीबी सहयोगी भी आसपास ही देखे जाते रहे- एक तरफ सचिन पायलट और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब न तो अहमद पटेल हैं, न कांग्रेस के साथ सिंधिया। एक को तो होनी ने छीन लिया और दूसरे को भाजपा ने।

● **विपिन कंधारी**

भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष पूरी तरह कमजोर होता जा रहा है। विपक्ष एकजुटता और मजबूती के लिए जो भी प्रयास करता है, वह सफल नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह यह है कि विपक्ष के नेता अपना-अपना वर्चस्व चाहते हैं। इस कारण चुनावी मैदान में विपक्ष बिखर जाता है। हालिया 5 राज्यों के चुनाव में विपक्ष की एकता पूरी तरह गायब रही। इसका फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भाजपा को मिला। दरअसल, विपक्ष को अपनी रीति और नीति नए सिरे से तय करनी पड़ेगी।

विपक्षी अपनी रीति-नीति नए सिरे से तय करें

5 राज्यों के चुनाव नतीजे कई दृष्टि से ऐतिहासिक होने के साथ ही भविष्य की राजनीति पर गहरा असर डालने वाले भी हैं। इन नतीजों को लेकर ममता बनर्जी समेत अन्य विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया उनके संकुचित दृष्टिकोण को ही बयान कर रही है, जबकि आवश्यक यह है कि वे जनता के मन-मिजाज को समझने के साथ राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर अपना एजेंडा स्पष्ट करें। इसलिए करें, क्योंकि चार राज्यों में भाजपा की जीत में राष्ट्रीय मुद्दों की भी भूमिका रही है। आज का मतदाता क्षेत्रीय मसलों के साथ ही राष्ट्रहित के मुद्दों को भी ध्यान में रखकर वोट देता है। इसी कारण जहां उप्र में योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में वापसी के साथ 37 साल से चला आ रहा मिथक तोड़ा, वहीं उत्तराखंड में यह धारणा खंडित की कि हर चुनाव में सत्ता बदल जाती है। चार राज्यों में भाजपा की जीत की तरह पंजाब में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी अकल्पनीय प्रदर्शन कर बड़ा संदेश दिया है।

राजनीतिक रूप से सबसे अहम राज्य उप्र में भाजपा ने सपा की चुनौती को जिस तरह मात दी, उसका महत्व इसलिए अधिक है, क्योंकि ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि भाजपा को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ेगा और कथित किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी और हाथरस जैसे कांड उसे बहुत महंगे पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लखीमपुर खीरी समेत 23 जिलों में विरोधी दलों का खाता भी नहीं खुला। उप्र में भाजपा को कोविड महामारी से उपजी कठिन चुनौतियों के बीच भी जीत इसलिए मिली, क्योंकि जनता ने पिछले पांच साल सुशासन को महसूस किया और विपक्षी दलों के दावों पर भरोसा नहीं किया। कथित किसान आंदोलन के बहाने भाजपा को किसान विरोधी साबित करने की कोशिश जाट बहुल पश्चिमी उप्र में भी नाकाम रही। इस नाकामी की बड़ी वजह यह रही कि आम किसान यह देख रहा था कि भाजपा किसान सम्मान निधि समेत अन्य योजनाओं से उसकी समस्याएं हल करने की हर संभव कोशिश कर रही है।

सपा ने भाजपा को चुनौती अवश्य दी और अपनी सीटें एवं वोट प्रतिशत भी बढ़ाया, लेकिन वह यादव-मुस्लिम समीकरण बनाकर भी आगे इसलिए नहीं बढ़ सकी, क्योंकि ऐसा कोई खाका पेश करने में नाकाम रही, जिस पर जनता भरोसा कर पाती। मुस्लिमों और यादवों की गोलबंदी सीमित असर तो डाल सकती है, लेकिन वह निर्णायक जनादेश नहीं दिला सकती। सपा को यह भी समझना होगा कि ध्रुवीकरण के जवाब में भी ध्रुवीकरण होता है।

भाजपा ने अपने राष्ट्रवादी एजेंडे के साथ अपनी राजनीति को जो स्वरूप प्रदान किया है, विपक्ष को उसकी गहराई में जाने की आवश्यकता

मोदी का स्टेमिना विरोधियों पर भारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी परेशान हैं कि मोदी थकते नहीं हैं। मोदी 72 साल के होने जा रहे हैं लेकिन उनकी शारीरिक चुस्ती और स्टेमिना ने विरोधियों को हैरान कर दिया है। मोदी चुनाव जीतने के लिए ना सिर्फ मेहनत करते हैं बल्कि एक-एक कदम सोच समझकर उठाते हैं। उनके अंदर दूरदर्शिता है। मोदी कितनी दूर की सोचते हैं इसका एक उदाहरण अहमदाबाद में नजर आया जब उन्होंने गुजरात के गांव-गांव से एक लाख से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों को बुलाया और उनके साथ लंबी बात की। मोदी ने उन्हें गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के कई सुझाव दिए। अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मोदी ने पंचायत के नेताओं के साथ इतना समय क्यों बिताया। नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस राजनीति पर रहता है। वे सोते-जागते देश की जनता और भाजपा के बारे में सोचते रहते हैं। यही कारण है कि देशभर में भाजपा विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच सक्रिय रहती है और चुनावों में इसका जमकर फायदा उठाती है।

है। जो लोग भाजपा को हिंदुत्ववादी करार देकर उसे सांप्रदायिक बताते हैं, वे भारत के सांस्कृतिक स्वरूप को नहीं समझते। भाजपा ने इसी स्वरूप को अपनी राजनीति का एक आधार बनाया है। जो हिंदुत्व भाजपा के डीएनए में है, वह सनातन संस्कृति का संस्कार है। जब कोई इस संस्कार को नकारता है या भारतीयता के पर्याय हिंदुत्व को लांछित करता है तो जनता में उसकी प्रतिक्रिया होती है, जिसका लाभ भाजपा उठाती है। इसी कारण विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे का कोई तोड़ नहीं खोज पा रहा है। चार राज्यों और खासकर उप्र में भाजपा ने डबल इंजन **सरकार की क्षमता प्रदर्शित** कर जीत हासिल की। यह जीत इसलिए आसान हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा शासन में कानून एवं व्यवस्था की बदहाली और जंगलराज वाले खौफ को बयान करने में सफल रहे। यह एक तथ्य है कि योगी सरकार कानून का राज कायम करने में सफल रही।

उत्तराखंड में भाजपा ने कांग्रेस की बदहाली का भी फायदा उठाया। तीन बार मुख्यमंत्री बदले जाने के बावजूद पुष्कर सिंह धामी बिगड़ते हालात संभालने में सफल रहे। कांग्रेस ने अपनी निष्क्रियता और निर्णयहीनता के कारण भाजपा की राह आसान बना दी। अब यह भी साफ हो गया कि गांधी परिवार में न तो कांग्रेस को दिशा देने की राजनीतिक सूझबूझ है और न ही यह समझने की क्षमता कि तमाम समस्याओं की जड़ में खुद उसका रवैया है। एक समस्या यह भी है कि कांग्रेस राष्ट्रीय मसलों पर वैसी ही संकीर्णता दिखाने लगी है, जैसी क्षेत्रीय दल दिखाते हैं। उत्तराखंड में राहुल गांधी ने हरीश रावत पर भरोसा नहीं किया और पंजाब में अमरिंदर सिंह पर। नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पर अमरिंदर को मुख्यमंत्री पद से अपमानजनक तरीके से हटाकर कांग्रेस ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। रही-सही कसर चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू की लड़ाई ने पूरी कर दी। इसका लाभ आप को मिला, जो पहले से ही पंजाब में अपनी जड़ें जमा रही थी। उसे कांग्रेस की आपसी लड़ाई के साथ ही भरोसा खो चुके अकाली दल के कारण प्रचंड जीत मिली। यह जीत क्षेत्रीय दलों के लिए एक सबक भी है, लेकिन आप के नेताओं को यह ध्यान रखना होगा कि उनके सामने उन समस्याओं से पार पाने की चुनौती भी है, जिनसे आज पंजाब जूझ रहा है। पंजाब सरीखे सीमांत राज्य का शासन चलाने के लिए कहीं अधिक राजनीतिक परिपक्वता की आवश्यकता है।

जब भाजपा चार राज्यों में मिली जीत को 2024 के आम चुनाव में विजय के आधार के रूप में देख रही है, तब एक खास सोच वाले लोग उसकी सफलता को लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती बता रहे हैं। आम तौर पर ये वही लोग हैं जिनका एजेंडा ही हर सूरत में भाजपा का अंध विरोध करना है। उन्हें न तो भारतीयता की समझ है और न ही राष्ट्रवाद की। इसी समझ का अभाव कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों में भी है। मोदी को अलोकतांत्रिक बताने वाले यह देखने से इनकार करते हैं कि कांग्रेस समेत अन्य दल किस तरह परिवारवाद में डूबे हैं और सामंती तरीके से संचालित हो रहे हैं। आखिर जो दल अपने परिवार हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हों, वे समाज और लोकतंत्र का भला कैसे कर सकते हैं? इसी सवाल पर प्रधानमंत्री ने फिर यह कहा कि परिवारवादी राजनीति ने राज्यों को पीछे धकेला है और चूंकि मतदाता इसे समझ चुके हैं, इसलिए वे ही एक दिन इस राजनीति का सूर्यास्त करेंगे। विपक्षी दलों के लिए यही बेहतर है कि वे जनादेश के संदेश को सही से समझें और अपनी रीति-नीति नए सिरे से निर्धारित करें। ऐसा करके ही वे अपना और देश का भला कर सकेंगे। उप्र, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भाजपा की शानदार जीत के तुरंत बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात की ओर रुख किया है, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है और पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं।

चार राज्यों में जीत का जश्न मनाने और दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद अगले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंचे और वहां रोड शो किया। उन्होंने भाजपा के सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों और पंचायत महासम्मेलन को भी संबोधित किया। ऐसे समय में जब बाकी नेता उप्र, पंजाब के चुनाव प्रचार की थकान उतारने में लगे हैं, मोदी पूरी ऊर्जा से अपने अगले अभियान में जुट गए।

नरेंद्र मोदी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और गुजरात में पिछले 27 साल से भाजपा की सरकार है। मोदी की जगह कोई और नेता होता तो ऐसे राज्य में चुनाव की ज्यादा चिंता नहीं करता लेकिन मोदी ने अभी से ही गुजरात के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। वे किसी भी चुनौती को हल्के में नहीं लेते। मोदी की गुजरात यात्रा का दृश्य उनकी ऊर्जा का एक बड़ा प्रमाण है। एयरपोर्ट से भाजपा ऑफिस तक खुली जीप में सवार होकर उन्होंने मेगा रोड शो किया। 10 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान दोनों ओर जयकारे लगाने वाले समर्थक थे। पार्टी दफ्तर में उन्होंने भाजपा के सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों और राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों को गुजरात चुनावों के लिए रोडमैप दिया।

● **इन्द्र कुमार**

कमजोर विपक्ष बना भाजपा की मजबूती

कमजोर विपक्ष ने भाजपा का काम आसान कर दिया। विपक्ष लगातार नेगेटिव कैंपेन में लगा रहा। चुनाव से पहले विपक्ष के नेता पूरी सीन से नदारद रहे। कोरोना महामारी के दौरान कहीं जमीन पर नजर नहीं आए। यह सब बातें विपक्षी दलों के खिलाफ गईं और भाजपा ने इन्हीं बातों के आधार पर बाजी एक बार फिर अपने नाम कर ली। आपको याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष के नेता कहते थे कि किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उप्र में भाजपा साफ हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस लखीमपुर खीरी की घटना (भाजपा नेता के बेटे के वाहन ने प्रदर्शनकारियों को कुचल दिया था) को लेकर बहुत हंगामा किया गया उस इलाके में भाजपा सभी 8 सीटों पर जीत गई। फिर यह भी दावा किया जा रहा था कि भाजपा को छोड़कर अखिलेश के साथ गए ओबीसी नेता (ओपी राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी) योगी को हरा देंगे, लेकिन यहां भी सब उल्टा हो गया।

पुरानी पेंशन की सौगात

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चौथी बार विधानसभा में बजट पेश किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई लोक लुभावन घोषणाएं की हैं। बजट के जरिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को कई सौगातें दी हैं। विशेषज्ञों की राय है कि इस बजट का बड़ा असर 2023 में देखने को मिलेगा। राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। इससे प्रदेश के कर्मियों में खुशी की लहर है। इसके साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन में बढ़ोत्तरी की गई है।

राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2004 और इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की। बजट में इसकी घोषणा कर दी है। इसके बाद प्रदेशभर के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। पूरे प्रदेश में सरकारी कर्मचारी खुशी मना रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसका बड़ा असर 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बजट भाषण के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन में भी बढ़ोत्तरी की घोषणा की है। जनपद अध्यक्षों का मानदेय 6 हजार से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है। इसके साथ ही जनपद उपाध्यक्षों का मानदेय चार से बढ़ाकर छह हजार कर दिया गया है। जनपद पंचायत सदस्यों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 5 हजार कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बजट में विधायक निधि की राशि बढ़ा दी गई है। विधायक निधि को 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया गया है। इससे क्षेत्र के विकास में विधायकों को मदद मिलेगी।

वहीं, बस्तर संभाग में डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स का गठन होगा। इस नवीन कैडर से बस्तर संभाग में कठिन परिस्थितियों में कार्यरत सहायक आरक्षकों को पदोन्नति और वेतनभतों का लाभ मिलेगा। राज्य के शहीदों के सम्मान में रायपुर में छत्तीसगढ़ **अमर ज्योति स्मारक** और पुलिस मेमोरियल टॉवर की स्थापना की जाएगी। बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मालखरौदा, बलरामपुर, राजपुर, धमधा, भोपालपटनम, भैरमगढ़, बागबाहरा, भरतपुर, खड़गवां-चिरमिरी, तिल्दा -नेवरा और सहसपुर-लोहारा में अनुविभागीय कार्यालय हेतु 77 पदों के सेटअप का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही व्यापमं और छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग की तरफ से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में स्थानीय प्रतिभागियों का परीक्षा शुल्क माफ करने की घोषणा सरकार ने की है।

इस बजट में मुख्यमंत्री ने बतौर वित्तमंत्री होकर हर समुदाय के लिए कुछ न कुछ बजट में धनराशि का प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2022-23 का राज्य बजट पेश करते हुए कई ऐतिहासिक घोषणाएं कीं। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को परीक्षा शुल्क से राहत दी गई है। वहीं राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा उनकी बजटीय घोषणाओं में किसानों को कृषि कार्य के लिए बिजली मुफ्त देने की भी बात कही गई है।

पूरे बजट को देखा जाए तो इसमें ग्रामीण, बेरोजगार, किसान और सेवानृवित्त कर्मचारियों पर मुख्यरूप से ध्यान दिया गया। बघेल द्वारा बजट के माध्यम से की गई उनकी घोषणाओं की चर्चा तो हो ही रही है लेकिन इसमें सबसे अधिक चर्चा उनके द्वारा इस बार बजट पेश करने के लिए गोबर से बना बैग लेकर विधानसभा पहुंचने को लेकर रही है। अपने बजटीय भाषण में बघेल ने कहा कि यह बजट सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के महात्मा गांधी के मूल मंत्र को साकार करने का एक प्रयास है। बघेल ने वर्ष 2022-23 का राज्य के लिए 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया है। जिसमें राज्य के कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा दिलाने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई है। 1 जनवरी, 2004 एवं इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। इससे राज्य के करीब 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा।

बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित छत्तीसगढ़ मॉडल की झलक देखने को मिली। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि 6 हजार से बढ़ाकर 7 हजार कर दी गई है। वहीं बजट में छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को भी बड़ी राहत प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक मंडल और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में अब अभ्यर्थियों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। इसके अलावा गौण खनिजों में भ्रष्टाचार और कालाबाजारी की शिकायत पर रोक लगाने अब माइनिंग का पूरा अधिकार पंचायत के पास होगा। पंचायतों की अनुमति के बगैर माइनिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

● **अक्स ब्यूरो**

2023 में दिखेगा बजट का असर

गोठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। स्थानीय खाद्य उत्पादों और लघु वनोपज के मूल्यवर्धन के लिए प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी। बांस और लकड़ी के शिल्प, धातु शिल्प और अन्य हस्तशिल्प से संबंधित लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए स्थानीय युवाओं को सहायता की जाएगी। इसके साथ ही बस्तर संभाग में डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स का गठन किया जाएगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। बजट में जो घोषणाएं की गई हैं, वह सीधे जनता से जुड़ी है। जानकार मानते हैं कि इस बजट का बड़ा असर जनता पर पड़ेगा। ऐसे में 2023 में भाजपा की राहें छत्तीसगढ़ में आसान नहीं होंगी। साथ ही कांग्रेस की राहें इससे आसान हो सकती हैं।

दक्षिण के सहारे तीसरा मोर्चा

करीब ढाई महीने बाद मुंबई में शरद पवार एक बार फिर से तीसरे मोर्चे के लिए अपना आशीर्वाद देते नजर आए। लेकिन 20 फरवरी को हुई बैठक में इस बार एनसीपी प्रमुख शरद पवार का समर्थन लेने वाला किरदार बदला हुआ था। इस बार शरद पवार के साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस प्रमुख के.चंद्रशेखर राव मौजूद थे। ठीक इसी तरह की बैठक बीते एक दिसंबर को ममता बनर्जी ने शरद पवार के साथ थी। उस समय उन्होंने यह कहते हुए तीसरे मोर्चे के गठन को बल दिया था कि यूपीए कही नही है।

बीते दिनों के.चंद्रशेखर राव ने शरद परवार के साथ-साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की थी। और उसके बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि हम लोग इस बात पर सहमत है कि देश में बड़े परिवर्तन की जरूरत है। हम जुल्म के साथ लड़ना चाहते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे ने बदलाव को देश की जरूरत बताते हुए कहते हैं कि मौजूदा राजनीतिक हालात में बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा, च्हमारा हिंदू बदला लेने वाला नहीं है।ज इसके अलावा शरद पवार से मुलाकात के बाद चंद्रशेखर राव ने कहा कि देश के कुछ और नेताओं से बातचीत के बाद हम च्एजेंडाज पेश करेंगे। इन नेताओं के बयानों से साफ है कि भाजपा के खिलाफ देश के सामने एक नया मोर्चा बनाने की तैयारी है। इसके लिए गैर भाजपा दलों को एक जुट करने पर जोर है।

ममता बनर्जी के बाद केसीआर की कवायद से साफ है कि अब दोनों नेता कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा बनाना चाहते हैं। क्योंकि ममता बनर्जी पहले से ही कांग्रेस में सेंध लगाकर उनके नेताओं को तृणमूल कांग्रेस में शामिल कर रही हैं। इसके अलावा वह यह भी कह चुकी है कि भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस में ताकत नहीं है। इसी तरह केसीआर भी गैर कांग्रेस दलों के साथ ही आगे बढ़ेंगे। क्योंकि तेलंगाना में उनकी सीधी टक्कर कांग्रेस से हैं। ऐसे में वह किसी भी हालत में राष्ट्रीय राजनीति के लिए राज्य की राजनीति में समझौता नहीं करेंगे। हालांकि पिछले कुछ समय से राव कांग्रेस के मुकाबले भाजपा को ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं।

केसीआर को आगे करने में ममता बनर्जी की अहम भूमिका रही है। उन्होंने 13 फरवरी को के चंद्रशेखर राव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को फोन करके गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की कवायद शुरू की है। असल में ममता बनर्जी राज्य सरकारों के साथ केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपालों के साथ चल रही खींचतान को मुद्दा बनाकर, भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करना चाहती हैं। और इस कड़ी में अब के.चंद्रशेखर राव भी उनके साथ हो गए हैं।

लेकिन इस कवायद में सबसे कमजोर कड़ी उत्तर प्रदेश है। क्योंकि चाहे ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव हो या फिर शरद पवार। इनमें से किसी भी राजनेता का जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं है। और दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। जहां पर 80 लोकसभा सीटें है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़,हरियाणा ऐसे राज्य हैं जहां पर भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। और दक्षिण के क्षेत्रीय दलों का इन राज्यों में कोई जनाधार नहीं है। और इन राज्यों में कुल मिलाकर लोकसभा की 185 सीटें आती हैं। इसके अलावा दिल्ली और पंजाब में भी दक्षिण के दल कमजोर हैं। इसके साथ ही देश की 200 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं, जहां पर कांग्रेस की भाजपा या अन्य दलों से सीधी टक्कर है।

अगर गैर भाजपाई दलों को देखा जाय तो करीब 226 लोकसभा सीटों पर ये दल असर रखते हैं। इसमें पश्चिम बंगाल में 42 लोक सभा सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48, तमिलनाडु में 39, तेलंगाना में 17 सीटें हैं। इसके अलावा झारखंड में 14, उड़ीसा 21, आंध्र प्रदेश में 25 और केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं। जहां पर गैर भाजपाई मुख्यमंत्री हैं। लेकिन समस्या यही है कि इन गैर भाजपा शासित राज्यों में झारखंड और महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है। वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के रिकॉर्ड को देखते हुए भाजपा विरोधी गुट में शामिल होना आसान नहीं है। वहीं केरल में वाम दलों की सरकार है, जिसके लिए ममता बनर्जी को समर्थन देना आसान नहीं। इसीलिए कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा केसीआर की कवायद पर कहा कि वह भाजपा के विरोध में विपक्षी गठबंधन बनाना चाह रहे हैं। क्या कांग्रेस के बगैरर यह संभव है? साथ में उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह सवाल अघाड़ी के नेताओं से है।

● **बिन्दु माथुर**

यूपी के नतीजे पर बहुत कुछ निर्भर

अगर के.चंद्रशेखर राव की मीटिंग की टाइमिंग को देखा जाय तो उन्होंने शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ बैठक उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में चल रहे चुनाव के दौरान की है। साफ है कि 10 मार्च के नतीजे तीसरे मोर्चे की कवायद को बहुत हद तक प्रभावित करेंगे। अगर यूपी में भाजपा की बहुमत के साथ सरकार बनती है तो निश्चित तौर भाजपा के अपने सहयोगी दलों पर कहीं ज्यादा प्रभाव बढ़ जाएगा और दूसरे दल भी एनडीए के कुनबे में 2024 के लिए साथ आ सकते हैं। लेकिन अगर भाजपा हारती है और समाजवादी पार्टी या दूसरे समीकरण के जरिए सरकार बनती है तो तीसरा मोर्चे के लिए काफी कुछ सकारात्मक होगा। और ऐसी स्थिति भाजपा के सहयोगी भी उसका साथ छोड़ सकते हैं। ऐसे में 10 मार्च का दिन 2024 की राजनीतिक तस्वीर के लिए बेहद अहम दिन होने वाला है।

पुरानी पेंशन का दांव

राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने फरवरी के दूसरे पखवाड़े में एक ऐसा फैसला कर लिया, जिसने देशभर की राज्य सरकारों को भी इस पर अमल करने को मजबूर कर दिया है। दरअसल गहलोत सरकार ने एक बड़े फैसले में कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन बहाल करके देश के दूसरे हिस्सों में भी कर्मचारियों के लिए बड़ी उम्मीद जगा दी है। अब केंद्र सरकार पर भी इसका दबाव बनेगा। देशभर के कर्मचारी संगठनों की यह बड़ी मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। राजनीति के लिहाज से यह बड़ा फैसला है और देश में अगर दूसरे राज्य भी इसे लागू करते हैं, तो करोड़ों कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। निश्चित ही गहलोत सरकार के पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के ऐलान के बाद देश के बाकी राज्यों में भी ये बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। उन्होंने निश्चित ही बड़ा दांव चल दिया है।

अब मोदी सरकार पर भी केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की इन राज्यों में भी सरकारी कर्मचारी संगठन सरकारों के सामने ये मांगें पहले से रखते रहे हैं और अब गहलोत सरकार के फैसले के बाद उन्हें कहने का अवसर मिल गया है। उप्र में विधानसभा चुनाव के घोषणा-पत्र में समाजवादी पार्टी ऐसा ही वादा कर चुकी है। देश के कई राज्यों में सरकारी कर्मचारी संगठन फिर से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए लगातार सरकार पर दबाव बनाते रहे हैं। इसके लिए वे सड़कों पर आंदोलन भी कर रहे हैं। निश्चित ही गहलोत सरकार ने कर्मचारियों की वाहवाही लूट ली है। राजनीतिक दलों में **पुरानी पेंशन योजना** की चर्चा रही है। कांग्रेस इसका समर्थन करती रही है। अब करोड़ों कर्मचारी आस लगाए हैं कि पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल हो जाएगी। वैसे केंद्र सरकार ने जब नई पेंशन योजना (एनपीएस) लागू की थी, लेकिन राज्यों पर इसे लागू करने की अनिवार्यता नहीं थी। हालांकि धीरे-धीरे कमोबेश सभी राज्यों ने इसे अपना लिया। लेकिन जल्दी ही नई पेंशन योजना का विरोध भी शुरू हो गया, जो आज तक जारी है।

पुरानी पेंशन बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहे कर्मचारी संगठनों ने राजस्थान सरकार के फैसले का स्वागत करने के साथ ही अब राज्यों और केंद्रीय स्तर पर इस लड़ाई को और तेज करने का आव्हान भी किया है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े नेताओं का कहना है कि राजस्थान सरकार के फैसले से कर्मचारी देशभर में बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत का इस फैसले के लिए संगठन आभार करते हैं; क्योंकि उन्होंने कर्मचारियों की भावनाओं को समझा। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह रावत का कहना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनपीएस कार्मिकों के लिए जो फैसला लिया है, वह ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि देश के लाखों एनपीएस कर्मचारियों में राजस्थान सरकार के इस फैसले से उत्साह है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिन-रात मेहनत करके एनपीएस कार्मिकों ने अपने संघर्ष से पुरानी पेंशन बहाली की आवाज को लगातार सड़क से सदन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। राजस्थान सरकार के सराहनीय कदम से अन्य राज्यों में भी उम्मीद जगी है। अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पुरानी पेंशन बहाली को गंभीरता से लें, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बनने वाला है।

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को अब सेवानिवृत्त होने पर पहले के सरकारी कर्मचारियों की तरह ही पूरी पेंशन मिलेगी। बता दें कि सन् 2004 में पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर दिया गया था। सन् 2004 से पहले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित पेंशन मिलती थी। यह पेंशन सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के वेतन पर आधारित होती थी। इस योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिजनों को भी पेंशन का प्रावधान था। अटल बिहारी वाजपेई की सरकार ने अप्रैल, 2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया था और नई पेंशन योजना लागू की गई थी। इसके बाद राज्यों ने भी नई पेंशन योजना को अपना लिया। बता दें कि पिछले कई वर्षों से सरकारी कर्मचारी फिर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग के साथ विरोध-प्रदर्शन करते रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को भी इसका इंतजार है। कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को भी एनपीएस से ओपीएस में ला सकती है। इनमें वो कर्मचारी शामिल होंगे, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद इसकी सुगबुगाहट शुरू हुई है।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

पुरानी और नई पेंशन में अंतर

पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) और नई पेंशन योजना यानी न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) में बड़ा अंतर है। ओपीएस में कर्मी की पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं होती, जबकि एनपीएस में उसके वेतन से 10 फीसदी (बेसिक+डीए (महंगाई भत्ता) की कटौती होती है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ सुविधा है, लेकिन एनपीएस में यह नहीं है। ओपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है और इसका भुगतान सरकारी खजाने से होता है। लेकिन एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है और बाजार के मिजाज पर इसका भुगतान निर्भर है। जाहिर है बाजार से मिलने वाले रिटर्न की कोई गारंटी नहीं मिलती। ओपीएस में सेवानिवृत्ति के समय अंतिम बेसिक वेतन की 50 फीसदी तक निश्चित पेंशन मिलती है, जबकि एनपीएस में निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है। ओपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है, लेकिन एनपीएस में यह नहीं होता। ओपीएस सेवानिवृत्ति के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है, एनपीएस में इसका अस्थायी प्रावधान ही है। ओपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने की स्थिति में फैमिली पेंशन मिलती है, जबकि एनपीएस ऐसा होने पर फैमिली पेंशन तो मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसा सरकार जब्त कर लेती है। ओपीएस में सेवानिवृत्ति पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का आयकर नहीं लगता, लेकिन एनपीएस में शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा, उस पर कर (टैक्स) देना पड़ेगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से कोई निवेश नहीं होता, लेकिन एनपीएस में सेवानिवृत्ति पर पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40 फीसदी पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी है। ओपीएस में 40 फीसदी पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, एनपीएस में यह प्रावधान नहीं है। ओपीएस में मेडिकल सुविधा है, लेकिन एनपीएस में इसका कोई निश्चित प्रावधान नहीं है।

भीख के कटोरे में तब्दील पूर्वांचल

पूर्वांचल का नाम आते ही देश के अन्य हिस्से हों या भारत की अर्थव्यवस्था को करीब से जानने वाले विदेशी सबके जेहन में बस एक ही तस्वीर सामने आती है। वह है पिछड़ापन, बेकारी व लाचारी। जिनको ये सभी लोग पूरबिया व बिहारी के नाम से जानते हैं। यहां के लोगों के पास आजादी के पूर्व या बाद के दौर में राजनीतिक संकट व गुलामी के खिलाफ आवाज उठाने व कुर्बानियों की कहानियों से भरे इतिहास की मोटी गठरी मौजूद है। इस पर चर्चा करने के बजाय हम यहां बात करेंगे इसके पिछड़ेपन के कारणों की।

उप्र का पूर्वांचल भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में चीनी उद्योगों की भूमिका को बेहद प्रमुख माना गया है। यहां चीनी उत्पादन में लागत काफी कम है और जलवायु परिस्थितियां और मिट्टी की स्थिति गन्ने के उत्पादन के अनुकूल हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह भारत की सबसे उपजाऊ भूमि पर स्थित है जिसे दोआब कहा जाता है जो भूमि का एक अत्यंत उपजाऊ बेल्ट है। जिसमें गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गोंडा, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद प्रमुख रूप से शामिल हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र में चीनी कारखाने मुख्य रूप से गंगा मैदान के उत्तरी भाग में, पंजाब के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के साथ-साथ हरियाणा के पूर्वी भागों में स्थापित किए गए। बिहार में, वे मूल रूप से उत्तरी पश्चिमी जिलों में विशेष रूप से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण, पटना, सारण और गोपालगंज में चालू किए गए। उप्र में चीनी उद्योगों के संकेंद्रण के दो क्षेत्र हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर जिले तथा दूसरा बस्ती, गोंडा, सीतापुर, देवरिया और गोरखपुर जिले।

पूर्वांचल में विशेषकर अविभाजित देवरिया जिले का चीनी उद्योग के मामले में सुनहरा अतीत रहा है। राज्य के 38 जिलों में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती रही। जिसमें देवरिया का इलाका चीनी का कटोरा कहा जाता था। यहां कभी 14 चीनी मिलें हुआ करती थीं। यूं देखें तो लखनऊ से पूरब की तरफ ट्रेनों से बढ़ते ही छपरा रेलखंड पर जरवल रोड से शुरू होकर बभनान, बस्ती, खलीलाबाद, सरदार नगर, गौरी बाजार, बैतालपुर, देवरिया, भटनी व बिहार के हिस्से में प्रवेश करते ही सीवान, पचरूखी के अलावा आसपास में प्रतापपुर, मढ़ौरा तथा पडरौना के रूट पर सेवरही, तमकुहीराज, कसानगंज व जिले की सीमा से सटे बिहार के गोपालगंज का थावे, गोपालगंज, कठकुईयां, सासामुसा आदि स्थानों पर चीनी मिलें स्थापित की गई थीं।

पंजाब के कर्मचंद थापर ने देवरिया के बैतालपुर में चीनी मिल की स्थापना की थी। गौरी बाजार में भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय की चीनी मिल थी। इसके अलावा अन्य मिलें प्राइवेट ही हुआ करती थीं। श्रमिक नेता शिवाजी राय कहते हैं कि वर्ष 1969 में विभिन्न क्षेत्रों के प्राइवेट उद्यमों के सरकारीकरण की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुहिम शुरू की थी। इस दौरान बैंक, कोयला क्षेत्र, बीमा कंपनी समेत चीनी मिलों के भी राष्ट्रीयकरण की सरकार ने एक शुरुआत की। जिसका नतीजा रहा कि देवरिया शहर के अलावा भटनी व बैतालपुर की मिल शुगर कारपोरेशन के हाथों में चली गई। वह एक ऐसा दौर था जब शिक्षक की नौकरी छोड़कर चीनी मिल में लोग काम तलाशते नजर आए। चीनी मिलों के द्वारा जारी गन्ने की पर्चियां वियरर चेक के समान इसे व्यापारी मानते थे। जिसे बंधक रखकर आसानी से व्यापारियों से किसान सामान ले लेते थे।

चीनी मिलों के सुनहरे अतीत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये न केवल किसानों के गन्ने का समय से भुगतान करती थीं, बल्कि उनके बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, सड़क आदि का निर्माण भी कराती थीं। कुशीनगर के सेवरही का किसान डिग्री कॉलेज वहां के **चीनी मिल** ने ही खोला था। जिसका नतीजा यह है कि आज भी कॉलेज का प्रबंधक पदेन केन यूनियन का चेयरमैन होता है। देवरिया शहर में बाईपास मार्ग के रूप में सीसी रोड का निर्माण भी यहां के चीनी मिल ने ही सर्वप्रथम की थी। इसी तरह अन्य मिलों द्वारा भी शिक्षण संस्थान, अस्पताल, सड़क आदि का निर्माण कराया गया था। गन्ना समितियों द्वारा किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक समेत अन्य समान निशुल्क या अनुदान पर मिला करता था। गन्ना किसानों के सुनहरे अतीत की जब हम चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि चीनी मिलों के पूर्व से ही यहां खांडसारी का कार्य ऊंचाई पर था। इसका केंद्र रामपुर कारखाना के अलावा बरहज का बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। जहां बड़ी संख्या में छोटे-छोटे खांडसारी मिल हुआ करती थीं। जिसमें किसानों के गन्ने की अच्छी खपत हो जाया करती थी, वहीं मजदूरों को काम भी मिल जाता था। यही नहीं इससे कारोबारियों के भी अच्छे दिन कटते थे। यहां तैयार किए गए गुड़ का जल मार्ग से विदेशों तक निर्यात किया जाता था। इसके बाद यहां चीनी मिलों की स्थापना शुरू हुई। जिसने देवरिया जिले को चीनी के कटोरे के रूप में पहचान दिलाई।

● लखनऊ से मधु आलोक निगम

11 करोड़ आबादी वाला इलाका उद्योग विहीन

अस्सी के दशक तक पूर्वांचल में स्थापित छोटे-छोटे उद्योग यहां के विकास की रीढ़ रहे। देवरिया समेत आसपास के जिलों में जहां चीनी उद्योग प्रमुख था वहीं वाराणसी में कालीन व साड़ी उद्योग, भदोही में कारपेट उद्योग, मऊ में साड़ी उद्योग, संतकबीर नगर में हथकरघा व पीतल बर्तन उद्योग आर्थिक समृद्धि के सबसे बड़े कारक थे। इसके विस्तार के लिए सरकारी स्तर पर कोई पहल न होने से ये मरते चले गए। आधुनिकीकरण के दौर में मशीनीकरण के आगे ये परंपरागत उद्योग धीरे-धीरे खत्म हो गए। जिसका नतीजा यह रहा कि पूर्वांचल का तकरीबन 11 करोड़ से अधिक आबादी वाला हिस्सा अब मात्र सस्ते मजदूरों का हब बनकर रह गया है। ये मजदूर संकट में महानगरों में जाकर सस्ते दर पर अपने श्रम को बेचने को मजबूर हो रहे हैं। कामगारों का पलायन रोकने के लिए मनरेगा भी सहायक नहीं साबित हो पा रही है। योजना की मूल संकल्पना बजट नहीं बल्कि लोगों के हाथों के लिए काम थी। और वह भी मांग के अनुसार। इसके तहत यह व्यवस्था बनाई गई कि मनरेगा के तहत जॉब कार्डधारकों को हर हाल में एक वर्ष के अंदर मजदूरों को 100 दिन कार्य उपलब्ध कराया जाएगा। इस कानून के विपरीत धरातल पर स्थिति काफी खराब है। देवरिया जिले के भलुवनी ब्लॉक के सुरहा के ग्राम प्रधान दीनदयाल यादव कहते हैं कि मौजूदा हालात में एक मजदूर को वर्ष में 30 दिन भी काम नहीं मिल पा रहा है।

लालू की सजा पर सियासत

चारा घोटाला राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद का पीछा छोड़ता नहीं लग रहा है। अब झारखंड में अंतिम (पांचवें) मामले में डोरंडा कोषागार से 139.50 करोड़ रुपए निकासी के सिलसिले में 5 साल जेल और 60 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला है। 74 साल के लालू प्रसाद कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं और सियासी परिदृश्य से मोटे तौर पर उनका गायब रहना उनकी पार्टी के लिए भी मुश्किलें पैदा कर रहा है। सही है कि उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने 2020 के पिछले विधानसभा चुनावों में पार्टी को काफी मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है और थोड़े ही अंतर से वे सरकार बनाने से चूक गए। शायद लालू प्रसाद की मौजूदगी से फर्क पड़ सकता था। उनके समर्थक इसी वजह से इन मामलों के जरिए उन्हें सियासी फलक से दूर रखने की साजिश का आरोप लगाते हैं। और यह नए सियासी विवाद का सबब भी बनता जा रहा है।

दरअसल अस्सी-नब्बे के दशक में पशुपालन के मद में विभिन्न कोषागारों से करीब एक हजार करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई थी। सीबीआई ने 66 मामले दर्ज किए थे, जिसमें छह में लालू प्रसाद को भी अभियुक्त बनाया गया। छठा मामला बांका कोषागार से 46 लाख रुपए की अवैध निकासी का है। पटना में सीबीआई की विशेष अदालत में इसकी सुनवाई चल रही है। लालू से जुड़े **इन छह मामलों** में 211 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का आरोप है, जिनमें लालू प्रसाद को 7 बार जेल जाना पड़ा है। 5 मामलों में कुल साढ़े 32 साल जेल की सजा हुई है और 1.65 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है, जिनमें वे करीब साढ़े तीन साल जेल में रहे। हालांकि ज्यादा समय बीमारी के नाम पर अस्पताल में गुजरा। अब सीबीआई की अदालत ने डोरंडा कोषागार से निकासी के मामले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की जांच का आदेश दिया है। ईडी ने दुमका और देवघर कोषागार से अवैध निकासी को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। सीबीआई कोर्ट से सजा के बाद लालू प्रसाद की ओर से हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई है।

उधर, बुढ़ापे में लालू के प्रति उपजती सहानुभूति से भी राजनीति गरमा गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, 'मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। जो लोग आज उनके साथ हैं, वे भी केस करने वालों में थे। वे मेरे पास भी आए थे कि मैं भी इसमें पार्टी बन जाऊं पर मैंने इनकार कर दिया था। केस करने वालों से ही पूछिए।' राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी को यह थोड़ा तीखा लगा। उन्होंने कहा, 'सारी दुनिया जानती है कि चारा घोटाले की सीबीआई से जांच के लिए हाइकोर्ट में जो याचिका दी गई, उसमें एक पर दस्तखत करने वाला मैं भी था, दूसरे पर वृषण पटेल थे। आजकल हम दोनों लालूजी के साथ हैं। नीतीश कुमार यह क्यों भूल रहे हैं कि यह कोई व्यक्तिगत फैसला नहीं था, पार्टी का था जिसके वे नेता थे। जॉर्ज फर्नांडीस ने हमें फोन किया कि हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी सिर्फ भाजपा दिखाई पड़ेगी। तब विमान से मैं आया और दस्तखत किया। भाजपा सेहरा लेना चाहती थी कि हम लालू प्रसाद से लड़ रहे हैं। मकसद था कि चुनाव में लालू को नहीं पटक पा रहे तो अदालत में दूसरे तरीके से उन्हें घेरा जाए। मकसद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना था। जहां तक चारा घोटाले का सवाल है, इसमें सब शामिल हैं। नीतीश बताएं कि उनकी श्याम बिहारी सिन्हा से मुलाकात हुई थी कि नहीं। खुद सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने भी चारा घोटाले का पैसा खाया है। मोदी बताएं कि वे बयान पर कायम हैं या नहीं।' सुशील मोदी कहते हैं, 'लालूजी की सजा से मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आश्चर्य यह है कि जिन लोगों ने उन पर मुकदमा दायर किया, शिवानंद तिवारी, वृषण पटेल और प्रेमचंद्र मिश्र वे तमाम लोग लालू के सलाहकार हैं या उनके साथ हैं और आरोप हम पर लगाया जाता है कि हमने फंसा दिया।' जो भी हो, यह विवाद इन दिनों बिहार में एक राजनीतिक रूप लेता जा रहा है, जिसके अक्स अगले चुनावों में दिख सकते हैं।

पशुपालन घोटाले में सजा के बावजूद लालू अपने समर्थकों में लोकप्रिय रहे हैं। उनकी अदा भी निराली रही है। कुछेक वाकये याद कीजिए। 9 जनवरी 1999 की बात है। लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थीं। लालू बेऊर जेल से जमानत पर निकले तो हाथी पर बैठकर अपने आवास पहुंचे थे। फिर, अलग राज्य बन चुके झारखंड में 2002 में रांची की विशेष अदालत में पेशी थी। लालू पटना से अपने समर्थकों के हुजूम के साथ गरीब रथ पर सवार होकर पहुंचे थे। रथ के पीछे मीलों तक उनके साथ चलने वाली गाड़ियों का काफिला था, जगह-जगह उनके समर्थक उनके स्वागत में खड़े थे। आज बुढ़ापे की अवस्था में उनकी किडनी 20 प्रतिशत की क्षमता से काम कर रही है और वे अनियंत्रित बीपी, मधुमेह सहित डेढ़ दर्जन बीमारियों से ग्रस्त हैं। चलने में भी सहयोग की जरूरत पड़ती है। उनकी जेल यात्रा भी विवादों में रही। पटना में राबड़ी देवी का शासन था तो बीएमपी के गेस्ट हाउस को ही कैंप जेल बना दिया गया था। रांची में सहयोगी पार्टी की सरकार रही तो रिम्स के निदेशक का तीन एकड़ का बंगला उनके लिए जेल बना रहा।

● **विनोद बक्सरी**

लालू का जादू अभी भी कायम

बिहार में उनका जनाधार थोड़ी-बहुत टूटन के बावजूद बरकरार रहा है। लेकिन अब भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कहते हैं, 'सीबीआई अदालत से उन्हें इतनी सजा मिल चुकी है कि अब वे मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते। उनका बिहार में कोई असर नहीं रह गया है।' लेकिन उनकी पार्टी राजद ने तेजस्वी के नेतृत्व में 2020 के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया। लालू आज भी अपनी पार्टी में खासी अहमियत रखते हैं। हाल में 10 फरवरी को राजद कार्यकारिणी की पटना में बैठक में तेजस्वी को राजद अध्यक्ष बनाने की चर्चा उड़ी थी, जिस पर लालू प्रसाद ने विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि 11 अक्टूबर को दिल्ली में पार्टी के अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों के चुनाव होंगे।

चीन की सैन्य नीति

निरंतर जारी सैन्य सुधार

चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को सीएमसी द्वारा जारी 'सैन्य रणनीतिक दिशा-निर्देश' के रूप में रखा जाता रहा है और यह वर्गीकृत होता है। लेकिन 'रक्षा श्वेतपत्र' में इसके कुछ ब्यौरे जारी किए जाते हैं, जो कि सार्वजनिक दायरे में होता है। चीन में सैन्य सुधार निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। राष्ट्रपति शी ने उसे अधिक प्रोत्साहित किया है और लक्ष्य स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिए हैं। उन्होंने समझ लिया है कि 2049 तक एक महाशक्ति की हैसियत वाला एक शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र बनने के चीनी सपने को साकार करने के लिए सैन्य सुधार बेहद महत्वपूर्ण हैं। उनके रणनीतिक दिशा-निर्देश 2015 के रक्षा श्वेतपत्र में दर्ज किए गए और 2019 के इस श्वेतपत्र में इसे और मजबूती दी गई। 2015 में उन्होंने पीएलए के रूपांतरण को आकार देने के लिए विस्तृत सुधारों की घोषणा की। सीएमसी को ज्यादा स्वायत्तता दी गई और इसके चार सामान्य विभागों की जगह 15 उप-विभागों वाले संयुक्त स्टाफ विभाग का गठन किया गया। पीएलए को पूरी तरह समेकित किया गया और इसके सात सैन्य क्षेत्रों को तीन सेनाओं वाले पांच थिएटर कमांडों में बदल दिया गया। तीन नई सेनाओं का गठन किया गया- पीएलए ग्राउंड फोर्सेज, पीएलए रॉकेट फोर्सेज, पीएलए स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्सेज। स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्सेज में इलेक्ट्रोनिक युद्ध, साइबर युद्ध, मनोवैज्ञानिक युद्ध, अंतरिक्ष युद्ध के रणनीतिक भ्रम एवं संचार-इलेक्ट्रोनिक पहलू शामिल हैं।

चीन के राष्ट्रपति और 'सेंट्रल मिलिट्री कमीशन' (सीएमसी) के अध्यक्ष शी जिनपिंग ने सैन्य सुधारों के तहत सैन्य साजोसामान के मूल्यांकन तथा परीक्षण के लिए हाल में नए नियम लागू किए। इन नियमों के कारण चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) को हथियारों के विकास और खरीद के फैसले करने के लिए ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे। भारत की तरह चीन का डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस (डीआईबी) सरकारी महकमा है और रक्षा उत्पादन पर एकाधिकार रखता है। नए नियमों का लक्ष्य पीएलए और डीआईबी के बीच संबंधों को बेहतर बनाना और डीआईबी को अधिक कार्यकुशल बनाना है।

पहले, रक्षा प्रबंधन की जटिल व्यवस्था के कारण डीआईबी के निगम ही रक्षा तकनीक और हथियारों का विकास करने के मुख्य स्रोत थे और उन्हें बंधक जैसे ग्राहक पीएलए पर थोप दिया जाता था। फीडबैक मिलने के बाद सामान में सुधार और संशोधन किया जाता था। यूवान वांग मिलिट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी थिंक टैंक में एक शोधकर्ता झाउ चेनमींग ने कहा, 'पहले, हथियार बनाने वाली कंपनियां अपना उत्पाद खरीदने के लिए पीएलए पर जोर डालती थीं, चाहे उनकी जरूरत उन्हें हो या नहीं, क्योंकि सेना को कहा गया था कि वह रक्षा उद्योग में कामगारों की नौकरी बचाने के लिए उनके ऑर्डर मान लें।'

यह व्यवस्था काफी संतोषजनक ढंग से चलती रही क्योंकि अधिकतर हथियार मीडियम टेक्नोलॉजी वाले रूसी हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग पर आधारित होते थे। जब पीएलए ने बदलाव शुरू किया जिसके लिए अत्याधुनिक सैन्य तकनीक पर आधारित हथियारों और सपोर्ट सिस्टम की जरूरत थी, तब कंपनियां उम्दा जरूरतों को पूरा करने में अक्षम रहीं।

पिछले साल 'सैन्य उपकरणों के नियम' जारी किए गए ताकि अधिक आधुनिक हथियारों और दूसरे सैन्य उपकरणों का शोध और विकास किया जा सके और उत्पादित तथा चीनी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों का बेहतर प्रबंधन और रखरखाव किया जा सके। नए नियमों का मुख्य जोर विविध तरह के इलाकों और युद्धस्थलों में युद्ध के लिए तैनात सैनी उपकरणों के परीक्षण और मूल्यांकन पर था। पीएलए ने पिछले दो दशकों में खुद को तीसरे और चौथे पीढ़ी के सैन्य हथियारों और उपकरणों से लैस किया है। अब जो सुधार किए जा रहे हैं उनका जोर पांचवीं-छठी पीढ़ी के सैन्य हथियारों पर है।

चीन का डीआईबी बहुत बड़ा है। रक्षा से संबंधित दुनिया के 15 सबसे बड़ी फर्मों में से सात- नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, चाइना शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन, चाइना एरोस्पेस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, चाइना स्टेट इंडस्ट्री ग्रुप कॉर्पोरेशन और चाइना इलेक्ट्रोनिक टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन- चीन के सरकारी उपक्रम हैं। 2017 में इसने 4 अरब डॉलर मूल्य के हथियार निर्यात किए जिनमें जहाज, विमान, बख्तरबंद वाहन, मिसाइल, तोपें, ड्रोन और सेंसर शामिल थे।

चीन के डीआईबी को मैन्युफैक्चरिंग के विशाल आधार का सहारा हासिल है, जिसमें दुनिया का 25 फीसदी मैन्युफैक्चरंग उत्पादन होता है। इसमें से 50 फीसदी उत्पाद दोहरे उपयोग के लायक होते हैं। पीएलए की जरूरतें पूरी करने के अलावा इनके निर्यात की भी भारी संभावना है। चूंकि इसका वास्ता राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाले 'सीएमसी' से ही है इसलिए इसे पूर्णत: सरकारी होने का लाभ भी उपलब्ध है। 'मिलिट्री-सिविल' मिश्रण नीति विज्ञान व तकनीक से जुड़े शोध संस्थानों-विश्वविद्यालयों से संबंध बनाने की अनुमति देती है। रक्षा उत्पादन में लगने वाले 37 खनिजों में से 18 उसके यहां उपलब्ध हैं और बाकी 19 खनिजों का आयात करने के लिए उसने राजनयिक और व्यापार समझौतों के सहारे सप्लाई-चेन तैयार कर रखा है। अतीत में सबसे बड़ी खामी यह थी कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ बहुत सख्त थी और साम्यवादी व्यवस्था में प्रोत्साहनों का अभाव था। इसे 2015 के सुधारों के बाद आंशिक रूप से ठीक कर लिया गया और नए सीएमसी को ज्यादा अधिकार मिले। लोकतांत्रिक देशों की तरह वहां कोई वैधानिक, न्यायिक और मीडिया निगरानी नहीं है और सीएमसी के किसी गलत फैसले के गंभीर नतीजे हो सकते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि डीआईबी को जो कलपुर्जे चाहिए उनके लिए चीन बहुत हद तक अमेरिका और उसके मित्र देशों और रूस पर निर्भर है। आरएएनडी के मुताबिक, '2019 में, सेंटर फॉर एड्वान्स्ड डिफेंस स्टडीज (सी4एडीएस) ने पाया कि रूस नहीं बल्कि अमेरिका ही चीन के डीआईबी का सबसे बड़ा सप्लायर है और उसके आयातों में 20 फीसदी हिस्सा उसी का होता है।' वह विमान और नौसेना के लिए इंजन समेत पूरा का पूरा सैन्य उपकरण आयात करता है। तकनीकी शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए वह पश्चिमी देशों पर निर्भर है लेकिन विकसित देश भी चीन पर इतने निर्भर हैं कि इस निर्भरता का निकट भविष्य में लाभ उठाने की संभावना नहीं है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

खतरनाक मोड़ पर युद्ध

भारत समेत विश्व के कुछ चुनिंदा देशों द्वारा प्रयास के बावजूद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। रूसी हमले की तीव्रता से प्रतीत होता है कि रूसी सेना इन हमलों की तैयारी पहले से ही कर रही थी और बड़े पैमाने पर हमले करने की योजना थी। हमलों की वजह से यूक्रेन से जनता का भारी पलायन हुआ है और लोग यूक्रेन से सटे हुए आसपास के देशों में शरण ले रहे हैं। अब तक लगभग 20 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं जिनमें से आधे लोगों ने पोलैंड में शरण ली है, जबकि शेष अन्य पड़ोसी देशों में शरण ले चुके हैं।

हालांकि वर्तमान संघर्ष का कोई तत्काल उत्प्रेरक नहीं है और यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के निर्णय से रूस को उत्पन्न खतरे को ही हमलों की वजह माना जा रहा है। वैसे अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से यह कहा जा रहा है कि फिलहाल वे नाटो में शामिल होने के अपने निर्णय को लेकर तटस्थ हैं, जिससे एक बार तो ऐसा लगा कि युद्ध थम जाएगा, परंतु रूस का इरादा कुछ और ही लग रहा है। माना जा रहा है कि रूस या तो यूक्रेन या उसके बड़े भाग पर कब्जा करना चाहता है या फिर रूस समर्थित रिहायशी क्षेत्रों को यूक्रेन से अलग कर उन्हें रूस का हिस्सा बनाना चाहता है। परंतु रूस को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी अपेक्षा के विरुद्ध उसे यूक्रेन की सेना व स्थानीय जनता से भारी प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका और अन्य देशों ने युद्ध रोकने व संघर्ष विराम के अनेक प्रयास किए, रूस पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए, परंतु उनका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा जिसके परिणामस्वरूप रूस लगातार अपने हमले तेज करता जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी युद्ध रोकने के प्रयास किए गए, पर सुरक्षा परिषद में रूस द्वारा वीटो किए जाने की वजह से इस मामले में कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हमले की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया है, परंतु महासभा की शक्तियां सीमित होने के कारण संघर्ष रोकने में उसका कितना प्रभाव होगा, अभी यह आंकलन करना मुश्किल है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से विश्व के समक्ष अनेक चुनौतियां व प्रश्न पैदा किए हैं। क्या कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र जब चाहे किसी भी कमजोर देश पर कोई भी कारण या बहाना बनाकर हमला कर जितनी चाहे जान-माल की हानि कर सकता है? क्या किसी भी कारण से एक देश पर किए गए आक्रमण को न्यायोचित ठहराया जा सकता है और क्या विश्व समुदाय द्वारा बनाए गए कानून व संस्थाएं आक्रमण रोकने में असहाय हैं? इसमें कोई संदेह नहीं कि देशों के अपने राजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक व आर्थिक हित होते हैं। परंतु उन हितों को साधने के लिए किसी संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र पर आक्रमण कर उसे तबाह करना, उसकी भूमि और संसाधनों पर कब्जा करना, निर्दोष जनता को मारना और उन्हें अपना घर व देश छोड़ने पर मजबूर करना कितना न्यायोचित है? दुर्भाग्य है कि यूक्रेन के आम व्यक्तियों को देश की रक्षा के लिए हथियार उठाना पड़ रहा है व विदेश में रह रहे लोग देश के लिए लड़ने के लिए वापस आ रहे हैं।

युद्ध में मारे गए व घायल लोग, उनके बिलखते परिजन व रोते बच्चों की दुर्दशा देखकर हृदय को असहनीय पीड़ा होती है कि किस प्रकार एक देश द्वारा अपने हितों को साधने के लिए एक खुशहाल देश को बर्बादी की राह पर ला दिया गया। रूस ने यह हमला करके अंतरराष्ट्रीय बल निषेध, मानव अधिकार व आपराधिक कानूनों का घोर उल्लंघन किया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर देशों की समानता, संप्रभुता, राजनीतिक स्वतंत्रता व क्षेत्रीय अखंडता पर आधारित है और देशों को एक-दूसरे के विरुद्ध किसी भी प्रकार का बल प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाता है। चार्टर के अनुसार बल का प्रयोग केवल आत्मरक्षा में देश में वास्तविक सशस्त्र हमला होने की स्थिति में सुरक्षा परिषद द्वारा मामले का संज्ञान लेने तक किया जा सकता है। बिना किसी उत्प्रेरक के आक्रमण कर रूस ने न केवल बल निषेध कानून, बल्कि आम नागरिकों पर हमला कर वैश्विक मानवीय व आपराधिक कानूनों का भी उल्लंघन किया है। रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए आक्रमण ने न केवल यूक्रेन में भीषण मानवीय त्रासदी को जन्म दिया है, अपितु वैश्विक शांति व सुरक्षा के समक्ष भी गंभीर खतरा पैदा किया है। इस प्रकार की घटनाएं निसंदेह अंतरराष्ट्रीय कानून व संस्थाओं की प्रासंगिकता व विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि इस संघर्ष से अंतरराष्ट्रीय कानून व संस्थाएं प्रभावहीन या समाप्त हो गई हैं। अंतरराष्ट्रीय पटल पर कानून व व्यवस्था केवल एक पहलू है। इसके अतिरिक्त असंख्य ऐसे पहलू हैं जहां अंतरराष्ट्रीय कानून व संस्थाएं निरंतर सफलता से कार्यरत हैं और विश्व शांति व विकास में उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता।

● **कुमार विनोद**

देशों की आंतरिक शांति

द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत ही यह अहसास हो गया था कि जब तक देशों में आंतरिक शांति नहीं होगी, वैश्विक शांति व सुरक्षा संभव नहीं है। देशों की आंतरिक शांति व वैश्विक शांति का आपस में सीधा संबंध है। देशों की आंतरिक शांति के लिए मानवाधिकारों की रक्षा व देश का सामाजिक व आर्थिक विकास अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र केवल शांति व सुरक्षा पर ही कार्य नहीं करता, अपितु अपनी अनेक विशिष्ट संस्थाओं के माध्यम से पूरे विश्व में स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव अधिकार व आर्थिक प्रगति के लिए लगातार कार्यरत है। अनुभव बताता है कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन अधिक व उल्लंघन कम होता है और अधिकांश देश स्वेच्छा से उनका आदर व अनुपालन करते रहे हैं। अनेक ऐसे कार्य हैं जो दैनिक जीवन में हमारे आसपास होते रहते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि वे अंतरराष्ट्रीय कानून व संस्थाओं की सफलता से कार्यरत होने से ही संभव हो रहे होते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, संपर्क, संचार, उड्डयन, व्यापार, अंतरिक्ष, समुद्र, मानव अधिकार, बौद्धिक संपदा, राजनयिक विशेषाधिकार आदि अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अंतरराष्ट्रीय कानून व संस्थाएं अनवरत सफलता से कार्यरत हैं।

बाधा रहित महिला सशक्तीकरण

वर्षों से महिलाएं अधिकार के लिए संघर्षरत

वर्षों से महिलाएं लैंगिक समानता, स्वतंत्रता और अधिकार के लिए सतत् प्रयास और संघर्ष करती आई हैं। परिणामस्वरूप आज विश्व के लगभग सभी देश विकास प्रक्रिया में आधी आबादी की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए उनकी सहभागिता को सुनिश्चित कर रही है। चाहे वह निर्णय निर्माण प्रक्रिया हो या सैन्य क्षेत्र, मेडिकल, कला, विज्ञान और खेल जगत, ऐसे कई अन्य क्षेत्रों में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। परंतु इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि महिलाएं स्वतंत्र होकर भी स्वतंत्र नहीं हैं और पुरुषों के समकक्ष होकर भी समान नहीं हैं। कहीं न कहीं हमारी सामाजिक संरचना और समाज में लोगों की मानसिकता अभी भी यही बनी हुई है कि महिलाएं अपना निर्णय स्वयं और सही ढंग से नहीं ले सकती हैं। परिवार से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक उनसे संबंधित निर्णय जब तक वे स्वयं नहीं लेंगी, जब तक समाज में लोगों की मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा, तब तक महिला सशक्तीकरण की बात करना निरर्थक होगा। सरकारें अपना कार्य कर रही हैं।

आज हम एक ऐसे वैश्विक परिवेश में रह रहे हैं, जहां विश्व में लगभग सभी देश महिला स्वतंत्रता, समानता और अधिकार जैसी अवधारणाओं की केवल बात ही नहीं करते, बल्कि जमीनी स्तर पर इसे क्रियान्वित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। महिला सशक्तीकरण और महिला शिक्षा जैसी बातों पर विमर्श में बदलाव वैश्विक स्तर पर तो परिलक्षित हो ही रहा है, बल्कि अब महिलाओं के नेतृत्व में विकास जैसी प्रगतिशील बातें भी हो रही हैं। परंतु पहला प्रश्न यह है कि क्या महिला सशक्तीकरण का संबंध केवल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका संबंध देश की आधी आबादी के आत्मनिर्णय, समाज की दकियानूसी रुढ़िवादी प्रथाओं के प्रति जागरूक होना भी है। वास्तव में महिला सशक्तीकरण आधी आबादी की प्रगति, उनमें चेतना का संचार और जागरूकता से संबंधित है।

आज महिलाएं अपने सीमित दायरे से निकलकर अपनी रचनात्मकता और योग्यता के बल पर विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। वहीं वर्तमान में **देश के भीतर हिजाब** पर हो रहा विवाद एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। इंटरनेट मीडिया पर हिजाब पहनी हुई एक छात्रा का सड़क पर लगाया जा रहा एक चर्चित नारे का वीडियो सामने आने के बाद से उसे निडर और बहादुर कहा जा रहा है। इसी क्रम में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा बयानबाजी भी कर दी गई कि महिलाओं को यह अधिकार है वह कुछ भी पहन सकती है और यह उनका व्यक्तिगत मामला है। मुस्लिम समुदाय के कुछ नेता इस मामले में धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता का हवाला दे रहे हैं। इस ज्वलंत मुद्दे के पीछे तथाकथित लोगों के कुछ तत्कालीन कारण या यूं कहें कि अवसर निहित है जो कि देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे चुनाव में समुदाय विशेष का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उनको बरगलाया जा रहा है। राजनीतिक लाभ के कारण कट्टरपंथियों द्वारा हिजाब का मुद्दा खड़ा किया गया है।

विदित हो कि 19वीं शताब्दी में विभिन्न समाज सुधारकों- राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सर सैय्यद अहमद खान आदि ने महिलाओं की दयनीय स्थिति को सुधारने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। यह प्रयास न केवल हिंदू धर्म की महिलाओं, बल्कि मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए भी था। महिला शिक्षा, विधवा विवाह, पारिवारिक संपत्ति में अधिकार, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का विरोध, ऐसे कई मुद्दे जिस पर समाज सुधारकों द्वारा आंदोलन किया गया और बाद में उन्हें सफलता भी मिली।

ये तो रही 19वीं शताब्दी की बात, लेकिन आज तो हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं। स्वाधीनता के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। ऐसे समय में हिजाब पहनने के लिए मुस्लिम छात्रों द्वारा देश के कई क्षेत्रों में आंदोलन करना और कट्टरपंथियों के बहकावे में आकर सड़कों पर उतरना कहां तक सही है? एक महिला संभवत: अपनी इच्छा से पर्दा या हिजाब का चयन तो नहीं करती, बल्कि धर्म की आड़ में बचपन से ही उस पर पर्दा थोपा जाता रहा है तथा उन पर सामाजिक दबाव बनाया जाता है।

बहुत ही रोचक बात यह है कि विश्व के कई मुस्लिम बाहुल्य (लगभग 80-90 प्रतिशत) देश में सार्वजनिक स्थल पर हिजाब, बुर्के पर कुछ कारणों- जिनमें आधुनिकीकरण, धर्मनिरपेक्षता और कई देशों ने सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन अपने देश के बारे में बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। ऐसे में एक ऐसा लोकतांत्रिक देश जो सर्व समावेशी समाज पर बल देता है, महिला सशक्तीकरण की बात ही नहीं, बल्कि यहां महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर बल दिया जा रहा है। आज हिजाब पहनने को लेकर आंदोलन किया जा रहा है जो बेहद दुर्भाग्य की बात है। इस विवाद ने महिला सशक्तीकरण को हास्यास्पद बना दिया है। जो महिलाएं बिना हिजाब के कार्यस्थल पर जाती हैं, उनके चरित्र पर न केवल सवालिया निशान खड़ा करता है, बल्कि भेदभाव को भी बल प्रदान करता है।

गौरतलब है कि यह केवल हिजाब विवाद का ही मुद्दा नहीं है। समाज में महिलाओं की स्थिति, समान अधिकार, स्वतंत्रता, स्वयं का निर्णय, स्व-चेतना का मुद्दा है। महिला होने के नाते यह समय है स्वयं की स्थिति पर पुन: विचार करने का, ऐसी सभी प्रथाओं और कुरीतियों का विरोध करने का, जो उनको अधीनता की तरफ ले जाए। धार्मिक कट्टरपंथियों को आईना दिखने का जो महिलाओं को एक वस्तु समझने की भूल करते हैं। समय है स्वयं के अस्तित्व पर विचार करने का कि क्या हम महिलाएं सही मायने में स्वतंत्र हैं? वह किसी भी धर्म समुदाय की हो, क्या महिलाएं स्वतंत्रता के मूलभूत सार को समझ रही हैं, उसका उपभोग कर पा रही हैं?

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

रामचरितमानस में पर्यावरणीय संपन्नता

रामचरितमानस में पर्यावरणीय संपन्नता के कतिपय संक्षिप्त संकेतों का अवलोकन करें तो श्रद्धेय गोस्वामी तुलसीदास जी का वृक्षारोपण को एक स्वाभाविक कार्य मानने एवं मानस में वर्णित प्रकृति में उपलब्ध औषधीय तत्वों का प्रतीकात्मक रूप तथा जैविक विविधता एवं मानस में वैयक्तिक वृत्ति और पर्यावरण का समन्व्य आदि बिंदु गोस्वामीजी की विलक्षण प्रतिभा को उजागर करते हैं। इन्हीं बिंदुओं की गहराई प्रकृति पर्यावरण और प्रगति की ओर भी संकेत करती है।

रामचरितमानस में पर्यावरण के संदर्भ में वर्णन करते हुए कहा है कि उस समय पर्यावरण प्रदूषण कोई समस्या नहीं थी। पृथ्वी के अधिकांश भू-भाग पर वन-क्षेत्र होता था। शिक्षा के केंद्र आबादी से दूर ऋषि-मुनियों के वनों में स्थित आश्रम हुआ करते थे। श्रीरामचंद्रजी ने भी अपने भाईयों सहित महर्षि विश्वामित्रजी से उनके आश्रम में ही शिक्षा ग्रहण की थी। समाज में ऋषि-मुनियों का बड़ा सम्मान था। प्रतापी राजा-महाराजा भी इन ऋषि-मुनियों के सम्मुख नतमस्तक होने में अपना सौभाग्य समझते थे। यही करण है कि जब श्रीराम को बनवास हुआ तो उन्हें सर्वाधिक प्रसन्नता इसी बात की हुई थी कि उन्हें वन-क्षेत्र में ऋषि-मुनियों के सत्संग का लाभ प्राप्त होगा-

मुनिगन मिलन विशेष वन,
सबहिं भांति हित मोर।

श्रीराम को भविष्य में रामराज्य की स्थापना करनी थी जिसमें मानव-जीवन को सुखमय बनाने हेतु मानव-प्रकृति, जीव-वनस्पति, सभी में सामंजस्य पर आधारित समवेती विकास संभव हो सके। रामचरितमानस में हम पाते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक अवयवों को मात्र उपभोग की वस्तु नहीं माना गया है बल्कि सभी जीवों तथा वनस्पतियों से प्रेम का संबंध स्थापित किया गया है। प्रकृति के अवयवों का उपभोग निषिद्व न होकर आवश्यकतानुसार कृतज्ञतापूर्वक उपभोग की संस्कृति प्रतिपादित की गई है जैसे कि वृक्ष से फल तोड़कर खाना तो उचित है लेकिन वृक्ष को काटना अपराध है-

रीझि-खीझी गुरूदेव सिष
सखा सुसाहित साधु।
तोरि खाहु फल होई भलु
तरु काटे अपराधू।।

रामराज्य धरती पर अनायास स्थापित नहीं किया जा सकता है इसके लिए प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण की संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है जैसा कि तुलसीदासजी ने रामचरितमानस में वर्णित किया है कि श्रीरामचंद्र जी के विवाहोपरांत बारात लौटकर अयोध्या आती है तो अयोध्या नगरी में विविध पौधों का रोपण किया जाता है-

सफल पूगफल कदलि रसाला।
रोपे बकुल कदम्ब तमाला।।

पौधा-रोपण की संस्कृति को विकसित करने के लिए श्रीराम ने अपने वन-प्रवास के दिनों में सीताजी व लक्ष्मणजी के साथ विस्तृत पौधारोपण की ओर संकेत करते हुए कहा कि-

तुलसी तरुवर विविध सुहाय।
कहुं कहुं सिएं, कहुं लखन लगाये।।

शुभ अवसर पर पौधा-रोपण की संस्कृति से आज के सबसे भयावह संकट-पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति संभव है। इसीलिए रामराज्य में प्रकृति के उपहार स्वत: प्राप्त थे।

प्रकृति, पर्यावरण, प्रगति के मध्य अंत: संबंध है जिनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण सांस्कृतिक विरासत से निर्मित एवं विकसित होता है और इस संदर्भ में भारतीय हिंदू संस्कृति की वैश्विक भूमिका प्राचीनकाल से ही मानी गई है। पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण संरक्षण हिंदू संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं। वाल्मीकि रचित रामायण से लेकर तुलसीदास रचित श्रीरामचरितमानस में प्रकृति चित्रण पर्यावरण संचेतना, पर्यावरण संरक्षण का विस्तृत उल्लेख किया गया है। वास्तव में हिंदू धर्म एक विशिष्ट पूजा पद्धति, आस्था तक ही सीमित नहीं है वरन जैसा कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी हिंदू धर्म को परिभाषित करते हुए कहा है कि हिंदूधर्म एक जीवन शैली है। हिंदू धर्म की इस जीवन शैली में धर्म तथा पर्यावरण में सह-संबंध माना गया है। जिसके अंतर्गत पर्यावरण प्रकृति के साथ मानव द्वारा उचित, संवेगात्मक एवं सामन्जस्यपूर्ण संबंध निभाना ही उसका धर्म है। पृथ्वी को धरती माता के रूप में पूजित माना गया तथा सूर्य, जल, वायु, वृक्ष, अग्नि सभी को देवता मानकर पूजनीय माना गया केवल यही नहीं विभिन्न देवी-देवताओं के वाहक के रूप में विभिन्न पशु-पक्षियों की भी आराधना की पद्धति विकसित की गई। जल, वायु को दूषित करना, वृक्षों का अनावश्यक रूप से कटाव करने को पाप माना जाता था क्योंकि उस समय ऋषि, मुनियों को पर्यावरण के इन महत्वपूर्ण घटकों के महत्व का ज्ञान था। तत्कालीन भारतीय सामाजिक जीवन में पर्यावरणीय तत्वों के साथ सामंजस्य की भावना धर्म से जुड़ी हुई थी।

लेकिन पाश्चात्य भौतिकवाद की अवधारणा पर आधारित प्रगति के स्वरूप एवं दिशा ने आज इक्कीसवीं शताब्दी में पर्यावरण प्रदूषण के रूप में मानव जाति के अस्तित्व को ही चुनौती प्रस्तुत कर दी है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, ओजोन परत में छिद्र, अम्लीय वर्षा इत्यादि का अत्यंत विनाशकारी स्वरूप बुद्धिजीवी, विवेकशील, वैज्ञानिकों की चिंता का कारण बन चुके है। लंबे समय तक भौतिक विकास के विनाशकारी मद में मदोन्मत्त लोगों की सुप्त पर्यावरण चेतना अब जागृत हो रही है तथा इस भौतिकवादी प्रगति के पुरोधा भी पर्यावरण संरक्षण की बात करने लगे हैं। मानव समाज किस समय कौन सी समस्या से ग्रस्त होता है और उसके निदान के लिए समाज के सदस्यों की भूमिका एवं सहभगिता एवं शासकीय प्रयासों की तुलना में अधिक उस समाज के सांस्कृतिक मूल्य अधिक प्रभावी होते हैं। इस संदर्भ में भारतीय संस्कृति के आधार पुरातन ग्रंथ-वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण के साथ-तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का अध्ययन व विश्लेषण अत्यंत लाभप्रद हो सकता है। विशेषकर रामचरितमानस का क्योंकि वर्तमान समय में घर-घर में न केवल रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ के रूप में पूजा जाता है। वरन इसका पाठ पारिवारिक व सामाजिक स्तर पर किया जाता है।

● **ओम**

आशा की किरण

सीमा प्रतिदिन कॉलेज से आते-जाते एक छोटे बच्चे की पीठ पर बहुत छोटी बच्ची को गले से बंधा देखती। बच्चा पीछे बच्ची का बोझ उठाता और आगे एक टोकरी में पान और पान लगाने का सामान रखकर पान बेचता। सीमा को अपना बचपन याद आ गया। मां-पापा एक हादसे में उसे और उसकी छोटी सी बहन को छोड़कर भगवान के पास चले गए। घर में एक बूढ़ी दादी थी। बेचारी कुछ घरों में काम करके दो समय की रोटी जुटा पाती थी। सीमा भी छोटी बहन को लेकर दादी के साथ काम पर जाने लगी। काम के साथ वह पढ़ाई भी करती रही और ट्यूशन भी पढ़ाती रही। धीरे-धीरे करके वह बीए में आ गई दादी अब भी काम करती। बस एक इच्छा थी कि सीमा कहीं नौकरी कर ले तो वह छोटी बहन को पढ़ा लेगी और वह काम करना छोड़ देंगी। आज उस बच्चे को देखकर वह रुक गई और उसने पूछा- छोटे भाई तुम टूटी चप्पल पहने हो, पीठ पर अपनी बहन को लेकर पान बेचते हो ऐसी क्या मजबूरी है। उसने कहा दीदी मेरा नाम पिंटू है, मेरी मां बीमार है। मां कहती है कि हम दोनों उसके पाप का नतीजा है। हमारे पिताजी कोई बहुत बड़े अमीर आदमी हैं मेरी मां बहुत सुंदर हैं। उस अमीर आदमी ने मां को शादी का वायदा किया था। मां उसकी बातों में आ गई जब तक उसका मतलब निकला मां को रखा उसके बाद हम दोनों को पैदा करके वह चला गया। मां उसे ढूंढकर उसके आलीशान बंगले पर गई। वहां वह अपनी पत्नी के साथ था उसने मेरी मां मुझे और मेरी छोटी बहन को धक्के मारकर निकाल दिया। मां सदमे से अर्द्ध विक्षिप्त हो गई। मैं और कोई काम नहीं कर सकता था पान वाले मामा मुझे सुबह यह पान का सामान दे देते हैं और शाम को अपने सामान के पैसे ले लेते और बाकी बचे पैसे मुझे देते हैं। सीमा उस छोटे बच्चे के स्वर की दृढ़ता देखकर दंग रह गई पर उसकी आवाज का दर्द महसूस करती रही। वह बोली मेरे छोटे भाई कल से शाम को तुम मेरे पास आकर एक घंटा पढ़ाई करोगे। शायद मैं इसी से तुम्हारी मदद कर सकूं। पिंटू की आंखों में एक नई आशा की किरण दिखाई दे रही थी।

- डा. मधु आंधीवाल

श्रम का गीत

श्रम करने वालों के आगे,
गहन तिमिर हारा है।
श्रम करने वालों के कारण,
ही तो उजियारा है।।
खेत और खलिहानों में जो,
राष्ट्रहितों के वाहक हैं
अन्न उगाते, स्वेद बहाते,
जो सच फलदायक हैं
श्रम के आगे सभी पराजित,
श्रम का जयकारा है।
श्रम करने वालों के कारण,
ही तो उजियारा है।।
सड़कों, पांतों, जलयानों को,
जिन ने नित्य संवारा
यंत्रों के आधार बने जो,
हर बाधा को मारा
संघर्षों की आंधी झेले,
साहस नित वारा है।
श्रम करने वालों के कारण,
ही तो उजियारा है।।
ऊंचे भवनों की नींवें जो,
उत्पादन जिनसे है
हर गाड़ी, मोबाइल में जो,
अभिवादन मन से है
स्वेद बहा खुशहाली रचता,
श्रमसीकर प्यारा है।
श्रम करने वालों के कारण,
ही तो उजियारा है।।

- प्रो. (डॉ.) शरद नारायण खरे

सीता सी वामा

सैकड़ों लड़कियां देख चुके पर तुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। लड़की देखकर जवाब नहीं देता और दो दिन बाद मना कर देता है। आखिर तुम्हारी पसंद क्या है राम मनोहर!

राम मनोहर- लड़की देखने के बाद छानबीन करने पर लड़की में वह समर्पित भावना नजर नहीं आती जो मैं चाहता हूं माते।

शकुंतला (आश्चर्य करते)- समर्पित भावना से तुम्हारा क्या आशय है?

राम मनोहर- जैसे प्रभु राम के साथ सीता जी सारे सुख त्यागकर वनवास गई थी, ऐसी समर्पित भावना।

शकुंतला- पहले स्वयं के बारे में विचार करो कि क्या तुम्हारा आचरण भी मर्यादित राम जैसा है? तभी सीता सी समर्पित भावों की वामा की चाहना करना उचित होगा।

इस पर राममनोहर विचारों में खो गया!

- लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाला

अनंत में खो गया कलाई का जादूगर...

52 साल की उम्र अधिक नहीं होती, खासतौर पर यह उम्र अगर लेग स्पिन की कला के उस्ताद शेन वॉर्न की हो, तो कत्तई नहीं। दुनिया के महान स्पिनर में शुमार ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न का निधन हो गया है। लट्टू की तरह गेंद को नचाने वाले कलाई के जादूगर का जादू तिलिस्म अनंत में खो गया है। आप वॉर्न को उनकी जिंदगी के विवादों और बयानों से परे, सिर्फ मैदान में सफेद या रंगीन कपड़ों में लाल या सफेद गेंद फेंकने वाले गेंदबाज की निगाह से देखें तो आपको पता चलेगा, क्रिकेट की दुनिया में हमने क्या खो दिया है। वह शांत देहभाषा के साथ गेंदबाजी करते थे। अंपायर से बस चंद कदम दूर जाकर पॉपिंग क्रीज के कोने के पास अपने रन-अप में वह बस मछली की घात में उसकी तरफ खामोशी से बढ़ते बगूले की जैसे दबे पांव से आते, फिर उनका सिर झुकता, उनके सुनहरी जुल्फें हवा में लहरातीं लेकिन उन जुल्फों के पीछे से चतुर-सुजान आंखें बल्लेबाज की तरफ टंगी होतीं और फिर इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण काम होता। गेंद की सिलाई को दुश्मन की गर्दन की तरह उंगलियों में फंसाए वॉर्न गेंद रिलीज करते और अपनी गेंद को पर्याप्त धीमी रखते और फ्लाइट देते थे।

हवा में उड़ान भरती चिड़िया जैसी गेंद बल्लेबाज की तरफ आती, तो अमूमन बल्लेबाज उसके टप्पे का अंदाजा नहीं लगा पाते। अंदाजा लगा भी लिया तो अधिकतर यह भांपने में चकमा खा जाते कि टप्पा खाकर गेंद किधर निकलेगी, और कितना निकलेगी। यह जादू था। यही वॉर्न की अय्यारी थी। दुनियाभर के गेंदबाज उनकी कलाई के घुमाव से चकित रहते थे और बेशक, खौफ खाते थे। वॉर्न, बेशक क्रिकेट के संगीत, जिसमें विलो की लकड़ी पर चमड़े की गेंद के टकराने से पैदा हुआ ताल शामिल होता है, के संगीतकार थे और वह इसके सुर साधने में सिद्धहस्त थे। गेंद की चमक गई नहीं, गेंद का चमड़ा थोड़ा-सा चमड़ा रुखड़ा हुआ नहीं कि वॉर्न विलंबित ताल पकड़ते थे और फिर, द्रुत और सम पर आते-जाते रहते थे। क्रिकेटरों के लिए वॉर्न कभी आसान नहीं रहे, उनको खेलना कठिन था। पर दर्शक तो दर्शक, विपक्षी बल्लेबाज भी उनकी गेंदबाजी के दीवाने थे।

आखिर, जिस गेंदबाज की घूमती गेंद ने एशेज में इंग्लैंड के घर में माइक गैंटिंग को ऐसे आउट किया, कि गैटिंग खुद चकरा गए थे। गेंद ने लेग स्टंप के बाहर टप्पा खाया और मिट्टी छोड़कर तेजी से निकली और समकोण पर घूमती हुई गैटिंग के ऑफ स्टंप से जा टकराई थी। यही गेंद थी बॉल ऑफ द सेंचुरी, यानी सदी की बॉल। क्रिकेट प्रशंसकों के लिए उम्रभर याद रखने वाली गेंद रही है यह। शेन वॉर्न ने अपने कैरियर के दौरान 145 टेस्ट मैच में 708 विकेट उड़ाए थे, जबकि 194 वनडे मैचों में 293 विकेट उनके खाते में दर्ज हैं। वैसे एक बात बता दें, गेंदबाजी के साथ उन्होंने बल्लेबाजी में भी जौहर दिखाए, पर शतक नहीं लगाया कभी। वॉर्न ने टेस्ट क्रिकेट में 3154 रन भी बनाए, जो बिना शतक के किसी भी बल्लेबाज के सबसे ज्यादा रन का विश्व रिकॉर्ड है। वॉर्न ने टेस्ट क्रिकेट में 12 पचासे ठोंके, लेकिन उनका उच्चतम स्कोर 99 रन रह गया, जो उन्होंने 2001 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पर्थ टेस्ट में बनाया था।

इसके अलावा भी वॉर्न एक बार और शतक के करीब पहुंचकर चूक गए थे। वनडे में भी उन्होंने 1018 रन बनाए। वे दुनिया के उन चुनिंदा क्रिकेटर्स में शामिल हैं, जिनके नाम पर टेस्ट और वनडे, दोनों में बल्ले से 1000+ रन और गेंद से 200+ विकेट दर्ज हैं। बहरहाल, वॉर्न से जुड़ा एक दिलचस्प प्रसंग है। प्रसंग तो कई हैं और इनमें से एक शारजाह में भारतीय क्रिकेट के सम्राट सचिन तेंडुलकर और फिरकी मास्टर वॉर्न के बीच ताबड़तोड़ कुटाई के किस्से का जिक्र तो हजारों बार हो चुका है।

ऐसा ही एक मौका था, जिसका जिक्र वॉर्न ने अपनी आत्मकथा में किया है। एक बार बल्लेबाजी के छोर पर तेंडुलकर थे और दूसरे छोर पर सौरभ गांगुली थे। गांगुली की तुनकमिजाजी को वॉर्न अच्छे से जानते थे। तेंडुलकर ने वॉर्न की गेंद पर चौका या संभवतया छक्का जड़ा तो वॉर्न भारत के क्रिकेट शहंशाह की तरफ न जाकर, 'प्रिंस ऑफ कैलकूटा' यानी गांगुली की तरफ आए और बोले, देखो, लोग तुम्हें नहीं तेंडुलकर को देखने आते हैं क्योंकि वह छक्के मारता है। अगले ओवर में वॉर्न और गांगुली आमने-सामने थे। शायद, वॉर्न की चुटीली स्लेजिंग का असर गांगुली पर हो गया था क्योंकि गांगुली ने वॉर्न को आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन पर छक्का मारने की कोशिश की और स्टंप्ड हो गए। अपनी निजी जिंदगी में वॉर्न बेशक बैड बॉय रहे और उनकी मौत पर भी उनकी गेंदों की तरह की फिरकी यानी रहस्य के बादल हैं। सुबह विकेट कीपर मार्श के निधन और शाम में वॉर्न की मौत से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में सनाका खिंच गया है क्योंकि अपने उत्थान के दिनों में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के अजेय रथ के सात घोड़ों में से एक घोड़े शेन वॉर्न ही थे।

● **आशीष नेमा**

पाक्षिक पत्रिका अक्स के स्वामित्व एवं अन्य विषयों संबंधित विवरण

घोषणा

फार्म 4 (नियम 8 देखिए)

प्रकाशन	:	भोपाल
प्रकाशन अवधि	:	पाक्षिक
मुद्रक का नाम	:	राजेन्द्र आगाल
नागरिकता	:	भारतीय
पता	:	150 जोन-1, प्रथम तल मनोरमा काम्पलेक्स महाराणा प्रताप नगर भोपाल
प्रकाशक का नाम	:	राजेन्द्र आगाल
नागरिकता	:	भारतीय
पता	:	150 जोन-1, प्रथम तल मनोरमा काम्पलेक्स महाराणा प्रताप नगर भोपाल
संपादक का नाम	:	राजेन्द्र आगाल
नागरिकता	:	भारतीय
पता	:	150 जोन-1, प्रथम तल मनोरमा काम्पलेक्स महाराणा प्रताप नगर भोपाल
उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा	:	राजेन्द्र आगाल 150 जोन-1, प्रथम तल मनोरमा काम्पलेक्स महाराणा प्रताप नगर भोपाल

जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।

मैं राजेन्द्र आगाल एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकृत जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

दिनांक : 01.03.2022

राजेन्द्र आगाल
हस्ताक्षर

अनुपम खेर ने जब घर से चुराए पैसे

बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर फिल्म उद्योग में एक जाना-माना नाम हैं और उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स के दम पर इन सालों में अपने लाखों फैन बना लिए हैं। अभिनेता को ज्यादातर आज की पीढ़ी के अभिनेताओं के साथ पिता की भूमिका निभाते हुए देखा जाता है। सोशल मीडिया पर भी अनुपम खेर काफी एक्टिव रहते हैं और उन्हें अक्सर अपने वीडियो शेयर करते देखा जाता है। उन्होंने खुद से जुड़ी एक कहानी अपने फैंस के साथ शेयर की थी।

दरअसल, उन्होंने कॉलेज के दिनों में अपनी मां के पास से 118 रुपए चोरी कर लिए थे। उन दिनों वह पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। एक पुराने इंटरव्यू में अनुपम खेर ने खुलासा किया था कि उनके पास अपने पैरेंट्स को ऑडिशन के लिए पैसे मांगने की हिम्मत नहीं थी। ऐसे में उन्होंने अपनी मां के पास से पैसे चोरी कर लिए। इस ऐड में चयनित छात्रों के लिए 200 रुपए की छात्रवृत्ति का दावा किया गया था।

हालांकि, किसी तरह उनकी मां को उनकी इस हरकत के बारे में पता चल गया, जिसके बाद उन्होंने अनुपम खेर को जोरदार थप्पड़ मारा और यही नहीं इस मामले में पुलिस को भी शामिल कर लिया। अनुपम खेर ने शिमला से अपनी स्कूलिंग कम्प्लीट की है, लेकिन, थिएटर के लिए चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर दी। जिसके बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। अनुपम खेर ने महेश भट्ट की सारांश के साथ बॉलीवुड में कदम रखा था।

माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहती थीं माधुरी दीक्षित

बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की गिनती उन सितारों में की जाती है, जिनके फैंस भारत के साथ ही विदेशों तक में हैं। माधुरी दीक्षित ने मात्र 3 वर्ष की उम्र से कथक सीखना शुरू कर दिया था। हाल ही में उन्होंने नेटफ्लिक्स की वेबसीरीज 'द फेम गेम' से वेबसीरीज की दुनिया में डेब्यू किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, माधुरी दीक्षित बचपन से एक्ट्रेस नहीं, बल्कि कुछ और बनना चाहती थीं। उस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने के लिए वे पढ़ाई-लिखाई में काफी दिलचस्पी रखती थीं। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने अपनी शुरुआती पढ़ाई डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से पूरी की थी। उसके बाद उन्होंने सथाए कॉलेज, मुंबई में एडमिशन लिया था। वहां बीएससी के दौरान उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी को भी अपना एक विषय रखा था। दरअसल, वे माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहती थीं। हालांकि, कोर्स शुरू होने के 6 महीने बाद ही उन्होंने पढ़ाई छोड़कर फिल्मी दुनिया में कैरियर बनाने का फैसला कर लिया था।

कथक ने बदली दुनिया... माधुरी दीक्षित ने 3 साल की उम्र से डांस करना शुरू कर दिया था। उन्होंने 8 सालों तक कथक की पूरी ट्रेनिंग हासिल की थी। वे एक प्रशिक्षित कथक डांसर हैं। स्कूल के दिनों में भी माधुरी पढ़ाई-लिखाई के साथ ही एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी काफी दिलचस्पी लिया करती थीं। 7-8 साल की उम्र में एक पब्लिक परफॉर्मेंस के दौरान उनकी काफी तारीफ की गई थी, जिससे डांस को लेकर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया था।

सौरभ शुक्ला कभी कोर्ट नहीं गए लेकिन जॉली एलएलबी में काम कर जीता अवॉर्ड

सौरभ शुक्ला उप्र के शहर गोरखपुर में पैदा हुए थे। सौरभ सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर हैं। 'सत्या', जॉली एलएलबी, पीके जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय का परिचय देने वाले सौरभ को 'सत्या' में काम करने के बाद कल्लू मामा के नाम से मशहूर हो गए।

'जॉली एलएलबी' फिल्म में जस्टिस सुंदरलाल त्रिपाठी के रोल में बेहद पसंद किए गए। एक इंटरव्यू में अभिनेता सौरभ शुक्ला ने बताया था कि जज के रोल में उन्हें खूब तारीफ मिली लेकिन मजे की बात है असल जिंदगी में वे कभी कोर्ट नहीं गए। वे कहते हैं कि इस रोल को अगर मैं निभा पाया तो इसके पीछे फिल्म के डायरेक्टर सुभाष कपूर थे। उन्होंने ही सारी कहानियां सुनाई थी जिनके आधार पर मैं अपने किरदार के साथ न्याय कर पाया।

कल्लू मामा के नाम से फेमस हैं सौरभ शुक्ला

'सत्या' फिल्म में कल्लू मामा के किरदार में दर्शकों ने सौरभ शुक्ला को इतना पसंद किया कि इसी नाम से मशहूर हो गए। नाम तो मिला लेकिन काम के मामले में सौरभ को 'सत्या' की सफलता का कोई खास फायदा नहीं मिला। काफी मुश्किल भरा समय भी काटा, लेकिन इन्हें जब 'जॉली एलएलबी' में काम मिला तो कई अच्छी फिल्में इनकी झोली में आ गिरीं।

अर्थ से अर्थी तक

धर्म भी बिना अर्थ के नहीं हो पाता। इष्ट देव की फूलमाला, प्रसाद, मंदिर का निर्माण, पूजा, हवन सामग्री, आरती, दक्षिणा आदि में अर्थ की महती भूमिका है। इनमें कोई भी वस्तु या कर्म अर्थ बिना निरर्थक ही है। धर्म के लिए अर्थ की वैसाखी अनिवार्य है। कहना यही चाहिए कि बिना अर्थ के धर्म एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता।

पृथ्वी लोक में मानव के चार पुरुषार्थों के अंतर्गत धर्म के बाद 'अर्थ का' दूसरा स्थान है। धर्म किसी के वश का हो या न हो, किंतु अर्थ सबके वश में है अथवा यों कहिए कि सभी को अर्थ ने अपने वश में किया हुआ है।

एक नन्हें मानव-शिशु को यदि कागज का एक टुकड़ा दें तो यह आवश्यक नहीं है कि वह उसको ले। वह ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। इसके विपरीत यदि उसे कोई नोट दिया जाए, तो वह तुरंत मुट्ठी में भींच लेता है और सहज ही आपको पुन: वापस भी नहीं करता। यही तो अर्थ की क्षमता है। यही अर्थ की महती शक्ति है।

इस धरती पर क्या नर और क्या नारी, क्या धनवंत और क्या भिखारी, क्या राजा और क्या रंक; सबके लिए है अर्थ का मधु दंश। भले ही यह दंश बनकर धारक को डस ले अथवा उसकी आवश्यक आवश्यकता बनकर उसका जीवन बन जाए! कुछ भी कर सकता है। अर्थ एक ऐसी चादर है, जो काले को गोरा बना दे। काली लड़की को स्वर्ग की अप्सरा का सम्मान दे दे। गोबर पर गिरे तो उसे कलाकंद बना डाले। अर्थ सारे दोषों को ढंककर किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु को कंचन सदृश चमक प्रदान करने की क्षमता रखता है।

अर्थ की महिमा सारा संसार गाता है। उससे लाभ उठाता है। किसी सिनेमाई गीत की पंक्ति 'बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया...' इसी बात की पुष्टि करती है। लोगों को यह भी कहते हुए देखा जाता है कि 'बाप-बेटे का भी हिसाब होता है। मानवीय संबंधों को अच्छा या बुरा बनाने में अर्थ की अहम भूमिका है। यदि बाप अपने दो-चार बेटों में जिसे अर्थवंत बनाए रखे उसके लिए उनका बाप बहुत अच्छा है, अन्यथा केवल अर्थ के लिए कलयुग के अनेक सपूत कपूत बन गए हैं। नाराज पुत्रों द्वारा खेत, घर, संपति आदि का उनकी इच्छानुसार यदि आवंटन नहीं हुआ, तो पल भर में ही सारे आदर्शों को खूंटी पर टांगकर बाप को स्वर्ग लोक की यात्रा कराने में देरी नहीं करते। यदि आई हुई पुत्रवधू को ससुरजी से अर्थ नहीं मिलता तो उनके लिए उन्हें रोटी तक देना निरथर्क मान अघोषित, कभी-कभी घोषित करके बहिष्कृत भी कर दिया गया है।

धर्म भी बिना अर्थ के नहीं हो पाता। इष्ट देव की फूलमाला, प्रसाद, मंदिर का निर्माण, पूजा, हवन सामग्री, आरती, दक्षिणा आदि में अर्थ की महती भूमिका है। इनमें कोई भी वस्तु या कर्म अर्थ बिना निरर्थक ही है। धर्म के लिए अर्थ की वैसाखी अनिवार्य है। कहना यही चाहिए कि बिना अर्थ के धर्म एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता।

तीसरे पुरुषार्थ 'काम' के लिए भी अर्थ एक मजबूत सहारा है। कामनाओं की पूर्ति घर को चलाना, विवाह, शादी, रसोई, वस्त्र, गृह निर्माण सबमें अर्थ एक जीवंत तत्व है। जीजाजी जब तक अर्थ से सालियों को प्रसन्न नहीं कर लेते तब तक जीजी के घर में उनका प्रवेश नहीं हो पाता। इसलिए वे उनके जूते चुराकर अन्यत्र छिपा देती हैं। जब उनका पर्स अर्थवान हो जाता है, तभी उन्हें मार्ग दिया जाता है। यहां भी पूरी ब्लैकमेलिंग चलती है; वह भी अर्थ से।

बस एक ही पुरुषार्थ 'मोक्ष' के लिए अर्थ आवश्यक नहीं है। 'स्वार्थ' में भी अर्थ पूरी तरह रमा हुआ है। यदि स्वार्थ से अर्थ निकाल दिया जाए तो बचता भी क्या है, जो बिना इसके निरर्थ ही है। अब देखिए इस 'निरर्थ' में तो वह जबरन घुसा हुआ है। जब 'परमार्थ' की बात करते हैं, तो वह भी अर्थ से अछूता नहीं है। खेती, व्यवसाय, नौकरी, सेवा, पुण्य, पाप; कोई भी हो; मैं अथवा आप, सब में अर्थ रमण कर रहा है। अरे! उसने 'व्यर्थ' को भी वृथा नहीं रहने दिया! कोई 'समर्थ' होगा तो क्या वहां अर्थ नहीं होगा? अवश्य होगा।

दहेज के भूखे भेड़ियों ने तो अर्थ से मानवीय जगत को नरक बनाकर रख दिया है। जहां अर्थ की अतिशयता है, वहां मानव और मानवता का कोई मूल्य नहीं है। 'दुल्हन ही दहेज है,' का नारा झूठा सिद्ध हो चुका है। बिना 'दहेज-अर्थ' (जो नोट, सोना, चांदी, गहने, वस्तु, सामग्री के रूप में भी है) के दूल्हा या दूल्हे का बाप, कोई भी संतुष्ट नहीं होता। ससुराल में भी बहू दर्शन से पूर्व सास, ननदों और पड़ोसियों द्वारा दहेज-दर्शन का चलन है। बहू के मुखारविंद का प्रथम दर्शन; चाहे सास करे, पड़ोसी करें, संबंधी करें, अथवा सुहाग सेज पर स्वयं दूल्हा ही क्यों न करें, अर्थ की रिश्वत तो देनी ही पड़ती है। अर्थ में वह चमत्कारिक शक्ति है, जो काली दुल्हन को भी मेनका और रंभा बना देती है। इतनी शक्ति तो 'गोरी बनाव केंद्रों' के रसायनों में भी नहीं है।

संसार में होने वाली अनेक लड़ाइयां भी जर, जोरू और जमीन के लिए होती चली आ रहीं हैं। वह लड़ाई चाहे राजा से राजा की हो, देश से देश की हो, बाप से बेटे की हो, पति से पत्नी की हो, वेतन भोगी, व्यवसायी, कारीगर, कर्मचारी; किसी से किसी की हो, वहां सर्वत्र ही अर्थ तत्व ही मूल कारक है। यहां तक कि मनुष्य के शरीरांतरण के बाद अर्थी भी अर्थ से ही सार्थक होती चली आई है। शवाच्छादन, घृत, पुष्प, धूप, चंदन, काष्ठ सभी में अर्थ ही अर्थ है। जीवन विरक्त साधु संतों की उदर पूर्ति क्या बिना अर्थ के कभी हुई है। जन्म से मृत्यु पर्यंत एकमात्र अर्थ ही प्राण है। अर्थ ही त्राण है। अर्थ के लिए तो मानव ने देवी लक्ष्मी को यह पवित्र अधिकार दिया ही हुआ है, कि वे हमारे घर पर अर्थ वर्षा करती रहें। ज्ञान-देवी हों चाहे नहीं हो, पर अर्थ की देवी अवश्य ही हों। उनके जाने वे उल्लू पर बैठकर आवें या कैसे भी आवें, पर आनी चाहिए। इसके लिए वर्ष में अर्थ वर्षा के लिए दीपावली का एक विशेष पर्व भी मनाया जाता है। लक्ष्मी काली हों या गोरी, पर आनी ही चाहिए। साधन कैसा भी हो, पर आनी लक्ष्मी (अर्थ) ही चाहिए। इसलिए चोर, डाकू, जेबकट, राहजनी कर्ता, गबनी, बेईमान, ईमानदार, धर्मी, अधर्मी; किसान, मजदूर, अपनी-अपनी अर्थ-देवी की पूजा करते हैं। मिले, चाहे छप्पर फाड़ कर दे, चाहे आंगन में बिना पसीना बहाए दे। काम से दे, या हराम से दे। पर दे।

● **डॉ. भगवत स्वरूप 'शुभम'**

HEIDELBERGCEMENT

149 वर्षों का अतुलनीय अनुभव

माईसेम सीमेन्ट की सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता, मज़बूती और टिकाऊपन के पीछे उसके विश्व प्रख्यात उत्पादनकर्ता जर्मन कंपनी हाइडलबर्ग सीमेन्ट का 149 वर्षों का अतुलनीय अनुभव है जो 50 देशों में लगातार सुनिश्चित करता आया है कि उसके द्वारा उत्पादित सीमेन्ट का हर कण गुणवत्ता के मापदंड पर खरा उतरे ताकि उनका नारा "सर्वोत्तम निर्माण के लिए" उसके ग्राहकों का विश्वास पात्र बना रहे।

क्योंकि जब सीमेन्ट की गुणवत्ता का सवाल हो,
तो सीमेन्ट का हर कण मायने रखता है..

माईसेम सीमेन्ट | सर्वोत्तम निर्माण के लिए

सस्ता सीमेन्ट या बढ़िया सीमेन्ट - फैसला आपका

For all licenses and BIS standards please refer to www.bis.gov.in
HeidelbergCement India Limited CIN: L26942HR1958FLC042301 Phone +91-124-4503700 e-mail - assistance@mycem.in

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

17/1, Sector-1 Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) India-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687